



# मेरे कामकाजी जीवन के संस्मरण

एम० विश्वेश्वरैया



मेननग बुक ट्रस्ट, इंदिया  
नई दिल्ली

आश्विन १८८९ (सितंबर १९६७)

मूल्य : ५.००

## भूमिका-

इस पुस्तक में मेरा प्रमुख उद्देश्य है अपने कामकाजी जीवन का साक्षेप और प्रामाणिक परिचय देना। संभव है कि पाठको को अन्त में जोड़े गये तीन अध्याय इस प्रकार की पुस्तक के लिए कुछ असंगत से लगें, क्योंकि वे जिन समस्याओं को लेकर लिखे गये हैं उनका इस पुस्तक से प्रत्यक्षत कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना होगा कि मैंने अपने अनुभवों से जो कुछ भीना है उसे देश के राष्ट्रीय जीवन पर लागू करने का मेरा यह पहला प्रयास है, चाहे यह (प्रयास) कितना ही सक्षिप्त और दोषपूर्ण क्यों न हो।

पिछले कुछ वर्षों में असाधारण ही नहीं कुछ नातिकारी परिवर्तन हुए हैं, और आगे भी होते रहेंगे। भारत का विभाजन कर दिया गया और उसके प्रधान भागीदार, भारत ने एक लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।

कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठा और जीवन-स्तर की दृष्टि से आज के भारत और प्रगतिशील देशों में, जिनमें अमरीका का उदाहरण सब से प्रत्यक्ष है, बहुत अन्तर है।

भारत की जनसंख्या, मेरे ही जीवनकाल में, दुगुनी हो गयी। देश के कृषि-प्रधान होने के बावजूद, इतनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त भ्रष्ट का उत्पादन नहीं हो पाता। देश में काम करने की सुस्त गति बिनाजनक है। यदि स्वतन्त्रता का कुछ अच्छा परिणाम होता है तो लोगों की शिक्षा, आदतों, कार्यक्षमता और सत्कार के बारे में उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए जल्दी ही प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें अधिक काम करना है और अधिक उत्पादन करना है। सरकार की आर्थिक नीति में भी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे जीवित रहने के लिए संघर्ष कम कठिन हो, और भविष्य अधिक उज्ज्वल हो।

भारत के लिए यह संभव नहीं है कि वह आगे न बढ़े और एक गतिहीन और योजनारहित देश बना रहे। यदि उत्तरी अफिरका जनता संगार के मामलों, आधुनिकताम आधारितिक विद्वान्तों और रचनात्मक विचारों के बारे में व्याव-

हारिक ज्ञान हासिल नहीं करेगी और सृजनात्मक शक्ति से अनुप्राणित नहीं होगी तो उसका भविष्य सतरे में पड़ जाएगा।

मैं उन चारों मित्रों का भी कृणो हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का पढ़ा और उसके सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव दिये।

—एम० विश्वेश्वरैया

## विषय-सूची

### अध्याय

### पृष्ठ संख्या

१. सरकारी सेवा में प्रवेश	९
२. सिचाई इंजीनियरिंग, जल-वितरण तथा जल-निकास	१७
३. बम्बई राज्य में किये गये कार्य	२६
४. बम्बई राज्य में काम	३३
५. हैदराबाद (दक्षिण) में विशेष सलाहकार— इंजीनियर के पद पर	४१
६. मैसूर में चीफ इंजीनियर के पद पर	४९
७. मैसूर में दीवान के पद पर नियुक्ति	६०
८. मुधारवादी प्रयास	६८
९. शिक्षा-प्रसार तथा मैसूर विश्वविद्यालय	७६
१०. मैसूर में लोक-मुधार के कार्य	८४
११. बाद की परिस्थितिया और नौकरी में ऐच्छिक अवकाश-ग्रहण	९४
१२. अवकाश-प्राप्त करने के बाद मैसूर में किये गये कार्य	१०१
१३. सलाहकार इंजीनियर के रूप में किये गये कार्य	१०९
१४. सरकारी तथा सार्वजनिक समितियों में	११७
१५. राजनीतिक तथा अन्य सम्मेलन	१२५
१६. विदेश-यात्रा	१३१
१७. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता	१४१
१८. राष्ट्रीय चरित्र	१५०
१९. राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय कार्यकुशलता	१५७









## सरकारी सेवा में प्रवेश

तेईस वर्ष की आयु में पूना कॉलेज ऑफ साइंस से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के पश्चात्, फरवरी सन् १८८४ में मुझे बम्बई प्रान्तीय सरकार के लॉक-निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर की जगह मिल गयी। उन दिनों इस विभाग में हर माल एक स्थान बम्बई विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग परीक्षा में सर्व-प्रथम आनेवाले विद्यार्थी के लिए सुरक्षित रखा जाता था। नवम्बर, १८८३ में मैंने इंजीनियरिंग की उपाधि ली और मार्च, १८८४ में सरकारी नौकरी पर लग गया।

पहले-बहुल मेरी नियुक्ति नासिक जिले में की गयी। पहली बार कार्यभार संभालने के लिए नासिक गया तो मेरे कुछ पूना-निवासी मित्रों ने मेरी बड़ी सहायता की। पूना के तत्कालीन विख्यात नेता श्री महादेव गोविन्द रानडे ने मुझे नासिक के डिप्टी कलक्टर के नाम एक परिचय-पत्र दिया और मेरे कुछ अन्य हितैषी मित्रों ने नासिक के मामलेदार को मेरा हर तरह से ध्यान रखने के लिए लिख दिया।

मुझे नासिक में अपना पद ग्रहण किये अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपना विचार बदल कर मेरी बदली खानदेश जिले में कर दी, जिसका सदर मुकाम धुलिया नामक नगर में था। वहां मुझे एक उच्च सहायक इंजीनियर श्री डब्ल्यू० एल० स्ट्रेंज के साथ कुछ दिन काम करने के बाद उनका स्थान ग्रहण करने का आदेश मिला और श्री स्ट्रेंज ने, मुझे नये पद के नैतिक दायित्वों से भली-भांति अवगत करा कर, मुझे कार्यभार संभालने के योग्य बना दिया। कुछ हफ्ते मेरे साथ काम करने के बाद श्री स्ट्रेंज का तत्कालीन नासिक को हो गया। उनके चले जाने के पश्चात् कुछ महीनों तक मैं उस छोटे-से कार्यालय का काम चलाता रहा। मेरा काम अपने इलाके के सिचाई-मार्गों का दौरा करना तथा छोटे-छोटे ऐनिकट और नाले-नालियों की मरम्मत की देखरेख करना था। इसके अतिरिक्त यह काम भी मेरे जिम्मे था कि जब कभी जिला अध्यक्ष का आदेश हो, मैं पांजरा नदी के दोनों किनारों पर सिचाई-मार्गों के निर्माण और  
में लगे हुए अधीनस्थ अधिकारियों के काम का निरीक्षण करूं।

कुछ महीनों तक इसी प्रकार के सामान्य कार्य करने के पश्चात् गान्धेजी नागिक जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (मिन्चार्ड) ने मुझे एक पाटप साइकल निर्माण करने का आदेश दिया। यह पाटप साइकल उस मिन्चार्ड मार्ग के आर-पार बनाया जाना था, जिसके द्वारा पांजरा नदी का जल धुलिया में लगभग ३५ मील दूर पश्चिम की ओर स्थित दाताग्वी नामक ग्राम तक जाता था। एक सहायक नदी मिन्चार्ड-मार्गों के हैड वर्म तथा दाताग्वी ग्राम के मध्य में पांजरा नदी में मिलती थी। इसी गांव के लिए मिन्चार्ड के पानी की व्यवस्था की जानी थी और यह पाटप साइकल उसी सहायक नदी के आर-पार ले जाया जाना था। यद्यपि, संभवतः अंग्रेजी प्रजासन में भी पूर्ण, जल-मार्गों को इस प्रकार नदी के आर-पार ले जाने के लिए एक पानी सेनुवारी बनी हुई थी। यह सेनुवारी वास्तव में प्रयोग में वह पानी और अन्य उसी जगह एक पाटप लगाने की तकनीक थी। इस साइकल के लिए आवश्यक पाटप की मांग थी स्ट्रेज भेज चुके थे। जिले के विभागीय अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थानीय मध्य-स्थितिजन्य अधिकार ने इस निर्माण-कार्य का भार भार मुझे सौंप दिया। मई १८९९ में वर्षा ऋतु आरम्भ होने में कुछ घंटे

दिमाई देगा, मैं धुलिया से वहाँ वापस चल जाऊँगा। इसका जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ, वह मेरी आशाओं के बिल्कुल विपरीत था। एक सरकारी ज्ञापन (मेमोरैण्डम) द्वारा मुझे यह आदेश दिया गया कि काम कदापि बन्द न किया जाए। अन्त में टिप्पणी थी : 'अदेशों के प्रति उत्साह और उनके परिपालन की दृष्टि से सहायक इजीनियर अपनी जीवन-वृत्ति का श्रीगणेश बड़े भड़े ढंग में कर रहे हैं।'

यह पढ़ कर मैं बहुत हतोत्साह हुआ। इस मामले पर कुछ सोच-विचार करने के पश्चात् मैंने कार्यकारी इजीनियर को लिखा कि आप के आदेशानुसार मैं काम को जारी रखूँगा और, यदि कोई अदृष्ट बठिनाई न आ खड़ी हुई तो, इसे पूरा कर के ही धुलिया लौटूँगा। मैंने बताया कि जहाँ तक सम्भव हो सके, मैं स्वयं में पूरी-पूरी किकायत करने का प्रयास करूँगा, किन्तु इतना करने पर भी अनुमानित ध्येय से अधिक खर्चा हो गया तो आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। कुछ ही महीनों में स्थानीय राज-मजदूरों और भील कारीगरों की गहायता से मैं खट्टानें काट कर पाइप लगाने का कार्य पूरा करने में सफल हो गया।

साइकल तैयार हो गया और गिचाई-मार्ग का पानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगातार बहने लगा।

जब यह कार्य चल रहा था, तब मैं प्रतिदिन घोंड़े पर बैठ कर पांजरा नदी पार करके मौके पर जाया करता था। एक दिन सुबह नियत समय पर मेरे नदी पार कर लेने के बाद नदी में भारी बाढ़ आ गयी। बाढ़ का पानी तीन-चार रोड तक बढ़ा रहा और मैं घाबरा-बगले में, जहाँ मेरा दस्तर और बैग था, न लौट सका। नदी पार करने के लिए आम-पाम वही कोई पुल भी न था। कार्य-स्थल घंगले में करीब छह मील दूर था और बीच में पांजरा नदी पड़नी थी। बगले तक पहुँचना असम्भव था, अतः पहली रात मैंने कार्य-स्थल के समीप मन्दवन नामक ग्राम में बितायी और दूसरे दिन दागारती गांव में ठहरा। यह वही गांव था जिनमें मेरा भी मिचाई के लिए यह पाइप साइकल बनाया जा रहा था। इस गांव के लोग इकट्ठे हो कर मेरे स्वागत को आये और उन्होंने मेरे टहरने का प्रबन्ध करते मेरा बड़ा मतलब किया। तीसरे दिन सुबह मैंने अपने भील कारीगरों तथा उनके बैलों की सहायता से नदी पार करके घंगले में पहुँचने का निश्चय किया। मेरे घोड़े और उगाड़ी बाड़ी की भी इन्ही लोगों ने चड़ी हुई नदी के पार पहुँचाया।

यहाँ इतना बताया ही काफी होगा कि पाइप साइकल बनाने का काम मैंने



की विभागीय परीक्षा तथा जिले की भाषा (मराठी) में भीस्तिन तथा लिखित परीक्षा पास करें। इनको पास किये बिना न तो किसी को नौकरी पक्की हो सकती थी और न ही पदोन्नति हो सकती थी। इन परीक्षाओं को पास करने के लिए आवश्यक अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान-संचय करने में एक नये अधिकारी को प्रायः दो-तीन वर्ष लग जाते थे। भाषा की परीक्षा पास करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात न थी, किन्तु मुझे सदेह था कि मैं व्यावहारिक इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता पूर्वक पास हो सकूँगा या नहीं। यह तो सत्य है कि इंजीनियरिंग की व्यावहारिक परीक्षा में बैठने का सुझाव दे कर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मेरे प्रति बड़ी उदारता और सहृदयता का परिचय दिया था। मैंने उन्हें लिखा कि समस्त व्यावहारिक परीक्षा पास करने के लिए मुझे अभी पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा था। उन्होंने मुझे डाटते हुए लिखा कि युवावस्था में ही इस प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण अपनाना शोभा नहीं देता। फलतः मैंने परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र भेज दिया। तीन इंजीनियरों की एक परीक्षा-समिति, नियुक्त की गयी, जिसमें मेरे मुख्य अधिकारी भी थे। समिति ने मुझे पास कर दिया और न केवल मेरी नौकरी पक्की हो गयी, बल्कि मुझे द्वितीय श्रेणी का सहायक इंजीनियर भी बना दिया गया। इस प्रकार बीस माह के अन्दर उन्नति करते हुए मैं प्रथम श्रेणी में पहुँच गया; जिसके परिणाम-स्वरूप मुझे ५०० रुपये मासिक वेतन मिलने लगा।

जिला खानदेश में मलेरिया का प्रकोप होने के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा और मैंने स्थान-परिवर्तन के लिए लिखा। केन्द्रीय इन्वीजन के चीफ इंजीनियर ने मेरी बदली पूना में, पूना जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सड़क व भवन निर्माण) के अधीन कर दी। अब तक मेरा संबंध सिचाई और जल-मप्लाई के कामों से रहा था। बदली होने पर मुझे मिजिल इंजीनियरिंग की एक नयी शाखा का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। कुछ समय के लिए मुझे गणेशखिण्ड (पूना) में स्थित 'गवर्नमेंट हाऊस' की देख-भाल का कार्य सौंपा गया। यहाँ प्रान्तीय सरकार का प्रधान कार्यालय था। इसके अतिरिक्त दूसरे निर्माण-कामों, जिनमें नगर के आम-जाल बनाने वाली सड़कों का काम भी शामिल था, मेरे विम्वे थे। यहाँ पूना के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी मुझे हर तरह से परर्या और मुझे लगा कि मेरे बारे में उनकी अच्छी राय बन गयी है।

बड़े सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया। उस वारे में जब एकजीवूटिव इंजीनियर को मेरी रिपोर्ट मिली, तब उन्होंने मुझे लिखा कि उपरोक्त जापान में उन्होंने जो कुछ भी मेरे गिलाफ़ लिखा था, उसे रद्द कर दिया गया है।

इसके बाद मैं एकजीवूटिव इंजीनियर की सहायनार्थ मच-ट्रिब्यूनल आफ़िसरों की देग-रेग में होने वाले कामों की प्रगति का निरीक्षण करना रहा। कुछ महीनों के बाद मुझे कुछ एक बड़ी नहरों की देग-भाऊ का कार्य मिला गया। ये नहरें जिंके के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित थी और केवल उनकी देग-भाऊ के लिए एक अलग नव ट्रिब्यूनल कायम किया गया था। यह बहुत ही सामान्य नवा जवाब था। मुत्तार कार्यों के लिए, सिल्वेराई अनुदान की मदद जमाई कम देना करनी थी कि उसमें नहरों की सम्मन आदि की व्यवस्था की जाएगी है। इस बीच गानदेग और नानिक जिंके के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (निचाई) ने कुछ नदीनों की छड़ी ली और मुझे इसके ग्यान पर कार्य करने पर अवसर मिला। इस छोटे समय के लिए मेरा प्रधान कार्य इस नानिक जिंके के सार्वसाध नामक ग्यान में रहा।

की विभागीय परीक्षा तथा बिस्ले की भाषा (मराठी) में भौतिक तथा लिखित परीक्षा पास करें। इनको पास किये बिना न तो किसी को नौकरी पक्की हो सकती थी और न ही पदोन्नति हो सकती थी। इन परीक्षाओं को पास करने के लिए आवश्यक अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान-संचय करने में एक नये अधिकारी को प्रायः दो-तीन वर्ष लग जाते थे। भाषा की परीक्षा पास करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात न थी, किंतु मुझे सदेह था कि मैं व्यावहारिक इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता पूर्वक पास हो सकूंगा या नहीं। यह तो सत्य है कि इंजीनियरिंग की व्यावहारिक परीक्षा में बैठने का सुझाव दे कर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मेरे प्रति बड़ी उदारता और सहृदयता का परिचय दिया था। मैंने उन्हें लिखा कि संभवतः व्यावहारिक परीक्षा पास करने के लिए मुझे अभी पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा था। उन्होंने मुझे डांटते हुए लिखा कि युवावस्था में ही इस प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण अपनाना शोभा नहीं देता। फलतः मैंने परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र भेज दिया। तीन इंजीनियरों की एक परीक्षा-समिति, नियुक्त की गयी, जिसमें मेरे मुख्य अधिकारी भी थे। समिति ने मुझे पास कर दिया और न केवल मेरी नौकरी पक्की हो गयी, बल्कि मुझे द्वितीय श्रेणी का सहायक इंजीनियर भी बना दिया गया। इस प्रकार बीस माह के अन्दर उन्नति करते हुए मैं प्रथम श्रेणी में पहुँच गया; जिसके परिणाम-स्वरूप मुझे ५०० रुपये मासिक वेतन मिलने लगा।

जिला खानदेश में मलेरिया का प्रकोप होने के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा और मैंने स्थान-परिवर्तन के लिए लिखा। केन्द्रीय डिबिजन के चीफ इंजीनियर ने मेरी बदली पूना में, पूना बिस्ले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सड़क व भवन निर्माण) के अधीन कर दी। अब तक मेरा संबंध सिचाई और जल-प्लाई के कामों से रहा था। बदली होने पर मुझे सिविल इंजीनियरिंग की एक नयी शाखा का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। कुछ समय के लिए मुझे गणेशलिण्ड (पूना) में स्थित 'गवर्नमेंट हाऊस' की देख-भाल का कार्य सौंपा गया। यहाँ प्रांतीय सरकार का प्रधान कार्यालय था। इसके अतिरिक्त दूसरे निर्माण-कार्य, जिनमें नगर के आस-पास बनने वाली मड़कों का काम भी शामिल था, मेरे जिम्मे थे। यहाँ पूना के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी मुझे हर तरह से परखा और मुझे लगा कि मेरे बारे में उनकी अच्छी राय बन गयी है।



मेरे कुछ वर्ष तक पूना जिले में कार्य करने के पश्चात् सन् १८१३ में मराठे सरकार की ओर से सतार (निच प्रांत) में काम करने के लिए एक इंजीनियर की मांग आयी। सतार नगर में वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए नियुक्त किये गये एक यूरोपियन अधिकारी का अचानक देहांत हो गया था और उनके स्थान की पूर्ति के लिए सरकार को एक इंजीनियर की जरूरत थी। पूना में मेरे अधिकांगी थी ई० के० रेनार्ड ने मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझ कर मुझे बताया कि यदि मैं इस पद की ग्रहण करना चाहूँ तो उन्हें क्षीघ्र सूचित करें। सूचित होकर भी मेरा उत्तर के हृदय की विजायता और उदारता का एक नमूना है, जहाँ मैं उसे यथा उचित करता हूँ :

पूना, २० मार्च १८१३

प्रिय मिस्त्रेस्वरैया,

मुझमें कहा गया है कि मैं एक विशेष कार्य के लिए किसी मुसोमपरी इंजीनियर का नाम दूँ। चार्ज, सतार में जल-निर्माण तथा वाटर-निर्माण की व्यवस्था करने का है।



उपर्युक्त प्रस्ताव को मेरे पास भेजते हुए बम्बई सरकार ने २ अगस्त, १८९६ के अपने शासकीय प्रस्ताव सं० २७८ E-१०९९ में अपनी ओर से निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ीं :

“बम्बई के महामहिम गवर्नर मपरिपद् इस अवसर पर महार वाटर वर्क्स के निर्माण में श्री विश्वेश्वरैया द्वारा की गयी सेवाओं की प्रशंसा करते हैं।”

छुट्टी से लौटने के पश्चात् मुझे गुजरात के मूरत जिले में नियुक्त किया गया। मूरत शहर में एक योजना के अन्तर्गत वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा था और काम को शुरू हुए थोड़े दिन ही हुए थे। इस योजना के अनुसार कुछ पानी प्राप्त करने के लिए तापती नदी के तल में गोलाकार कुएं गोदरे जाने थे। ऊपर से इन कुओं का मुंह बन्द किया जाना था ताकि नदी का जल-प्रवाह भीतर न आ सके और साफ पानी तल की रेतीली तहों में से छन-छन कर आता रहे। इस पानी का वाटव द्वारा नदी-तट के एक कुएं में पहुंचाना था, जहां इंजन लगा हुआ था। योजना का नक्शा जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तैयार किया था और नदी-तट में कुएं खोदने का काम मुझे सौंपा गया। उस समय मुझे कुछ महीनों तक मूरत और भड़ौच जिलों के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर काम करने का अवसर भी मिला। यह काम मूरत वाटर वर्क्स की मेरी जिम्मेदारियों के अर्तियोग्य था।

## सिंचाई इंजीनियरिंग, जल-वितरण तथा जल निकास

मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय द्विवीजन के महायुक्त के पद में अप्रैल, सन् १८९९ में मेरी बदनो जिला पूना के सिंचाई विभाग में हो गयी। सिंच को छोड़ कर बम्बई प्रेजीडेंसी में यह सबसे बड़ा सिंचाई जिला था। इसमें प्रेजीडेंसी के दो सबसे बड़े जलाशय थे और यहां प्रेजीडेंसी भर में सबसे अधिक इलाका नहरों द्वारा सींचा जाता था। पूना के उपनगरीय क्षेत्र तथा पूना और किरकी छावनियों में जल वितरण का कार्य भी मेरे विधि में था। पूना नगर की आवश्यकताओं के लिए बिना साफ किया हुआ जल, मूठा नामक नहर में सींचा जाता था। यह नहर पूना नगर के दक्षिण में कुछ ऊंची गतह पर बहती थी।

जिला पूना की सिंचाई व्यवस्था में मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह पेश आयी कि पानी के अनियमित वितरण तथा किसानों द्वारा उसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाय। पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए यह जरूरी था कि वितरण व्यवस्था पर नियन्त्रण रखा जाय। परन्तु वहां के किसान उसके आदी न थे। नहर के पानी के निबाम-स्थल पर लगे फाटकों की मरम्मत तथा निगरानी सिंचाई विभाग के कर्मचारी भली-भांति करते थे, लेकिन सहायक सिंचाई भागों में जहरत से अधिक जल पहुँच जाता था और किसान उसका दुरुपयोग करते थे। पूना नगर के निकटवर्ती इलाके की सिंचाई व्यवस्था एक बहुत ही सुयोग्य भारतीय सहायक इंजीनियर श्री बी० एन० वर्तके के अधीन थी। श्री वर्तके पूना शहर के ही रहने वाले थे। उन्होंने जल वितरण पर नियन्त्रण करने के लिए एक नया व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार बारी-बारी से दम-दम दिन के लिए सबको निश्चित जल-राशि दी जाती थी। परन्तु वहां के किसान और जमींदार, जो मनमाने ढंग से पानी लेने के आदी थे, इस नियन्त्रण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे और एक अच्छा खासा हंगामा मचा हो गया। इस नियन्त्रण के विरुद्ध महाराष्ट्र के महान् नेता श्री बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में निकलने वाले प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र 'केसरी' में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। इस पत्र ने लिखा कि मेरे अधीन काम करनेवाले

सिचाई विभाग के अधिकारियों ने जल वितरण व्यवस्था पर, मनमाने ढंग से, अनेक अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

मैंने 'केसरी' की कतारों सरकार को भेज दीं और साथ में यह स्पष्ट कर दिया कि इस नियन्त्रण को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने यह भी लिखा कि पानी द्वारा सिंचित भेत ज्यादातर पूना निवासियों के हैं और इस मामले में इतना हाथ-तोड़ा मचने का कारण यह है कि पूना के ये लोग अपने शहर में काफी असर-रगूम रगते हैं।

ब्रम्हर्ष सरकार ने अपने उत्तर में लिखा कि सरकार को नगर विभाग के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, और इसके साथ ही उन्होंने मुझे अर्द्ध-निर्णय सम्बन्धी सब मामलों का निपटाने का अधिकार दे दिया।

फिर भी हमारी ओर से इस बात का प्रयत्न किया गया कि किसान लोग स्वयं ही गारी दिवनि को समझ लें। मैंने भूमि-स्वामियों की एक बैठक बुलाने के लिए फार्मगन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ० आर० पी० परांजपे से (जिन्हें बाद में मैं की उपाधि मिली) उनके कॉलेज का हॉल मांगा। यह कॉलेज नगर द्वारा भीने आने-वाले सेवों के समीप ही था।

वल्कि इस काम में सहायता के लिए, अपने खर्च पर, एक पटवारी भी देने को तैयार थी। अन्त में किसान इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने आग्रह किया कि नहर-विभाग जल-वितरण व्यवस्था पर अपने इस नियन्त्रण को बनाये रखे।

श्री बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध सहयोगी स्वर्गीय श्री एन० सी० केलकर ने इस समस्या के बारे में पूरी छान-बीन की और इस बात से संतुष्ट हो गये कि सरकार ने जो कुछ किया वह ठीक है। इस संबंध में उन्होंने अपने द्वारा सम्पादित पुनः 'केसरी' में कई लेख लिखे, जिनमें सरकार द्वारा अपनाई गयी नीति को किसानों के लिए हितकारी बताया। इस प्रकार खुले तरीके से निपटाने तथा प्रकाश में लाने से यह समस्या मुलमल गयी। किसानों ने जल-वितरण सम्बन्धी सरकारी कानूनों का पालन करना आरम्भ कर दिया और फिर उनकी कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं आयी।

## सिचाई आयोग का दौरा

उन्ही दिनों भारत सरकार ने भारतीय राज्य सचिव की स्वीकृति से भारतीय सिचाई आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग भारत भर में दौरा करके सरकार को सिचाई द्वारा भेती में वृद्धि करने के तरीकों के बारे में परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग के अध्यक्ष के पद पर मिश्र के त्यागि प्राण इंजीनियर सर कॉलिन रॉबर्ट माजिफ की नियुक्ति हुई और केन्द्रीय व प्रांतीय गवर्नरों के राज्य तथा सिचाई विभागों के कुछ उच्चाधिकारी इस आयोग के सदस्य बनाये गये। बम्बई प्रेसीडेंसी में आयोग ने केवल पूना सिचाई क्षेत्र का ही दौरा किया, क्योंकि महाराष्ट्र द्वारा सिचाई की दृष्टि से यह जिला बम्बई प्रेसीडेंसी में प्रमुख माना जाता था। मिश्र की छोड़ कर, बम्बई प्रेसीडेंसी में सिचाई व्यवस्था की स्थिति को आयोग के सम्मुख स्पष्ट रूप में रखने के लिए मैंने एक शायन तैयार किया। शायन का मुख्य उद्देश्य यह था कि बम्बई प्रेसीडेंसी की सिचाई सम्बन्धी विविध बातों की समझाकर, उनमें प्रजागम, मृत्पावन और व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन बिचे जायें और सिचाई के तरीकों में सुधार करने तथा नहरों द्वारा अधिक भूमि की सिचाई करने राज्य में वृद्धि की जाय। बम्बई गवर्नर ने

सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जल वितरण व्यवस्था पर, मनमाने ढंग से, अनेक अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

मैंने 'केसरी' की कतारों सरकार को भेज दीं और साथ में यह स्पष्ट कर दिया कि इस नियन्त्रण को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने यह भी लिखा कि पानी द्वारा सिंचित खेत ज्यादातर पूना निवासियों के हैं और इस मामले में इतना हाथ-तोवा मचने का कारण यह है कि पूना के वे लोग अपने शहर में काफ़ी असर-रसूख रखते हैं।

दम्बई सरकार ने अपने उत्तर में लिखा कि सरकार को नहर विभाग के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, और इसके साथ ही उन्होंने मुझे जल-वितरण सम्बन्धी सब मामलों को निपटाने का अधिकार दे दिया।

फिर भी हमारी ओर से इस बात का प्रयत्न किया गया कि किसान लोग स्वयं ही सारी स्थिति को समझ लें। मैंने भूमि-स्वामियों की एक बैठक बुलाने के लिए फ़र्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ० आर० पी० परांजपे से (जिन्हें बाद में सर की उपाधि मिली) उनके कॉलेज का हॉल मांगा। यह कॉलेज नहर द्वारा सींचे जाने-वाले खेतों के समीप ही था।

कॉलेज के हॉल में किसानों की बैठक का आयोजन हुआ। प्रमुख किसानों के साथ सिंचाई विभाग के छोटे कर्मचारियों को भी बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया, ताकि जल-वितरण सम्बन्धी अव्यवस्था के आरोपों के बारे में सवाल-जवाब किये जा सकें। हमने किसानों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम नहर के प्रत्येक निकास स्थल पर दस दिन की अवधि में दिये गये पानी को उनकी उपस्थिति में मापने के लिए तैयार हैं, ताकि यह ज्ञात हो जाय कि जिस हिसाब से नहर से पानी का निकास होता है, उस हिसाब से कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई होती है। ऐसा करते समय विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए दिये जानेवाले पानी की मात्रा को ध्यान में रखा जायगा। हमने उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि इस व्यवस्था को लागू करते समय विभिन्न फसलों के लिए जितना पानी देना निश्चित किया गया था, हम उससे भी कुछ अधिक मात्रा में पानी देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि काश्तकार उपलब्ध जल राशि को आपस में समझौते द्वारा बांट लेने के लिए राजी हों। इस बारे में सरकार किसानों को न केवल उनकी इच्छानुसार जल-वितरण पर नियन्त्रण रखने का अधिकार देने को तैयार थी,

वर्तक इस काम में सहायता के लिए, अपने खर्च पर, एक पटवारी भी देने को तैयार थी। अन्त में किसान इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने आप्रह किया कि नहर-विभाग जल-वितरण व्यवस्था पर अपने इस नियन्त्रण को बनाये रखे।

श्री बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध सहयोगी स्वर्गीय श्री एन० सी० बेलकर ने इस समस्या के बारे में पूरी छान-बीन की और इस बात से संतुष्ट हो गये कि सरकार ने जो कुछ किया वह ठीक है। इस सवध में उन्होंने अपने द्वारा सम्पादित पत्र 'केसरी' में कई लेख लिखे, जिनमें सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति को किसानों के लिए हितकारी बताया। इस प्रकार खुले तरीके से निपटाने तथा प्रकाश में लाने से यह समस्या सुलझ गयी। किसानों ने जल-वितरण सम्बन्धी सरकारी कानूनों का पालन करना आरम्भ कर दिया और फिर उनकी कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं आयी।

### सिंचाई आयोग का दौरा

उन्ही दिनों भारत सरकार ने भारतार्थ राज्य सचिव की स्वीकृति में भारतीय सिंचाई आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग भारत भर में दौरा करके सरकार को सिंचाई द्वारा भेती में वृद्धि करने के तरीकों के बारे में परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग के अध्यक्ष के पद पर पिछ के क्यालि प्राप्त इंजीनियर सर कॉलिन स्कॉट माफिक की नियुक्ति हुई और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के राजस्व तथा सिंचाई विभागों के कुछ उच्चाधिकारी इस आयोग के सदस्य बनाये गये। बम्बई प्रेजीडेंसी में आयोग ने केवल पूना सिंचाई क्षेत्र का ही दौरा किया, क्योंकि नहरो द्वारा सिंचाई की दृष्टि से यह जिला बम्बई प्रेजीडेंसी में प्रमुख माना जाता था। सिंध को छोड़ कर, बम्बई प्रेजीडेंसी में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति को आयोग के सम्मुख स्पष्ट रूप से रखने के लिए मैंने एक जापन तैयार किया। जापन का मुख्य उद्देश्य यह था कि बम्बई प्रेजीडेंसी की सिंचाई सम्बन्धी विशिष्ट बातों को ममज्ञाकर, उनमें प्रशासन, मूल्यांकन और व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन किये जायें और सिंचाई के तरीकों में सुधार करके तथा नहरो द्वारा अधिक भूमि की सिंचाई करके राजस्व में वृद्धि की जाय। बम्बई सरकार ने





श्री विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार की गयी एक अत्यन्त विशिष्ट और दिलचस्प योजना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने दीर्घकालीन पट्टे की खण्ड प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। इस योजना को हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और इसकी चर्चा रिपोर्ट के बम्बई अध्याय में की गयी है। हम इस योजना को हरदृष्टि से पूर्ण और मोच-विचार कर बनायी गयी समझते हैं। यद्यपि बम्बई सरकार ने अभी इस योजना पर विचार नहीं किया तथापि हम समझते हैं कि इसका मूल सिद्धान्त हर दृष्टि से परिपूर्ण है। यदि इस प्रकार की कोई प्रणाली दक्षिण में सिंचाई कार्यों के लिए लागू की जाय तो निश्चय ही इससे लोगों को अधिक लाभ होगा और माय ही सरकारी आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि श्री विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार की गयी इस प्रणाली को शीघ्र ही पूर्णरूपेण कार्यान्वित करना सम्भव हो सकेगा।”

रिपोर्ट के अनुसार इस प्रणाली का उद्देश्य यह था कि सिंचाई की सुविधाओं को अधिक गांवों तक पहुंचाया जाय, और, विशिष्ट खण्डों में विशिष्ट प्रकार की भूमि तथा परिस्थितियों के अनुसार, प्रत्येक गांव की सिंचाई की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय। प्रत्येक गांव में खण्ड का कुछ क्षेत्र इतना विस्तृत अवश्य होना चाहिए था, जिससे प्रत्येक किसान को, जो नहरी पानी से सिंचाई करता हो, सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही प्रत्येक किसान के हिस्से में इतना अधिक पानी भी न जाना चाहिए कि अनुकूल ऋतुओं में वह जल आपूर्ति के महत्व को ही भुला दे, जैसा कि अब तक होता आया था।

प्रत्येक खण्ड में भूमि के केवल एक तिहाई भाग में गन्ना तथा अन्य वारहमासी फसलें बोयी जायें और बाकी दो-तिहाई भाग में या तो रबी की फसल हो या वर्षा ऋतु की, और या फरवरी के अन्त तक सन्निधियां उगायी जायें। फरवरी के बाद, वर्षा ऋतु के आरम्भ होने तक, केवल उस एक-तिहाई भाग के लिए ही नहरी-पानी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो, जिसमें वारहमासी फसलें उगायी गयी हों। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड में, चारों-चारों से, तीन तरह की खेती की जा सकेगी।

बम्बई सरकार ने नीरा नहर पर इस योजना को लागू करने का काम मुझे सौंपा। परन्तु जिला कलक्टर और वहां के ‘सब-डिवीजनल-आफिसर,’ जो पुरोपनिधन थे, इस योजना के पक्ष में नहीं थे। वहां के मामलातदारों और राजस्व

जब मैं इस जलाशय को देखने गया तो पाया कि यद्यपि इन फाटकों को लगाये ४५ वर्ष से अधिक समय हो चुका है, तब भी ये बड़े सन्तोषजनक रूप से काम दे रहे हैं।

बार में मेरे परामर्श से डमी किस्म के फाटक ग्वालियर जल-सप्लाई से सम्बन्धित टीमरा डैम के फालतू पानी को रोकने के लिए तथा मैसूर नगर के समीप, कुम्भारगंगा गागर बांध के फालतू पानी को रोकने के लिये, लगाये गये थे।

### पूना तथा किरकी जल-वितरण व्यवस्था

पूना नगर में बिना साफ़ किया हुआ नहरी पानी दिया जाता था और पूना तथा किरकी छावनियों में साफ़ किया हुआ पानी दिया जाता था। ये दोनों जल-वितरण व्यवस्थाएं लगभग छः वर्ष तक मेरी देख-रेख में रहीं। छावनी की जल वितरण व्यवस्था में कई सुधार करने की जरूरत थी। भारत के तत्कालीन सेनापति लॉर्ड किचनर छावनी की जल-वितरण व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा उसके सुधारों के लिए आवश्यक धन-राशि की मंजूरी देने के अभिप्राय से दो बार पूना के दौरे पर आये। चूंकि स्थानीय गैर सैनिक प्रशासन अधिकारियों का सैनिक छावनी की जल-वितरण व्यवस्था में कोई हाथ नहीं था, अतः पहली बार बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लेमिंगटन ने तथा दूसरी बार लॉर्ड सिडेनहाम ने मुझे जल-सप्लाई सम्बन्धी समस्याओं पर लॉर्ड किचनर के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कहा। तीसरी बार लॉर्ड किचनर से मेरी मुलाकात बड़े विचित्र ढंग से हुई। बम्बई के गवर्नर लॉर्ड सिडेनहाम का अंगरक्षक एक दिन दोपहर के समय पूना में मेरे निवास स्थान पर पहुंचा और उसने कहा कि गवर्नर ने मुझे उसी शाम पांच बजे खड़गवासला के "लेक फ़ाइफ़" जलाशय पर बुलाया है। मैंने कहा कि खड़ग-वासला झील की देख-रेख का काम अब किसी अन्य अधिकारी के जिम्मे है और मैं तो सफ़ाई इंजीनियर के पद पर काम कर रहा हूँ।

फिर भी उसने मुझसे साथ चलने का आग्रह किया और कहा कि गवर्नर मुझ से ही मिलना चाहते हैं। खैर, पूना से लगभग नौ मील दूर जब मैं उस जलाशय पर पहुंचा तो गवर्नर ने लॉर्ड किचनर से मेरा परिचय कराया। तब मैं समझा कि मेरे स्वचालित नहरी फाटकों के काम का निरीक्षण करने के लिए ये दोनों अधिकारी पहले ही से खड़गवासला पहुंच चुके हैं। वहां फाटकों का काम देखने

तथा उनके बारे में पूछ-ताछ करने के पश्चात् वे गणेशखंड के 'गवर्नमेंट हाऊस' में लौट आये।

सन् १९०४ में जब मैं पूना में नियुक्त था, मुझे डिमला में आयोजित एक सिंचाई सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के सभी प्रांतों के सिंचाई विभाग के इंजीनियर उपस्थित थे। बम्बई प्रेजीडेंसी में मुझे तथा एक कनिष्ठ यूरोपियन अधिकारी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया था। मैंने सम्मेलन में चार प्रस्ताव पेश किये, जिनमें से कुछेक पर वह भी हुई, और मैं समझता हूँ कि उन चारों को प्रकाशित किया गया।

सन् १९०१ में बम्बई सरकार के सफाई इंजीनियर छट्टी लेकर यूरोप चले गये और मुझे पूना के कार्यकारी इंजीनियर (सिंचाई) के अपने पद के साथ साथ, उनका काम भी सभालने के लिए कहा गया। बाद में उनके स्थान पर काम करते हुए मैंने पूना नगर के लिए पहली बार आधुनिक मलमार्ग (पाइप सीवरेज) योजना तैयार की। नगरपालिका की जिम बैठक में इस योजना पर विचार करके इसकी स्वीकृति दी गयी थी, उसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता श्री गोपालकृष्ण गोखले कर रहे थे।

यहाँ यह धृता देना असंगत न होगा कि पूना में काम करते समय इंजीनियरिंग विभाग की सरकारी नीतियों से मेरा निकट का सम्पर्क रहा था और मुझे काफी दिलचस्प काम करने पड़ते थे। बम्बई लोकनिर्माण विभाग में, अपनी सेवा में, अन्तिम काल में, लगातार दस वर्ष के अपने आवास में, मुझे बड़े सुख और लाभप्रद अनुभव प्राप्त हुए। इस अवधि में मुझे सदा यूरोपियन विभागीय अभ्यर्थों के निकट सम्पर्क में काम करने का अवसर मिला। ये अधिकारी बहुत उदार और सहृदय हुआ करते थे। इसके अनिश्चित, मैं समझता हूँ कि मुझे पूना और दक्षिण में बहुत से भारतीय नेताओं का भी विद्वान प्राप्त था।

बम्बई सरकार के दफ्तर, हर साल, वर्षा के तीन-चार महीनों के लिए पूना चले जाते थे। अतः मुझे उच्च सरकारी अधिकारियों से तथा बम्बई विधान परिषद् के पूना में होनेवाले अधिवेशन में भाग लेने के लिए बम्बई प्रान्त के विभिन्न मार्गों से आये प्रमुख देशवासियों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के अवसर प्राप्त होने रहते थे।

तथा इसे चलाने का वार्षिक खर्च, ऋण की अदायगी तथा व्याज की रकम मिला कर, ३०,००० रु० के करीब होगा। जनता पर इस खर्च का भार फी व्यक्ति बहुत सामान्य होगा, क्योंकि अदन शहर और शेख ओथमान के मलमार्गों को समुद्र में बहाया जा सकता है, और इस प्रकार इन पर अधिक लागत नहीं आवेगी।”

अदन की जल-वितरण समस्या के बारे में मैंने निम्नलिखित रिपोर्ट दी :

“जल-वितरण व्यवस्था के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं किया जा सकता। सैनिक तथा व्यापारी वर्ग द्वारा अधिकांशतः समुद्र का ही साफ़ किया हुआ जल इस्तेमाल किया जाता है। अदन में बहुत-सी ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ हैं, जो पानी जमा करके बेचने का काम करती हैं। कुछ पानी, जोकि थोड़ा खारा होता है, एक सेतुवाही द्वारा प्रधान द्वीप से बन्दरगाह में लाया जाता है। यह सेतुवाही सैनिक अधिकार में है। इसके अतिरिक्त व्यापारी बन्दरगाह के पार के इलाके से बैलगाड़ियों द्वारा पानी लाते हैं।

“जमा हुआ पानी ३ रु० प्रति सौ गैलन के हिसाब से बिकता है और शेख-ओथमान के पानी की दूसरी किस्में एक रुपये से डेढ़ रुपये प्रति सौ गैलन के हिसाब से बिकती हैं। अनुमान है कि अदन निवासी लगभग सात लाख रुपये वार्षिक पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करते हैं।

“पीने योग्य पानी की बड़ी कमी है, परन्तु इस कमी को पूरा करने के लिए प्रधान द्वीप से ही जल प्राप्त करना होगा। मैंने इस बारे में कोई जांच नहीं की, परन्तु लगता है कि शुरू में जल-वितरण व्यवस्था के निर्माण पर काफ़ी व्यय होगा।

“अदन में पानी की बहुत अधिक मांग होने के कारण लोग इसके लिए ऊँचे से ऊँचे दाम दे रहे हैं। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि यहां किसी जल-वितरण व्यवस्था का निर्माण हो जाय तो वह अच्छी खासी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

“अदन से ६० मील दूर उत्तर की ओर पहाड़ी इलाका है जहां पर्याप्त वर्षा होती है। वर्षा का जल पहाड़ियों से नीचे बहकर एक नदी में मिल जाता है। बहुत-सी दूसरी नदियों की भांति इस नदी का जल समुद्र तक नहीं पहुँचता और कुछ दूर आगे जाकर, लहेज नामक स्थान पर नदी के रेतीले तल में ही समा जाता है। एक तजवीज़ यह थी कि नदी तल में बन्द मुंह वाले जमींदोज़ कुएं खोदकर उनमें पानी जमा किया जाये और उसे पम्प करके पाइप द्वारा १८ मील दूर अदन

में पहुंचाया जाय। यह योजना काफी सन्तोषजनक रहती, परन्तु इस पर एक तो अधिक व्यय हो जाने की सम्भावना थी, और दूसरा यह डर भी था कि वही लहेज के आस-पास बसनेवाले उपद्रवी कबीलो के लोग पाइप को काट न दें।"

जैसा कि बताया जा चुका है, मैंने एक रिपोर्ट जल-निकास और दूसरी जल-वितरण व्यवस्था के लिए तैयार की। बाद में एक सरकारी आदेश द्वारा बताया गया कि अदन के मेजर जनरल बराय ने जल-निकास तथा जल-वितरण योजनाओं की मफारिशा करते हुए लिखा।

"श्री विश्वेश्वरैया ने, जिन्हें मल-निकास के प्रश्न पर सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था, एक अत्यंत लाभदायक रिपोर्ट तैयार की, जो कि २० जनवरी, १९०७ को सरकार को भेजी जा चुकी है। हालांकि मल-मार्ग के निर्माण की यड़ी जरूरत थी, परन्तु ताजा जल देने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना उससे भी अधिक आवश्यक था।"

बम्बई सरकार के ३० जून, १९०९ के एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार ने आदेश दिया है कि जल-वितरण योजना के नक्शे तथा अनुमानित व्यय विवरण तैयार किये जायें और लहेज में जमीन लेकर वहां कुआं खोदने तथा भविष्य में उसकी रक्षा करने के धारे में लहेज के सुस्तान के साथ बातचीत की जाय।

जब मैं अदन में था तो मुझे उस समिति में शामिल होने के लिए भी कहा गया जो कि अदन में निर्मित सड़को पर हुए खर्च को लेकर भारत तथा बम्बई राज्य सरकार के मध्य हुए कुछ मत-भेदों का निपटारा करने के लिए बनायी गयी थी।

## कोल्हापुर शहर की जल-वितरण व्यवस्था

कोल्हापुर शहर में दिया जानेवाला पानी एक तालाब से आता था। इस तालाब के कच्चे बांध को टूटने से रोकने के बारे में परामर्श देने के लिए मुझे दो-तीन बार वहां जाने का अवसर मिला। कोल्हापुर के राजनैतिक एजेंट सैप्टीनेंट जर्नल डब्ल्यू० बी० फॉरिस ने बम्बई सरकार को लिखा कि तालाब के कच्चे बांध में जगह-जगह दरारें हो गयी हैं और उनके टूटने का खतरा है, और दोषपूर्ण निर्माण के कारण, बांध की सारी डलान पर पलस्तर काफी सरक गया था जिससे उनको भयंकर खतरा था। उन्होंने यह भी लिखा कि:

“यह अत्यंत आवश्यक है कि जल-वितरण व्यवस्था को विलकुल ठप हो जाने से रोकने के लिए महाराज कोल्हापुर किसी योग्य इंजीनियर का परामर्श लें। हमारे पास सलाहकारों की तो कमी नहीं, पर वे इस मामले में कोई जानकारी नहीं रखते। अतः मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए किसी अनुभवी यूरोपियन इंजीनियर को नियुक्त किया जाय, जो पूरी छानबीन करने के पश्चात्, यह सलाह दे कि क्या कुछ करना जरूरी है।”

इस काम के लिए मुझे कोल्हापुर भेजा गया और स्थानीय इंजीनियरों ने मेरे सुझावों के अनुसार बड़ी लगन से मरम्मत आदि का काम पूरा किया। इस काम के लिए मुझे कोई तीन बार कोल्हापुर जाना पड़ा। मरम्मत हो जाने के पश्चात् तालाब का कच्चा बांध विलकुल सुरक्षित हो गया।

इसके बाद कर्नल फ्रैरिस ने मुझे उस पत्र की प्रतिलिपि भेजी जिसमें कोल्हापुर के दीवान ने उनसे कहा था कि वह श्री विश्वेश्वरैया की सेवाओं के लिए दरबार की ओर से बम्बई सरकार का आभार प्रकट कर दें। उन्होंने लिखा :

“श्री विश्वेश्वरैया के सुझाव अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुए। दरबार को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि उनकी देखरेख में हुआ कार्य बहुत ही संतोषजनक है और गत मास हुई भारी वर्षा से भी इसे कोई क्षति नहीं पहुंची। कृपा कर श्री विश्वेश्वरैया को सूचित कर दिया जाय कि अब जलाशय लवालव भरा हुआ है और बांध सुरक्षित है।”

पत्र को भेजते हुए कर्नल फ्रैरिस ने लिखा कि श्री विश्वेश्वरैया का दरबार की ओर से आभार प्रकट कर दिया जाय।

### अन्य छोटे-मोटे कार्य

१५ मई, १९०७ की सरकारी सूचना, संख्या ई-१३२५, के अनुसार बम्बई प्रेजीडेंसी के तीन सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर डिवीजन छः महीनों के लिए मेरे अधीन कर दिये गये। दक्षिणी डिवीजन और परियोजना डिवीजन श्री एच० एफ० वीले के अधिकार में थे और मैं सफाई इंजीनियर के अपने स्थायी पद पर कार्य कर रहा था। श्री वीले छः महीने की छुट्टी लेकर चले गये और उनकी दो डिवीजनों का कार्य भी मुझे सौंप दिया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि गोदावरी मुला

और कुकारी का सर्वेक्षण-कार्य, जो कि दक्षिणी डिवीजन के सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर के अधीन था, जारी रहेगा। इस अवधि में मुझे पूना और बेलगाम, दो प्रधान कार्यालयों का काम देखना पड़ा।

बेलगाम में मैंने सड़को की मरम्मत सम्बन्धी कुछ नियम जारी किये। सड़कों की देख-रेख करनेवाले कई छोटे अधिकारियों को मैंने बेलगाम में बुलाया और उनके साथ पहले में लागू नियमों पर विचार-विमर्श करके नये नियम तैयार किये। बाद में सरकार ने इन नियमों को छपवा कर मिश्र के अतिरिक्त बम्बई प्रेजीडेंसी के लोक निर्माण विभाग की तीनों स्थायी डिवीजनों में भेजा।

इस अवधि में मुझे दक्षिणी डिवीजन के धारवार और बीजापुर नगरों के लिए जल-वितरण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर उसके अनुसार काम करते हुए, इन दोनों जिलों के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने योजना कार्य सम्पन्न किया।

अक्तूबर १९०८ में बम्बई के गवर्नर लॉर्ड सिडनहाम बीजापुर आये और नगर पालिका तथा जिला मण्डल के मान-पत्रों का उत्तर देते हुए उन्होंने नगर की जल-वितरण व्यवस्था के बारे में जो कुछ कहा वह इस प्रकार है

“मैं यह भलीभांति जानता हूँ कि बीजापुर नगर का भविष्य इस कठिनाई के हल पर निर्भर है। श्री विश्वेश्वरैया जैसे सुयोग्य इंजीनियर द्वारा तैयार की गयी योजना तथा उसे कार्य रूप देने के लिए चार लाख रुपये इकट्ठा करने की तजवीज पर विचार किया जा रहा है।”

इसके पश्चात् सरकार की ओर से जल-वितरण व्यवस्था की स्वीकृति दे दी गयी। योजना की समाप्ति पर नगर-पालिका ने मेरे प्रति आभार प्रकट किया।

सफाई इंजीनियर के रूप में कार्य करते समय मैं बम्बई प्रेजीडेंसी के सफाई बोर्ड का सचिव तथा अध्यक्ष भी था। इस पद पर कार्य करते हुए मैंने प्रेजीडेंसी के कई शहरों की जल-वितरण व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में तय्य और आकड़े एकत्रित करके उन्हें मुद्रित करवाया।

मुख्य इंजीनियर के पद पर काम करते हुए नौकरी के अन्तिम दिनों में मुझे उस समिति का सदस्य बनाया गया जो कि बम्बई नगर के कई गन्दे इलाकों में सुधार करने के लिए नियुक्त की गयी थी। इस समिति के अध्यक्ष बम्बई सरकार



के सज्जन जनरल थे। बम्बई के तत्कालीन देशभक्त नेता सर फ़िरोज़शाह मेहता भी समिति के सदस्य थे।

फ़रवरी, १९०५ में बम्बई सरकार ने मुझे बम्बई सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त कर दिया। यहां मेरा काम उन सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित था जिनके बारे में अभी विचार हो रहा था। इस बारे में एक सरकारी आदेश द्वारा बताया गया कि श्री विश्वेश्वरैया सफ़ाई इंजीनियर के पद के साथ-साथ लोक-निर्माण विभाग में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष कार्य करेंगे।

तकनीकी या प्रशासन सम्बन्धी मतभेद उत्पन्न हो जाने पर उनके निपटारे के लिए मुझे कई समितियों में काम करने का अवसर मिला। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा सम्बन्धी सुधार करने के लिए एक समिति बनायी गयी। मेरे अतिरिक्त, निदेशक, शिक्षा-विभाग तथा कॉलेज के प्रिंसिपल इस समिति के सदस्य थे। उस समय तक यह कॉलेज 'साइंस कॉलेज' के नाम से पुकारा जाता था। समिति ने इसका नाम बदल कर इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया और पाठ्यक्रम में भी उचित परिवर्तन किये। सरकार ने समिति द्वारा दिये गये तमाम सुझाव मान कर उन्हें लागू कर दिया।

नगर-पालिकाओं के लिए मैं जो भी कार्य कर रहा था उसकी सरकार ने बड़ी उदारता से सराहना की। २८ जनवरी, १९०८ के दिन अहमदाबाद में, नगर-पालिका के मान-पत्र के उत्तर में, बम्बई के गवर्नर लॉर्ड सिडनहाम ने जो कुछ कहा उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहां उद्धृत करता हूं:

“यह ठीक है कि सरकार नगर-पालिकाओं के प्रति उदार है। परन्तु मैं समझता हूं कि नयी योजनाओं के बारे में इस बात की तसल्ली होनी जरूरी है कि वे हर दृष्टि से पूर्ण हों और जल-वितरण व्यवस्था के प्रबन्ध कार्य में किसी प्रकार का अपव्यय न हो। मेरा तो यह सुझाव है कि आप इस बारे में श्री विश्वेश्वरैया जैसे सुयोग्य इंजीनियर का परामर्श लें।”

सितम्बर, १९०४ में मुझे बम्बई विश्वविद्यालय का अधिसदस्य नामजद किया गया। इस बारे में सूचित करते हुए बम्बई के गवर्नर के निजी सचिव ने मुझे लिखा—“महामहिम गवर्नर आशा करते हैं कि आप विश्वविद्यालय के अधिनियम बनाने के महत्वपूर्ण काम में योग दे सकेंगे। ये अधिनियम नयी सिनेट के बनते ही उसके सामने रखे जायेंगे।”

## अध्याय ४

### बम्बई राज्य में काम

बम्बई सरकार की सेवा में मैंने अपने जीवन के लगभग चौदह वर्ष पूना में ही बिताये। पूना में मेरा प्रवास, कई प्रकार से, मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। पूना बम्बई प्रेसीडेंसी के तीन प्रधान नगरों में से एक था। दूसरे दो नगर बम्बई तथा महाबलेश्वर थे। महाबलेश्वर एक पर्वतीय स्थल है। समय-समय पर मुझे सरकारी काम से बम्बई और महाबलेश्वर भी जाना पड़ता था। बम्बई सरकार के सबसे बड़े यूरोपियन अधिकारी सन्त गर्मी के दिनों में काम करने के लिए महाबलेश्वर चले जाते थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, १९०५ में मैं लगभग दस महीनों तक बम्बई मजिस्ट्रेट के विरॉप कार्य पर लगा रहा। फिर भी मैं समझता हूँ कि इतने दीर्घकाल तक पूना में रहकर मुझे एक प्रकार की सुविधा दी गई थी। जिन चार वर्षों तक मैं प्रांतीय अधिकारी के पद पर रहा मुझे अपने काम के मिलमिले में—बम्बई प्रेसीडेंसी के सिंध महित अधिकांश भागों में घूमने-फिरने के अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार के विविध अनुभवों द्वारा मुझे प्रान्त के शासन प्रबन्ध के बारे में और सरकारी नेताओं की राजनीतिक तथा सामाजिक गति-विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अवसर मिले। साधारणतः सरकारी नौकरी में इस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती।

सफाई इजीनियर के अनिरीक्त और भी बहुत से विभागीय अध्यक्ष ऐसे थे जिनके प्रधान कार्यालय स्थायी रूप से पूना में ही थे।

इसके अनिरीक्त पूना बौद्धिक तथा शिक्षा-केन्द्र भी था और बहुत से भारतीय अधिकारी नौकरी से अवकाश पाकर वही बस जाते थे। फरग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर, ममाबार पत्रों के सम्पादक और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी राजनीति में विशेष रुचि रखते थे और इस बात के पक्षपाती थे कि हिन्दुस्तानियों को राजनीतिक सुविधाएँ तथा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के और अधिक अवसर मिलने चाहिएँ। उनमें श्री महादेव गोविंद रानाडे जैसे योग्य, विद्वान्, सतुलित विचारों वाले तथा सतर्क नेना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह सरकारी कर्मचारी होने के साथ-साथ पूना तथा महाराष्ट्र की अबुद्ध जनता के मित्र, दार्शनिक

के मन्त्रालय बन गया था। वम्बई के नगरपालीक के अध्यक्ष नेता मर क्रियोजनाह मेहता भी समिति के सदस्य थे।

फरवरी, १९०५ में वम्बई सरकार ने मुझे वम्बई मनिपायल में विशेष कार्या-विहारी नियुक्त कर दिया। वहाँ मेरा काम उन विनाई परियोजनाओं से सम्बन्धित था जिनके बारे में अभी विचार हो रहा था। इस बारे में एक सरकारी आदेश द्वारा बताया गया कि श्री विश्वेश्वरैया वम्बई इंजीनियर के पद के साथ-साथ लोक-निर्माण विभाग में विनाई परियोजनाओं के लिए विशेष कार्य करेंगे।

नकलीबी या प्रशासन सम्बन्धी मनभेद उत्पन्न हो जाने पर उनके निपटारे के लिए मुझे कई समितियों में काम करने का अवसर मिला। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा सम्बन्धी सुधार करने के लिए एक समिति बनायी गयी। मेरे अतिरिक्त, निदेशक, शिक्षा-विभाग तथा कॉलेज के प्रिंसिपल इस समिति के सदस्य थे। उस समय तक यह कॉलेज 'माइंस कॉलेज' के नाम से पुकारा जाता था। समिति ने इसका नाम बदल कर इंजीनियरिंग कॉलेज रखा दिया और पाठ्यक्रम में भी उचित परिवर्तन किये। सरकार ने समिति द्वारा दिये गये तमाम सुझाव मान कर उन्हें लागू कर दिया।

नगर-पालिकाओं के लिए मैं जो भी कार्य कर रहा था उसकी सरकार ने बड़ी उदारता से सराहना की। २८ जनवरी, १९०८ के दिन अहमदाबाद में, नगर-पालिका के मान-पत्र के उत्तर में, वम्बई के गवर्नर लॉर्ड सिडनहाम ने जो कुछ कहा उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहां उद्धृत करता हूं:

“यह ठीक है कि सरकार नगर-पालिकाओं के प्रति उदार है। परन्तु मैं समझता हूं कि नयी योजनाओं के बारे में इस बात की तसल्ली होनी जरूरी है कि वे हर दृष्टि से पूर्ण हों और जल-वितरण व्यवस्था के प्रबन्ध कार्य में किसी प्रकार का अपव्यय न हो। मेरा तो यह सुझाव है कि आप इस बारे में श्री विश्वेश्वरैया जैसे सुयोग्य इंजीनियर का परामर्श लें।”

सितम्बर, १९०४ में मुझे वम्बई विश्वविद्यालय का अधिसदस्य नामजद किया गया। इस बारे में सूचित करते हुए वम्बई के गवर्नर के निजी सचिव ने मुझे लिखा—“महामहिम गवर्नर आशा करते हैं कि आप विश्वविद्यालय के अधिनियम बनाने के महत्वपूर्ण काम में योग दे सकेंगे। ये अधिनियम नयी सिनेट के बनते ही उसके सामने रखे जायेंगे।”

## बम्बई राज्य में काम

बम्बई सरकार की सेवा में मैंने अपने जीवन के लगभग बीसह वर्ष पूना में ही बिताये। पूना में मेरा प्रवास, कई प्रकार से, मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। पूना बम्बई प्रेसीडेंसी के तीन प्रधान नगरों में से एक था। हमारे दो नगर बम्बई तथा महाबलेश्वर थे। महाबलेश्वर एक पर्वतीय स्थल है। समय-भ्रमण पर मुझे सरकारी काम से बम्बई और महाबलेश्वर भी जाना पड़ना था। बम्बई सरकार के सबसे बड़े यूरोपियन अधिकारी सहित गर्मी के दिनों में काम करने के लिए महाबलेश्वर चले जाते थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, १९०५ में मैं लगभग दस महीनों तक बम्बई सचिवालय में विशेष कार्य पर लगा रहा। फिर भी मैं समझता हूँ कि इतने दीर्घकाल तक पूना में रखकर मुझे एक प्रकार की सुविधा दी गई थी। जिन चार वर्षों तक मैं प्रान्तीय अधिकारी के पद पर रहा मुझे अपने काम के मिलमिले में—बम्बई प्रेसीडेंसी के सिध सहित अधिकार भागों में घूमने-फिरने के अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार के विविध अनुभवों द्वारा मुझे प्रान्त के सामान्य प्रवृत्ति के बारे में और सरकारी निकायों की राजनीतिक तथा सामाजिक गति-विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अवसर मिले। साधारणतः सरकारी नौकरी में इस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती।

मफाई इंजीनियर के अनिरिक्त और भी बहुत से विभागीय अध्यक्ष ऐसे थे जिनके प्रधान कार्यालय स्थायी रूप से पूना में ही थे।

इसके अनिरिक्त पूना बौद्धिक तथा शिक्षा-क्षेत्र भी था और बहुत से भारतीय अधिकारी नौकरी से अवकाश पाकर वहीं बस जाते थे। फ़रम्युमन कॉलेज के प्रोफ़ेसर, समाचार पत्रों के सम्पादक और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी राजनीति में विशेष रुचि रखते थे और इस बात के पक्षपाती थे कि हिन्दुस्तानियों को राजनीतिक सुविधाएँ तथा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के और अधिक अवसर मिलने चाहिएँ। उनमें श्री महादेव गोविंद रानाडे जैसे योग्य, विद्वान्, संतुलित विचारों वाले तथा सतर्क नेता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह सरकारी कर्मचारी होने के साथ-साथ पूना तथा महाराष्ट्र की अबुद्ध जनता के मित्र, दार्शनिक

तथा मार्ग-दर्शक माने जाते थे। वे केवल पूना और महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि सारे देश में, स्वतंत्र विचारों वाले राजनैतिक नेता प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज सुधार सम्बन्धी कई सम्मेलनों में भाग लिया और उनकी अध्यक्षता भी की, जिसमें राष्ट्रीय और सामाजिक सुधारों की मांग की जाती थी। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, उसी प्रकार श्री रानाडे श्री गोपालकृष्ण गोखले को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। श्री रानाडे महाराष्ट्र में छोटी-छोटी उद्योग प्रदर्शनियों को तथा उद्योग विकास को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। इसके अतिरिक्त बम्बई तथा भारत के अन्य भागों के राजा तथा उच्चकोटि के राजनीतिक नेता इनसे सदा परामर्श लेते रहते थे।

श्री गोपालकृष्ण गोखले पूना में बहुत दिनों तक फ़रग्यूसन कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहे और इस अवधि में उन्होंने कुछ वर्षों तक सार्वजनिक सभा के सचिव का पद संभाले रखा। बाद में इन्होंने 'सर्वेण्ट्स आफ़ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की जिसने भारत के कई योग्य, देशभक्त तथा निःस्वार्थ नेताओं को आकर्षित किया। सार्वजनिक सभा की पत्रिका दरअसल श्री रानाडे ने आरम्भ की थी और शिवराम हरि साठे नामक एक वयोवृद्ध सज्जन उसके नाममात्र के सचिव थे। पत्रिका में अंग्रेज़ी के बड़े महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है सचिव अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। श्री रानाडे ने देश के अनेक भागों से इस पत्रिका के लिए लेखकों की सेवाएं प्राप्त कीं, परन्तु इसका अधिक प्रचार प्रेजीडेंसी के महाराष्ट्र डिवीज़न में ही था।

सन् १८९३ में मुझसे भी इस पत्रिका के लिए एक लेख लिखकर भेजने को कहा गया। मैंने राष्ट्रीय उत्थान पर एक लेख लिखकर भेजा और श्री रानाडे ने उसे प्रकाशित कर दिया।

श्री बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज़ी नीति और प्रशासन की कटु आलोचना करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई वर्ष जेल में रहना पड़ा। जेल में उन्होंने अपने समय का सदुपयोग इतिहास तथा दर्शन पर पुस्तकें लिखकर किया। वे श्री रानाडे और गोखले जैसे नेताओं द्वारा अपनाये गये अंग्रेज़ी सरकार से निपटने के नम्र तरीकों का अवसर मज़ाक उड़ाया करते थे।

सन् १८९० के आस-पास पूना में ऐसे बहुत से शिक्षित लोग थे जो कि नमाज सुधारकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार थे। एक बार करीब ४२ ब्राह्मण

सज्जनों ने पूना की एक ईसाई मंथ्या के ग्योते पर उनके माथ चाय-मार्टी में भाग लिया, जिनके परिणामस्वरूप वहाँ के बट्टर ग्राहणों ने उनका बहिष्कार कर दिया। मराठी पत्रों में उनका नाम बेनालमि घर कर (दावत में भाग लेने वाले व्यक्तियों की गिनती व्यालीस थी) उनकी निन्दा भी की गई, परन्तु पूना की जनता को सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने में अधिक समय नहीं लगा।

### दक्षिण क्लब की स्थापना

अपने मित्रों के संग घूमने-फिरने तथा खेलों में भाग लेने हुए मुझे विचार आया कि पूना में अंग्रेजी तरीके के क्लब का होना जरूरी है। अपने पूना प्रवाग में मैं शुरू-शुरू के दिनों में स्थानीय गेल के मैदानों में खेलने के लिए जाता करता था और उन मभाजों में भी भाग लेता था जिनमें श्री रानाडे, गोखले तथा वहा के कुछ जागीरदार और बकील जाता करते थे। मैंने पूना के सब-जज स्व० श्री चिन्तामन राव भट्ट के माथ मिलकर १४ जुलाई, १८९१ के दिन पूना के प्रमुख व्यक्तियों को एक परिपत्र भेजा कि हम पूना में एक क्लब की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके सहयोग की आवश्यकता है। फिर हम श्री रानाडे के पास गये और उनके नामने अपना प्रस्ताव रखकर उनमें प्रार्थना की कि वह हमें 'हीरा बाग' नामक एक भुग्ना भवन, जिसका ऐतिहासिक महत्व था, क्लब के लिए ले दें। श्री रानाडे को हमारा प्रस्ताव अधिक नहीं जचा और वह बोले कि पूना निवासी काम का समय आम तौर पर पान-सुपारी की पाटियों में ही बिताते हैं अतः अंग्रेजी तरीके के क्लब के लिए अधिक सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना नहीं। दुर्भाग्यवश मेरे उत्साही मित्र श्री चिन्तामन राव की प्लेग से मृत्यु हो गयी। परन्तु चीफ़ ही पूना के गम्भीर रहनेवाले कुछ पारसी सज्जन भूझे सहयोग देने को तैयार हो गये और क्लब की स्थापना के काम में प्रगति होने लगी।

हम एक बार पुनः जाकर श्री रानाडे से मिले और उन्होंने हीराबाग कमेटी पर अपना प्रभाव डालकर वह भवन हमें क्लब के लिए ले दिया। हमने क्लब के उद्देश्य और उमे चलाने के लिए अनुमानित खर्च का विवरण देकर परिपत्र छपवाए और उन्हें गहर में चटवाया। पूना निवासी दो सज्जन—नारायण भाई ढांडेकर जो धरार के अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक थे, तथा एक पारसी सज्जन सा बहादुर

दिनशा डी० खम्माटा जो पूना में सैनिक सेवाओं से सम्बन्धित थे, क्लब में सम्मिलित होकर मेरे साथ सचिव के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो गये। इसके पश्चात् हमने १७ नवम्बर, १८९१ के दिन क्लब का उद्घाटन करने का निश्चय किया और इसकी सूचना शहर के प्रमुख व्यक्तियों को देकर कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने लगे।

इस अवसर के लिए हमने हीरा बाग भवन की मरम्मत कराई। निश्चित समय पर क्लब की बैठक आरम्भ हुई और केवल दस व्यक्ति इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। यह देखकर भुझे बड़ी निराशा हुई। परन्तु आधे घण्टे के अन्दर-अन्दर पूना के लगभग २५ व्यक्ति (प्रतिष्ठित व्यक्ति) आ पहुंचे और होते-होते यह संख्या ७५ तक पहुंच गयी। उन दिनों आमतौर पर लोग सभाओं में निश्चित समय पर नहीं पहुंचा करते थे और जब तक उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो जाए, कि कोई प्रसिद्ध प्रवक्ता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहा है, वे वहां नहीं जाया करते थे।

सभा की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त ज़िलाधीश सरदार राव बहादुर गोपाल राव हरि देशमुख ने की तथा कई प्रमुख व्यक्तियों के भाषण हुए जिनमें बड़ीदा के अवकाश प्राप्त दीवान खां बहादुर खाजी शहाबुद्दीन तथा श्री रानाडे भी थे।

“श्री रानाडे ने अपने भाषण में कहा कि जब एक बार पहले पूना में एक क्लब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था तो हमारे कुछ मित्र जनों ने समझा कि यह-उन व्यक्तियों की एक चाल मात्र है जो दूसरे लोगों द्वारा धर्म विरुद्ध काम करवाकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। फिर उन्होंने अन्य क्लबों के नामों का उल्लेख किया जिन्हें शुरू करने की तजवीजें पहले भी हो चुकी थीं। उन्होंने कहा—“इन सब क्लबों की विशेषता यह थी कि उन्हें देशी रूप दिया गया था, हालांकि क्लब एक यूरोपियन संस्था है। अब जिस क्लब की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसका पूरा-पूरा स्वागत होना चाहिए।”

हीरा बाग भवन के सम्बन्ध में श्री रानाडे ने कहा :

“हम एक ऐतिहासिक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। मन् १७६८ में जब प्रथम पेशवा मरिगावटम के स्थान पर हैदर ने युद्ध कर रहे थे तब उन्हें अपना

एक वचन याद आया। इस वचन में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह उसके लिए किसी सुन्दर बाग में एक भवन बनवा देगे, ताकि जब वह दूर देश के अभियान पर गये हुए हों तो वह उसमें विश्राम कर सकें। सेंटिगपटम में उन्हें अपना वचन याद आया और उन्होंने अपने मन्त्री को लिखकर हीरा बाग भवन बनवा दिया। इस भवन का निर्माण और उद्घाटन की राजावट एक राजा ने रानी के लिए किया था मो, यह हमारा सीभाग्य है कि क्लब के लिए हमें यह जगह मिली। परन्तु यहां क्लब को स्थायी रूप से नहीं रखा जायगा। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही हमने अच्छी जगह की व्यवस्था कर लेंगे।” इससे पश्चात् श्री रानाडे ने क्लब के अवैतनिक सचिवों के प्रति आभार प्रकट किया और श्री विश्वेश्वरैया द्वारा किये गये कार्य की विशेष रूप से सराहना की।”

(दी डेली टेलीग्राफ तथा डेक्कन हेराल्ड, पूना, १९ नवम्बर, सन् १८९१) पूना के प्रमुख व्यापारी सरदार दोराबजी पदमजी क्लब के सभापति चुने गये और श्री रानाडे तथा श्री गोखले व्यवस्थापिका समिति के सदस्य बनाये गये।

सन् १८९४ में मक्यर तबदील हो जाने तक मैं एक सचिव के रूप में काम-काज की देख-भाल करता रहा। जब क्लब के सदस्यों को पता चला कि मेरी तबदीली मक्खर में हो गयी है तो उन्होंने मुझे दावत दी और क्लब के प्रति की गयी मेरी मराठनीय सेवाओं के बदले में मुझे एक एल्बम भेंट की जिसमें सब सदस्यों के चित्र लगे हुए थे।

क्लब १८९१ में शुरू किया गया था और ५० वर्ष बाद नवम्बर, १९४१ में उसकी स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी। क्लब का अवैतनिक सदस्य होने के नाते मुझे की अध्यक्षता करने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। इस अवसर पर पूना के समारोह प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। यह क्लब आज भी विद्यमान है और गत ६० वर्षों से पूना निवासियों का मन बहलावा कर रहा है। यह आज भी उसी हीरा बाग भवन में है जहां इसका उद्घाटन हुआ था।

सन् १८९८ में मैं अपनी जापान यात्रा के पश्चात् बम्बई लौटा। एक शाम श्री रानाडे ने, जो तब तक हाईकोर्ट के जज हो गये थे, अपने साथ खाने पर बुलाया। हम मुख्यतः जापान में हुई प्रगति के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। मेरे विदा होते समय श्री रानाडे अपने मकान के एक कमरे की ओर इशारा करके मुझे बताने लगे



कि उनके एक मित्र श्री वामन आवा रावजी मोदक, जो एक सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, वहां बीमार पड़े हैं। उनके ठीक-ठीक शब्द ये थे—“क्या आप जानते हैं कि उस कमरे में मेरा एक मित्र एक ऐसे रोग से बीमार पड़ा है जिससे सारा भारत पीड़ित है। अधिक पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री मोदक को लकवा हो गया है।

पूना में हर साल एक दरबार लगता था, जिसकी अध्यक्षता एक यूरोपीय अधिकारी महाराष्ट्र के डिवीजनल जज किया करते थे। इस दरबार में दो तरह के लोग बुलाए जाते थे—एक जागीरदार व सरदार और दूसरे सरकारी अफसर। एक बार दरबार के अफसर पर सरकारी अफसर बायीं पंक्ति में बैठे हुए थे और जागीरदार दायीं ओर। मैं बायीं पंक्ति में श्री रानाडे के साथ सबसे आगे बैठा था। हमें वहां काफ़ी देर तक निठल्ले बैठना पड़ता था। श्री रानाडे मुझे सामने बैठे हुए कुछ सरदारों व जागीरदारों का इतिहास—उनके स्वभाव की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताने लगे। जब वे मुझे करीब आघे दर्जन जागीरदारों के विचित्र स्वभावों के किस्से सुना चुके तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन लोगों के पास अक्सर आते जाते रहते हैं। वह बोले—“मैं उनके यहां कभी नहीं जाता। परन्तु सरकारी मामलों में किसी प्रकार की मुश्किल आ पड़ने पर या अपनी जागीर में कोई समस्या खड़ी हो जाने पर वे परामर्श लेने के लिए मेरे पास आते रहते हैं।” यह श्री रानाडे की बड़ी भारी विशेषता थी कि वह महाराष्ट्रवासियों के प्रिय नेता, मित्र तथा मार्गदर्शक थे। उनमें आत्मसंयम, योग्यता और देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह भारत के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे और यह बात बिल्कुल ठीक थी।

हालांकि मैं सज़ाई इंजीनियर के पद को संभाले हुए था, फिर भी समय-समय पर मुझे इसके अलावा दूसरे काम सौंप दिये जाते थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर डिवीजन छः महीनों तक मेरे अधीन रहे। सन् १९०७ में मुझे दो बड़ी रियासतों से मुख्य इंजीनियर के पद के लिए बुलावा आया। जब मैंने अपने महकमे के उच्चाधिकारियों को इसके बारे में बताया तो वे बोले कि वे मेरे बम्बई सरकार की नौकरी छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा। विशेष कार्यों के लिए नियुक्ति होने के कारण मैं कई वर्षों तक अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जितनी

गिनती एक बार १८ तक पहुँच गयी थी, आगे निकल जाता रहा। सरकार ने दो तीन अधिकारियों के पद हटाकर उन्हें पहले वाले पद पर लगा दिया और मुझे यह ज्ञान हुआ कि मुझे दूसरों से पहले तरक्की दिये जाने के कारण बड़ा असंतोष फैला हुआ है। उस समय देश में राजनीतिक घेतना की लहर दौड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी अपनी बारी न आ जाए, मेरे लिए मुख्य इंजीनियर के पद की प्राप्ति करना अशुभव है। तब मैंने बम्बई सरकार की नौकरी से अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया और अवकाश के पूर्व छुट्टी के लिए प्रार्थनापत्र दे दिया। जब इस बात की खबर सरकारी क्षेत्रों में पहुँची तो बड़ा आश्चर्य किया गया। लोग हैरान थे कि जब मुझे दूसरों से पहले तरक्की दी जा रही है तो मैं इस प्रकार का कदम क्यों उठा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे कुछ ऐसे हितैषी मित्र उच्च अधिकारियों गृह भी मेरी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे और फिर मेरी नौकरी अभी इतनी नहीं हुई थी जो मैं पेंशन पाने का अधिकारी होता। मेरे कुछ मित्रों को यह डर था कि मुझे पेंशन मिलेगी ही नहीं। परन्तु अन्त में बम्बई सरकार ने भारत सरकार से अपने ६ मार्च, १९६० के पत्र, सख्या १०८६, द्वारा मुझे पेंशन देने की मिकारिद करके हुए लिखा कि :

“महामहिम गवर्नर श्री विस्वेस्वरैया द्वारा की गयी अत्यंत सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन पाने का पूर्ण अधिकार देते हैं।”

बम्बई के गवर्नर लॉर्ड मिडनहाम द्वारा मुझे लिखे गये एक पत्र से यह पता चलता है कि बम्बई सरकार ने मेरी नौकरी के अन्तिम दिन तक मेरी सेवाओं की प्रशंसा की है।

पत्र का अंग कुछ इस प्रकार है

“यदि आप सरकारी नौकरी में रहते और मैं भारत में रहता तो मुझे आशा है कि मैं आपकी मूल्यवान् सेवाओं की पूरी-पूरी कीमत चुकाने में अवश्य सफल होता। आप तरक्की पाकर अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों से आगे निकल गये। मुझे आशा है कि आप इस बात को मानते होंगे कि आपके साथ विशेष उदारता का सलूक किया गया।

आप जो कुछ भी करने का निश्चय करें, मेरी तो यह हार्दिक अभिलाषा है कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर एक दिन उन्नति के क्षिप

पर पहुँचेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी में जो अनुभव प्राप्त हुए वह अत्यंत सुखद थे।"

इस प्रकार बम्बई राज्य में मेरी सरकारी नौकरी के अध्याय की समाप्ति होती है।

## हैदराबाद (दक्षिण) में विशेष सलाहकार इंजीनियर के पद पर

मूसी नदी हैदराबाद नगर के बीचो-बीच होकर गुजरती है और नगर को दो हिस्सों में बांट देती है। २८ सितम्बर, १९०८ के दिन यह नगर घोर वर्षा और तूफान की लपेट में आ गया। हैदराबाद के निकट रामगढ़ाबाद में, जो कि स्रवण क्षेत्र के प्रमुख वर्षा भागों के केन्द्रों में से एक था, उस दिन २४ घंटों में १२' ८ इंच और ४८ घंटों में १८' ९० इंच वर्षा हुई। इस वर्षा से इतनी विनाशकारी बाढ़ आयी, जिसकी मिसाल पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों में भी नहीं मिलती थी। नदी का उत्तरी किनारा दक्षिणी किनारे में अपेक्षाकृत नीचा था। नदी के स्रवण क्षेत्र में शहर में ऊपर लगभग ८६० वर्ग मील भूमि में ७८८ छोटे-छोटे तालाब थे, यानी स्रवण क्षेत्र की एक वर्ग मील भूमि में लगभग एक तालाब पड़ता था। मूसी नदी की बाढ़ी में, जहाँ बाढ़ आयी थी, दो स्रवण क्षेत्र थे, जिनमें से एक २८५ वर्ग मील और दूसरा ५२५ वर्ग मील था। नदी में पानी की सतह के निगानों से पता चला कि बाढ़ के कारण नदी में पानी का निकास ११०,००० क्यूमेक्स से शुरू होकर ४२५,००० क्यूमेक्स तक गया। नतीजा यह हुआ कि नदी की बाढ़ी में कोई भी तालाब टूटने से न बच सका। कुल मिलाकर २२१ तालाबों के टूटने की खबर मिली, जिनमें से १८२ ईमी अपवाह क्षेत्र में थे और ३८ मूसी में।

बाढ़ से जो हानि हुई उसकी जांच करने तथा भविष्य में इस प्रकार की तबाही को रोकने के लिए जो कदम उठाने जरूरी थे, उसके बारे में सलाह देने के लिए हैदराबाद सरकार को एक इंजीनियर की जरूरत पड़ी।

अवकाश ग्रहण करने से पूर्व जब मैं छुट्टी लेकर विदेश यात्रा कर रहा था तो इटली में मिलान नामक स्थान पर मुझे लंदन स्थित भारतीय न्यायिक के उप-सचिव की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में बम्बई के गवर्नर की ओर से प्राप्त एक तार की संक्षिप्त अंतिम थी और यह भी लिखा था कि पत्र का उत्तर शीघ्र दिया जाय। उत्तर में लिखा था :

“निजाम सरकार हैदराबाद का पुनर्निर्माण करने तथा अन्ध विचारों को जड़ता से खारज करने के लिए मुसलमानों के अजीबपन को मिटो देना था, जो मुझ पर है, मेवान् प्राप्त करना चाहती है। तथा आप का क्या होगा कि वह हमें काम के लिए तुरन्त भर्ती करवाते हैं? यह काम बहुत बड़ा है।”

श्री अहमदी ने, जो हैदराबाद के सर अकबर हैदरी के निकट सम्बन्धी थे मुझे कतारन भेजते हुए लिखा :

“मैं हैदराबाद में आपकी नियुक्ति के बारे में पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता इस बात पर हुई कि उन्होंने एक भारतीय को इस पद के उपयुक्त समझकर उसे इस पर नियुक्त किया।”

हैदराबाद में मुझे तीन विशेष कार्य करने थे।

१. हैदराबाद नगर का पुनर्निर्माण करने के बारे में मुझाव देना।
२. भविष्य में नगर को बाढ़ों के प्रकोप में बचाने के लिए कोई व्यवस्था करना।
३. हैदराबाद नगर और चन्द्रघाट के लिए एक जल-निकास योजना तैयार करना।

१५ अप्रैल, १९०९ के दिन हैदराबाद पहुँचकर मैंने दो बड़ी योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए कर्मचारियों की सलाह शुरू की। हैदराबाद सरकार बाढ़ से नगर के बचाव के कार्य को तथा नगर के लिए एक आधुनिक जल-निकास योजना तैयार करने के काम को बहुत महत्व देती थी। इन दोनों योजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य करके अनुमानित व्यय विवरण तैयार करना आवश्यक था। नगर में पक्की सड़कें बनाने तथा अन्य छोटे-छोटे कामों की व्यवस्था बाद में की गयी थी।

इसमें सन्देह नहीं कि हैदराबाद में १९०८ की बाढ़ वर्षा के कारण ही आयी थी। परन्तु यदि इसके साथ नदी के सवन क्षेत्र के अनेक तालाब न टूट जाते तो यह बाढ़ इतना भीषण रूप धारण न करती और शहर नष्ट होने से बच जाता।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सोमवार, २८ नवम्बर, १९०८ के दिन बाढ़ आयी और दोपहर होते-होते वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। आधी रात के समय बड़े जोर की वर्षा होने लगी। नतीजा यह हुआ कि तालाबों में लबालब पानी भर गया और वे एक-एक करके टूटने लगे। फिर तो बाढ़ के पानी ने शहर में जो प्रलय मचायो उसकी भिमांल मिलनी मुश्किल है। कहा जाता है कि कोलगावाड़ी नामक मुहल्ले में ही लगभग दो हजार व्यक्ति बह गये थे।

सर्वेक्षण तथा जाँच कार्य को पूरा करने के लिए कुछ इंजीनियर तथा बहुत



मे श्री एलन ने हैदराबाद सरकार के लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री एफ० मूरज को जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है -

“मैं हैदराबाद सरकार को एक तो इस बात पर बधाई देता हूँ कि वह एक बहुत बड़ी विपत्ति को एक वरदान में बदलने का प्रयास कर रही है और दूसरी इस बात पर कि इस काम के लिए उन्होंने जिसको चुना है, वह भारत के योग्यतम इंजीनियरों में से हैं। मैं समझता हूँ कि अधिक वाद-विवाद न कर के सीधे ही इस योजना के अनुसार कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। जहां तक नक्शों का संबंध है, मैं समझता हूँ कि एक योग्य इंजीनियर द्वारा तैयार किये गये नक्शे ऐसे ही होने चाहिए।”

मार्च, १९१३ मे, यानी मेरे हैदराबाद छोड़कर चले जाने के सठ्ठे तीन वर्ष बाद, हैदराबाद सरकार ने मूसी जलाशय का निर्माण आरम्भ किया। जब जलाशय के बांध का शिलान्यास किया गया तो रियासत के लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष श्री टी० डी० मैकेंडी ने महामहिम निज़ाम को मान-पत्र भेंट करते समय अन्य बातों के साथ यह भी कहा :

“स्वर्गीय महामहिम निज़ाम के सलाहकार बवाब के सरीको की योजना बनानेवाले कार्याधिकारी के चुनाव मे भी भाग्यशाली रहे। उन्होंने श्री विश्वेश्वरैया को चुना, जिनकी गिनती भारत के योग्यतम इंजीनियरों मे होती है। वह जीवन के किसी भी क्षेत्र मे अपना नाम पैदा कर सकते हैं। और आज वे मैसूर के दीवान के रूप मे बड़ा ही मराहनीय काम कर रहे हैं। श्री विश्वेश्वरैया को श्री अहमद अली द्वारा जो सहायता प्राप्त हुई, उसके लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट मे उनके प्रति बड़ा आभार प्रकट किया है।”

(टाइम्स आफ इण्डिया, २४ मार्च, १९१३)

इसी जलाशय के निर्माण का कार्य बाद मे आरंभ हुआ। इसके लिए मैंने श्री सी० टी० दलाल नामक एक बहुत ही सुयोग्य भारतीय इंजीनियर की सेवाए प्राप्त कर ली। श्री दलाल अवकाश प्राप्त एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और मैसूर के लोक-निर्माण विभाग मे बांध बनाने के काम में काफ़ी नाम कमा चुके थे।

मार्च १९०८ मे मूसी बांध के निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनेवाले अधिकारी थे, श्री अहमद अली, जिनका उल्लेख श्री टी० डी० मैकेंडी ने किया है। इस कार्य से संबंधित मेरे अधीन काम करनेवाले लोगों में वह निम्नदेह सबसे योग्य



अधिकारी थे। वह अपनी कार्य-कुशलता के बल पर, बाद में, हैदराबाद के मुख्य इंजीनियर हो गये और उन्हें नवाब अली नवाजजंग की उपाधि भी दी गयी। सन् १९२९ में बम्बई सरकार द्वारा स्थापित एक समिति में उन्हें ही मेरे साथ एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह समिति सिंध नदी पर बने सक्कर बांध सम्बन्धी कुछ समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी थी। इस समिति को लॉयड बांध व नहर निर्माण कार्य (सक्कर) के नाम से भी पुकारा जाता था।

ईसी बांध के निर्माण का कुछ काम श्री सी० टी० दलाल ने पूरा किया और शेष काम श्री क्लेमेंट टी० मुलिंग्स, जिन्हें बाद में सर की उपाधि मिली, ने किया। श्री मुलिंग्स वही इंजीनियर थे जिन्हें मद्रास में मेट्टूर बांध बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ था।

### हैदराबाद में जल-निकास योजना

हैदराबाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपा गया, वह था, हैदराबाद नगर के लिए एक आधुनिक मलमार्ग का निर्माण करना।

जैसा कि बताया जा चुका है, मूसी नदी हैदराबाद नगर के बीच में से होकर गुजरती है और नदी के दोनों ओर का गन्दा जल नालियों द्वारा नदी में बहा दिया जाता था। इस प्रकार कभी-कभी, विशेषकर गर्मी के मौसम में, मूसी नदी स्वयं एक गन्दे नाले में बदल जाती थी।

शहर में जहां कहीं आवादी अधिक थी और गलियां तंग थीं, लोग गन्दे जल के निकास के लिए अपने घरों के सामने गढ़े खोद लिया करते थे। कभी कभी तो इन गढ़ों के ऊपर तक भर जाने से गन्दा जल बाहर बहने लगता था और कभी-कभी यह सूख जाते। गन्दगी के इन गढ़ों में मच्छर पलते रहते। उन दिनों यह कहा जाता था कि यदि कोई परदेशी शहर में पहली बार आये और लोगों की इस आदत से अनभिज्ञ हो तो वह यही समझेगा कि शहरवालों ने मच्छर पालने का धंधा शुरू कर रखा है।

सबसे पहला काम यह किया गया कि नदी के दोनों ओर की गन्दी नालियों के पानी को पाइप द्वारा एक अलग खाद बनाने के फार्म में ले जाया गया। यह फार्म

नगर के पूर्व में नदी के बायें किनारे पर बनाया गया था। नदी के दक्षिणी किनारे का मल एक पाइप द्वारा चन्द्रघाट पुल के नीचे से नदी के पार ले जाकर उस फार्म में पहुँचा दिया गया।

मैने हैदराबाद सरकार से यह तय कर रखा था कि मैं बाढ़ नियन्त्रण की तथा आधुनिक मलमार्ग निर्माण की योजनाएं तैयार करके दूँगा। यह दोनों योजनाएं तैयार करके व्यय विवरण तथा नक्शों सहित मैने हैदराबाद छाँडने से पूर्व सरकार को पेश कर दी। बाढ़ नियन्त्रण योजना की रिपोर्ट १ अक्तूबर, १९०९ के दिन और दोनों नदियों पर जलाशय के निर्माण की योजना २० अक्तूबर, १९०९ को पेश की गयी।

नगर में मलमार्ग निर्माण की योजना ६ नवम्बर, १९०९ के दिन पेश की गयी। इस योजना के अन्तर्गत नगर की भारी गन्दी वस्तियाँ को, जो नगर के लिए एक बुराई बनी हुई थी, रखा गया था। भूकें सरकार सारे नगर में मलमार्ग निर्माण एक ही साथ नहीं करना चाहती थी, इसलिए नगर के बहुत से भागों का काम बाढ़ के व्योरेवार सर्वेक्षण पर छोड़ दिया गया। अंग्रेजी रेजीडेंट के कहने पर ४ जुलाई, १९०९ के दिन मैने उन्हें सिकन्दराबाद छावनी में जल-निकास सम्बन्धी एक रिपोर्ट तैयार करके दी, अपने १८ अक्तूबर, १९०९ के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा :

“छावनी की जल-निकास सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करके देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह रिपोर्ट छावनी के अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और इस पर शीघ्र ही काम शुरू किया जायगा।”

नवम्बर, १९०९ में मैने हैदराबाद सरकार की नोकरी छोड़ी। इसके पश्चात् १३ वर्षों तक उस नगर के इंजीनियरिंग सम्बन्धी कामों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा। सन् १९२२ में मुझे हैदराबाद की जल-निकास योजना के बारे में सलाह देने के लिए एक बार फिर बुलाया गया, क्योंकि योजना के काम में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। इस काम के लिए मुझे छ-सात बार हैदराबाद जाना पड़ा।

जल-निकास योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य में खाद फार्म बनाने और नदी के दोनों ओर के गन्दे पानी को पाइपों द्वारा खाद फार्म तक पहुँचाने का काम ही सबसे जरूरी था। गली-कूचों और घरों के साथ मिट्टी बालियों के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

जिन दिनों मुझे पुनः हैदराबाद बुलाया गया, उन दिनों जल-निकास योजना

सामान्य में बहुत से नाशन और जलशयन थे, परन्तु उनमें से भी-बचत बहुत छोटी  
 थी। रियासत की उमरी घोंघा घर, सार्वजनिक स्थान घर, आधे बरत कर मुक्त बहुत  
 बड़े जलशयन का निर्माण किया गया। इस जलशयन का पानी मिचार्ड के लिए  
 इस्तेमाल किया जा रहा था। पता चला कि रियासत पानी का न तो माप कर प्रयोग  
 करते थे, न हाथ रोक कर खर्च करते थे। पैसा करने में न केवल ये कामचला को लाभ  
 पहुँचाने में अग्रगण्य रहे, बल्कि उस क्षेत्र में मलिनिया भी फैल गया। जब मैंने इस  
 बारे में सुना तो मैंने मिचार्ड की सख्त प्रणाली को, जिसमें मैंने 'भारतीय मिचार्ड  
 आयोग १९०१-०३' के छपने के साथ ही बम्बई प्रांत में लागू किया था, यहाँ भी लागू  
 करने का प्रयास किया। परन्तु यहाँ भी, जैसा कि पूना में हुआ था, किसानों ने  
 इस प्रणाली का विरोध किया और रियासत के जिला अधिकारियों ने भी उन्हीं  
 का साथ दिया। चूँकि यहाँ लोग मनचाहे तरीके से पानी प्राप्त करने के पक्ष में  
 थे और किसानों तथा असैनिक अधिकारियों का विरोध करना आसान काम नहीं  
 था, विशेषकर जब मैं रियासत की प्रशासन व्यवस्था में बिल्कुल नया था, इस सुधार  
 को सस्ती से लागू न किया जा सका। मुझे सन्देह है कि पानी देने की इस अव्यवस्थित  
 प्रणाली की ओर जिम्मेवार अधिकारियों ने अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

इस पद को स्वीकार करने के पूर्व मैंने जिन दो बातों पर जोर दिया था, अर्थात् तननीकी प्रशिक्षण और उद्योग, महाराज ने उनके विकास को प्रोत्साहन दिया। सरकार ने दोनों के लिए अलग-अलग समिति नियुक्त की। तकनीकी शिक्षा के लिए यनायी राशी समिति में रियासती शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल श्री जे० बीर तथा तीन अन्य भारतीय अफसर थे। मुझे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

सितम्बर, १९१२ में हमने एक रिपोर्ट तैयार कर के सरकार को पेश कर दी।

### आर्थिक सम्मेलन

राज्य के उद्योग और आर्थिक समस्याओं के लिए महाराज ने, मेरे मुताबक पर, मैसूर राज्य के उच्च अधिकारियों और प्रमुख ग्रैंड सरकारी व्यक्तियों का एक आर्थिक सम्मेलन स्थापित करने का निर्णय किया जिसमें अत्यन्त आवश्यक मामलों पर विचार किया जाय और उनकी उत्पत्ति का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। इस सम्मेलन का उद्घाटन महाराज ने १० जून, १९११ को स्वयं किया। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया, उक्त भाषण इस प्रकार है:

"आर्थिक कुराहों का सबसे बड़ा इलाज शिक्षा है। इधर कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने जनता की बुद्धि के विकास तथा शिक्षा प्रसार के लिए पर्याप्त में अधिक अनुदान देकर, तथा अन्य प्रकार से, बहुत कुछ किया है और पर्याप्त में अधिक अनुदान भी दिये हैं। शिक्षा के महात्व को महसूस देने के लिए हमने इस विषय को अपने कार्यक्रम में सबसे पहले रखा है।"

"रियासती की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच करने का अभिप्राय होगा अज्ञान, कमीशनी, बीमारों और अशक्त-मृत्यु के कारणों की जांच करना। ये महामुद्दे हर देश में और हर जगह में बोड़े-बहुत विद्यमान रहते हैं। परन्तु हमारा इरादा यह होना चाहिये कि हम उन्हें जितना हो सके, उन्ना कम कर दें। समय बदल रहा है। अन्धकार भाषणों की प्रवृत्ति में दुरी को नाश कर दिया है। जिसमें दृष्टि तथा अन्य उद्योग-पेशों में प्रतिस्पर्धा का दर्जा है। उद्योगों परिरक्षणी और जनमानसों का है।

यों में लगाने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, परन्तु उनकी सर्वोत्तम अभिरक्षा करने के लिये, काम उद्देश्य के सिद्धि प्राप्त करने तथा व्यय में न्यून निकाशों के कारगराने स्थापित करने जैसे कुछ विशेष उद्देश्य-बन्धों तक ही सीमित थी। उन्होंने लोहा और हथौड़ी मशीनें आदि विपणन करने के उद्देश्यों में, जिनका प्रसारण की प्रवृत्ति थी, निरन्तरता नहीं दी।

## रेल विभाग

यहां यह बताना देना समझ होगा कि लोक-निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर के रूप में काम करते समय में रेल विभाग का मन्त्रि भी था। रेल विभाग का कार्य पिछले १५ वर्षों में ठण पड़ा था। तब तक रियासत की रेल व्यवस्था मद्रास तथा दक्षिण मराठा रेलवे कम्पनी के अधीन थी। रियासत में रेलों के विस्तार के

लिए यह जरूरी था कि मैसूर सरकार रेल व्यवस्था को अपने अधिकार में ले ले। तब मैसूर सरकार ने रेल व्यवस्था को अपने अधिकार में लेने तथा रेलों का विस्तार करने के लिए कार्य-यत्न तैयार किया।

## कावेरी जलाशय (कृष्णराज सागर)

मेरा अगला महत्वपूर्ण काम कावेरी नदी के आर-पार एक बांध निर्माण का था। सन् १९०२ में शिव भुद्रम् प्रपात पर, कावेरी के जोरदार बहाव द्वारा विजली पैदा कर, के एक विजली घर का निर्माण किया गया था। इस विजली घर में १३,००० हार्म पावर विजली तैयार की जा रही थी जिसमें से ११,००० हार्मपावर विजली महा से करीब ९० मील दूर कोन्नर की सोना खानों में दी जाती थी। शिवभुद्रम् की बिया जानेवाला पानी घटता-बढ़ता रहता था। धीरे-धीरे पट्टम में लगभग दस मील पश्चिम में, नम्रमवाडी नामक गाँव में, एक जलाशय बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया था, जिसका व्यावहारिक दृष्टि से कोई महत्व था। पानी को कावेरी घाटी में, बड़े पैमाने पर, विजली-उत्पादन तथा सिंचाई दोनों के लिए इस्तेमाल करने की दृष्टि से, एक विभाग जलाशय के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम फिर से शुरू किया गया। क्योंकि मैंने शिव के अगवान बांध जैसे-बड़े बड़े बांध देने में और बम्बई प्रेजिडेंसी के हैदराबाद इलाके में बड़े बड़े जलाशयों के नक्शे बनाने के सिलसिले में भी काम किया था, इसलिए मैसूर की कावेरी घाटी की जलधाराओं के लिए उपयुक्त सिंचाई तथा विजली-उत्पादन की एक संपूर्ण परियोजना तथा नक्शे तैयार करने में मुझे अधिक समय नहीं लगा।

शिव भुद्रम् विजलीघर का निर्माण उस काल में, जब सर के० शैपाट्रिअम्यर मैसूर के दीवान थे, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता से मेजर ए० सी० डि० एण्ट विनिमर, आर० ई०, जो उस समय राज्य के सुपरिटेण्डिंग इंजीनियर थे, की देख-रेख में हुआ।

कोन्नर की सोना खानों के व्यवस्थापक एजेंटों ने देखा कि खानों में दी जाने-वाली विजली काफी नहीं थी। गर्मियों में नदी में पानी कम हो जाने के कारण विजली और भी कम हो जाती थी। मैं विजली-विभाग में सरकारी सचिव भी

था, इसलिए मैंने व्यवस्थापक एजेंटों के प्रतिनिधि जान टेलर एण्ड सन्ज के साथ इस समस्या पर बातचीत की।

रियासत के बिजली विभाग के मुख्य बिजली-इंजीनियर श्री एच० पी० गिन्स भी इस बातचीत में शरीक हुए। बातचीत के बाद जलाशय के आकार और निर्माण की अवस्थाएं निश्चित की गयीं, ताकि शिवसमुद्रम् बिजलीघर को आवश्यक जल मिल सके तथा कावेरी घाटी के उन क्षेत्रों की सिंचाई हो सके जो रियासत के अंतर्गत आते थे।

१२४ फुट ऊंचा पक्का बांध बना कर, ४८,०० घन फुट पानी जमा करने की योजना बनायी गयी। इस भूमि से १५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होनी थी। और ८०,००० हार्स पावर बिजली पैदा की जानी थी। यह बिजली कोलार की सोना खानों के अतिरिक्त नदी की वादी में बसे शहरों और कस्बों में घरेलू इस्तेमाल और कारखानों के लिए भी चाहिए थी।

नदी पर जलाशय के लिए ऐसा बांध बनाने की योजना थी, जो नदीतल से १३० फुट ऊंचा तथा निम्नतम नींव से १४० फुट ऊंचा हो, लम्बाई ८,६०० फुट हो तथा नींव के पास तले की चौड़ाई १११ फुट हो।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है जलाशय के निर्माण से पूर्व १३,००० हार्स पावर बिजली पैदा की जाती थी, जिसमें से कोलार की सोना खानों के लिए ११,००० हार्स पावर बिजली दी जाती थी। खानों के मैनेजिंग एजेंट, जान टेलर एण्ड सन्ज ने, पांच वर्षों के लिए, ५,००० हार्स पावर बिजली की और मांग की और उस के बाद, १०,००० हार्स पावर बिजली की मांग की, शुरू में जलाशय के अन्दर जो पानी जमा किया गया वह शिवसमुद्रम् में २०,००० हार्स पावर बिजली, जिसमें पहले दी जा रही बिजली भी शामिल थी, पैदा करने के लिए काफी था। शिवसमुद्रम् प्रपात से कुछ ही नीचे, शिमशा नामक स्थान पर भी बिजली पैदा करने की एक बढ़िया तजवीज थी। अनुमान था कि दोनों बिजली घरों के तैयार हो जाने पर ८०,००० हार्स पावर बिजली पैदा की जा सकेगी। अब इतनी बिजली की पूरी खपत हो रही है।

यहां यह बता देना आवश्यक होगा कि जलाशय के निर्माण की योजना तो तैयार हो गयी, पर कुछ समय तक महाराज की ओर से इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति नहीं आयी। अनुमान था कि यह योजना २५३ लाख रुपये की

लागत से तैयार होगी। भायद रियासत के कुछ अधिकारियों ने महाराज पर दबाव डाल कर उन्हें इतनी बड़ी रकम खर्च करने से मना कर दिया। रियामन की ओर से इतनी बड़ी रकम पहले किसी एक परियोजना पर खर्च नहीं की गयी थी। परन्तु रियासत के दीवान श्री टी० आनन्दराव इस तजवीज का पूरा-पूरा समर्थन कर रहे थे। जब मुझे लगा कि मैं महाराज को सहमत नहीं कर सकता, तो मैंने रियामन की मौफरी से अवकाश ग्रहण करने की छान ली। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उत्तर भारत की ओर घूमने चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि योजना के निर्माण का काम तब भी ठंडा पड़ा था और उसमें कोई गति नहीं आयी थी। यह सब देख कर मैंने मौन भाग लिया और कुछ समय तक अपने दफ्तर के काम के बिना किमी और बात की ओर ध्यान देना बन्द कर दिया।

मेरे इस बदले हुए व्यवहार को देख कर महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया। उन दिनों वे बगलौर में ठहरे हुए थे। जब मैं उनके पास पहुँचा तो पूछने लगे कि पहले की भांति मैं नये विकास कार्यों में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। मैंने महाराज से सही बात माफ-माफ कह दी कि विकास कार्यों के लिये दी गयी सुविधाओं से मुझे काफी क्षमन्तोष हुआ है। मुझे कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। चूंकि रियामन में अब कोई ऐसा काम रहा ही नहीं जिसके प्रति उत्साह दिनाया जा सके, अतः मैं मौफरी छोड़ कर जाना चाहता हूँ। महाराज बोले-

"आप जल्दी मत करें। जो आप चाहते हैं, तो हो जायगा।" फिर वह बोले कि अगले सप्ताह मुझसे मैसूर में मिलना। वहाँ उन्होंने हर एक तजवीज की पूरी-पूरी जांच करने के पश्चात् मेरे द्वारा पेश की गयी भारी तजवीजों की मजूरी दे दी। इन सब में जलाशय के निर्माण की योजना सब से अधिक महत्वपूर्ण थी। मैं नहीं जानता कि इस योजना के बारे में महाराज ने बाहर के किसी इंजीनियर से परामर्श किया था या नहीं। परन्तु इससे मेरा यह मतलब हल हो गया कि जो योजना मैंने सरकार को पेश की थी वह, बिना किमी जोड़-नोड़ या परिवर्तन के, मजूर कर ली गयी।

जलाशय के निर्माण में अगली कठिनाई मद्रास सरकार के साथ पेश आती। मद्रास सरकार इसी नदी पर, कन्नमवाड़ी से लगभग ६० मील नीचे, मिट्टूर नामक स्थान पर एव जलाशय के निर्माण की योजना तैयार कर चुकी थी। रियासत की ऊँची बादी में जलाशय बना कर पानी रोक लेने से मद्रास सरकार के जलाशय



के लिए उतना पानी नहीं बचता था जितना कि वह एकत्रित करना चाहते थे। हमारे जलाशय की योजना तैयार हो जाने पर मद्रास सरकार के लिए यह जरूरी था कि वह अपनी योजना में आवश्यक परिवर्तन करे, परन्तु कुछ समय तक वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब हमने भारत सरकार के पास अपनी अपील भेजी और वादी के पानी में से अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए डटे रहे। जैसा कि मेरा विश्वास है, भारत सरकार के इंजीनियरों ने भी हमारे इस अधिकार का समर्थन किया। हमने भारत के वाइसराय लार्ड हार्डिंग से अपील की कि हमें बांध के निर्माण का काम शुरू करने की अनुमति दी जाय। वाइसराय ने हमारी अपील मान ली, परन्तु अभी ८० फुट ऊंचा बांध बनाने की ही अनुमति दी। हमने बांध बनाना शुरू कर दिया और नीचे से उसकी चौड़ाई उतनी ही रखी जितनी कि १२४ फुट ऊंचे बांध के लिए जरूरी थी। हम जानते थे कि हमारा अधिकार न्यायोचित है और अन्त में हमें बांध बनाने की अनुमति मिल जायगी। तब इस झगड़े का निपटारा करने के लिए एक समिति बनायी गयी और फ्रैंसला हमारे पक्ष में हो गया। इस सम्बन्ध में हमें जो समर्थन लार्ड हार्डिंग तथा मैसूर के अंग्रेज रेजीडेंट सर ह्यूडाली की ओर से प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।

७ अक्तूबर, १९१६ को मैंने प्रतिनिधि सभा में इस बांध के सम्बन्ध में एक भाषण दिया, जिसमें उन विवादास्पद बातों को स्पष्ट किया गया था जो कि निपटारा समिति के सामने रखी गयी थीं। भाषण का सारांश इस प्रकार है:

“डेल्टा के निवासियों में, विशेषकर तंजौर और त्रिचिनापल्ली जिले के लोगों में पुरस्कार के सम्बन्ध में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। अखबारों में और सार्वजनिक सभाओं में यही शोर मचा हुआ है कि समिति ने पक्षपात-पूर्वक फ्रैंसला मैसूर के पक्ष में दे दिया है, जो मद्रास के हितों के लिए घातक है। यह बात जनता में सम्भवतः एक तो इस कारण से फैली कि विवाद तकनीकी क्रिस्म का था और दूसरे यह समस्या ही कुछ ऐसी थी कि मद्रास में हो रहे एकतरफ़ा प्रदर्शन का खण्डन पहले नहीं किया जा सकता था।

“इस समय मैसूर के अन्तर्गत कावेरी वादी में नदी द्वारा ११५,००० एकड़ भूमि सिंची जा रही है। इसके विपरीत मद्रास प्रेजीडेंसी के निचले इलाकों में नदी के पानी द्वारा १,२२५,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा

रही है। पानी नदी के पानी में सींचा जाने वाला ९२ प्रतिशत इलाका मद्रास प्रेजिडेंसी में पड़ता है और केवल ८ प्रतिशत मैसूर में है। नदी के कुल पानी का तीन चौथाई भाग मैसूर के इलाके में से होकर बहता है, परन्तु जैसा कि बताया जा चुका है, रियासत को इस पानी से जो लाभ पहुँचता है, उसका अनुपात बहुत कम है। नदी का बहुत सा फालतू पानी हर साल बिना किसी काम भाड़े, समुद्र में जा गिरता है। मैसूर की योजना में तो इस फालतू पानी का बहुत थोड़ा हिस्सा काम में लाया जा रहा है।

"मैसूर के जलाशय में जहाँ ४८०० करोड़ घनफुट पानी जमा करने की संभावना है, वहाँ मद्रास सरकार उतने ही अवधि-क्षेत्र से इससे दुगुने आकार का जलाशय बनाने की योजना तैयार कर चुकी है।

"मैसूर के जलाशय से मैसूर राज्य में पहले से १५०,००० एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई होगी, जब कि मद्रास के जलाशय से ३२०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई का विस्तार होगा। यह क्षेत्र मैसूर के जलाशय द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र से दुगुने से भी अधिक है।

"ये दो तथ्य कि नदी में पर्याप्त फालतू पानी रहता है और मद्रास सरकार हमने दुगुने आकार का जलाशय बनाने का विचार रखती है, इस बात का सबूत है कि हमारे जलाशय के निर्माण से मद्रास सरकार के जलाशय में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। इस बात को सब मानते हैं कि मद्रास सरकार को केवल उतना ही जल प्राप्त करने का अधिकार है, जितना कि उसकी जमीनों की सिंचाई के लिए आवश्यक है।"

जब हमने कोटर की सोना खानों के मैनेजर एजेंट मेसर्स जॉन टेलर एण्ड सन्ड को यह वचन दिया कि हम १ जुलाई, १९१५ तक जलाशय का निर्माण पूरा कर देंगे, तो उन्होंने हम वारे में सन्देश प्रकट किया। परन्तु जब यह काम निश्चित समय पर पूरा हो गया और विजयपुर को पानी मिलने लगा तो कम्पनी के व्यवस्थापकों ने महाराज के प्रति बड़ा आभार प्रकट किया।

५ मई, १९११ के दिन मैं इस योजना के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, वह इस प्रकार है:

"एक बार आरम्भ हो जाने पर इस योजना में राज्य में प्रगति के अनेक रास्ते खुल जायेंगे। लेकिन प्रगति की रफ्तार किसी एक व्यक्ति के

वश में नहीं रहनी, बल्कि सरकार की शक्ति और दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। इस प्रकार के निर्माण कार्य ने राज्य को, परोक्ष आय के रूप में, यदि ३ प्रतिशत का लाभ होता है तो वह भी बहुत है। परन्तु आशा है कि इस योजना के पूर्ण हो जाने पर, राज्य को प्रत्यक्ष आय के रूप में ही काफी लाभ हो जायगा।”

भारत भर में इस जलाशय की कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं। यह विशेषताएं इस प्रकार हैं:

१. यह भारत भर में अब तक बने सब जलाशयों से बड़ा है।

नोट: मद्रास सरकार द्वारा इसी नदी पर बनाया गया मिठूर डाम इससे कहीं बड़ा है। परन्तु इसका निर्माण १३ वर्ष बाद आरम्भ हुआ था।

२. कावेरी की बायीं ओर वाली नहर को एक पहाड़ी में, पौने दो मील लम्बी एक सुरंग बना कर, उसमें से गुजारा गया है। सिंचाई नहर की यह सुरंग भारत भर में सबसे लम्बी है।

३. कृष्णराज सागर योजना से कई प्रयोजन सिद्ध होते हैं और इसे अमरीका की टी० बी० ए० योजना का ही छोटा रूप समझना चाहिए।

इससे लगभग १००,००० एकड़ भूमि में सिंचाई का विस्तार हुआ है तथा अभी और होगा।

इससे कोलार की सोना खानों को बिजली मिलती है।

इससे बंगलौर, मैसूर तथा राज्य के अनेक गांवों और कस्बों को घरेलू इस्तेमाल तथा कारखानों के लिए बिजली प्राप्त होती है।

इससे राज्य में गन्ने की खेती बढ़ गयी है और, अधिक बिजली उपलब्ध होने से, चीनी की मिलों को प्रोत्साहन मिला है।

इससे मैसूर तथा बंगलौर की कपड़ा मिलों के अतिरिक्त वहां के अन्य बहुत से उद्योग-धंधों के लिए बिजली प्राप्त हुई है।

४. तीन वर्ष पूर्व मैसूर के चीफ इंजीनियर ने, मेरे कहने पर, योजना सम्वन्धी एक आर्थिक रिपोर्ट तैयार की। सारी योजना पर राज्य की ओर से लगभग १० करोड़ रुपये खर्च किया गया था। इस योजना द्वारा जनता को लगभग १५ करोड़ रुपये वार्षिक का लाभ हो रहा था

और सरकार को, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आय के रूप में, १ करोड़ रुपये वार्षिक की आमदनी हो रही थी। इस प्रकार सरकार को इस योजना पर लगायी गयी कुल पूँजी पर १५ प्रतिशत लाभ हो रहा था।

## मैसूर में दीवान के पद पर नियुक्ति

अंग्रेजी शासन प्रबन्ध के पचास वर्ष

सन् १८३१ से लेकर १८८१ तक मैसूर, राज्य अंग्रेजी प्रशासन के अधीन रहा। तब २५ मार्च, १८८१ के दिन राज्य की वागडोर मैसूर के पैत्रिक राजवंश के हाथों में सौंप दी गयी। तब तक राज्य में बहुत-सी सड़कों तथा ५० मील लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका था और आधुनिक प्रशासन की बहुत-सी बातें लागू हो चुकी थीं। दूसरे शब्दों में, राज्य के अन्दर एक सुव्यवस्थित शासन प्रबन्ध कायम हो चुका था।

सन् १८७६-७८ में मैसूर में भीषण अकाल पड़ा, जिससे राज्य की भौतिक समृद्धि को बड़ा भारी धक्का लगा। रियासत के प्रथम दीवान श्री सी० रंगाचारलु के अनुसार सरकार को अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए १६० लाख रुपये खर्च करने पड़े और सरकार पर ८० लाख रुपये का ऋण हो गया। राज्य के दस लाख व्यक्ति इस अकाल का ग्रास बन गये और भौतिक साधनों को बड़ी भारी हानि पहुंची। अकाल के घातक परिणाम के कारण, १८८१ में शासन बदलते समय अंग्रेजी प्रशासन द्वारा लायी गयी अच्छाइयों की पूरी-पूरी सराहना नहीं हुई।

## भारतीय दीवानों द्वारा शासन प्रबन्ध के तीस वर्ष

सन् १८८१ के पश्चात् राजवंश के महाराजा या महारानी के अधीन भारतीय दीवान राज्य का शासन प्रबन्ध बड़ी लगन और कुशलता से चलाते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपना कर राज्य के कुछ विभागों में कई प्रकार के सुधार तथा परिवर्तन किये।

भारतीय राजाओं के शासन काल में रियासत में जो-जो महत्वपूर्ण सुधार तथा निर्माण कार्य किये गये, वे इस प्रकार हैं :

दीवान सी० रंगाचार्लू के समय में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गयी। दीवान सर के० शेषाद्रिअप्पर के समय में शिवसमुद्रम् पर कावेरी के पानी द्वारा बिजली पैदा करने की योजना तैयार हुई, मारीकानव पर जलाशय का निर्माण हुआ और कावेरी, काविनी तथा हेमावती की बाधियों में सिंचाई के लिए नहरें बनायी गयी। बगलोर तथा मैसूर के नगरों में बहुत-से सुधार करके उनका विस्तार किया गया। सन् १८८१ तक २५ लाख रुपये की लागत में ५० मील लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। सन् १९१०-११ तक यह लाइन बढ़ा कर ४११ मील लम्बी कर दी गयी और इस पर कुल २५० लाख रुपये खर्च हुए। इन ३० वर्षों में राज्य की सड़कें भी पहले से दुगुनी हो गयीं।

सन् १९०७ में जब श्री बी० पी० भागवत राव मैसूर के दीवान थे, तब राज्य में विधान परिषद् की स्थापना की गयी।

मैसूर प्रतिनिधि सभा में मैंने अपने प्रथम भाषण में जो आकड़े पेश किये, वह उल्लेखनीय हैं। रियासत की जन-संख्या, जो १८७१ में ५,०५५,४०२ थी, अकाल पड़ने के कारण १८८१ में ४,१८६,१८८ रह गयी। सन् १९११ में इस में पुनः वृद्धि हो गयी और यह ५,८०६,१९३ तक पहुँच गयी। यह वृद्धि इसलिए हुई कि अकाल के दिनों में जो लोग घरघार छोड़ कर दूसरे इलाकों में चले गये थे, वे रियासत की हालत सुधरने पर अपने घरों को वापस आ गये।

कस्बों की आबादी जो कि १८८१ में १३ प्रतिशत थी, सभबत कस्बों में लोगों का काम-धंधा न मिलने के कारण १९११ में ११ प्रतिशत रह गयी।

सेती-बाड़ी पर निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या, जो १८८१ में ३३ लाख थी, बढ़ते-बढ़ते १९११ में ४२ लाख तक पहुँच गयी। अहा तक सेती-बाड़ी का सम्बन्ध है, काफी उत्पादन को छोड़ कर १८८१-८२ में ४,२१३,५०५ एकड़ भूमि में जोनाई होती थी और १९११-१२ में ७,४३८,४६३ एकड़ भूमि में होने लगी थी। यानी सेती में ७९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् १८८१ के पदवान् रोजों में विस्तार अवश्य हुआ है, पर अधिक उत्पादन पर धन नहीं दिया गया।

रियासत का कुल राजस्व, जो पिछड़ी धनाढ्यों के आरम्भ में ५० लाख रुपये के करीब था, १८८०-८१ में १०१ लाख रुपये हो गया और १९१०-११ में २४७ लाख रुपये तक आ पहुँचा, जिसमें मोना खानों से प्राप्त होनेवाली आय भी शामिल

थी। इसी प्रकार रियासत का खर्च भी पहले से दुगना हो गया था। सन् १८-८०-८१ में यह २२३ लाख रुपये तक पहुंच गया।

राज्य में शिक्षा पर होनेवाला खर्च, जो कि १८८०-८१ में ३,९१,०२८ रुपये था, १९१०-११ में १८,७९,१३५ रुपये हो गया और स्कूलों में जानेवालों की संख्या, जो कि १८८०-८१ में ५३,७८२ थी, १९१०-११ में १३८, १५३ तक पहुंच गयी।

राज्य में कुछ छोटे-बड़े उद्योग जिनमें कोलार की सोना खानें तथा शिमोगा का मैंगनीज खानें और कुछ कपड़े की मिलें शामिल थीं, आरम्भ हो चुके थे। परंतु इनमें से अधिकांश किसी भी स्थानीय उद्यम से सम्बन्धित नहीं थे और इनसे लोगों की तकनीकी कुशलता या सहकारी उद्यम की प्रगति का प्रमाण न मिलता था।

### मेरे दीवान पद ग्रहण करने के समय मैसूर की स्थिति

नवम्बर १९१२ में महाराज ने टी० आनन्दराव के पश्चात् मुझसे दीवान का पद संभालने को कहा। यद्यपि मेरी यह तीव्र इच्छा थी कि उद्योग, शिक्षा तथा अन्य विकासकार्यों द्वारा मुझको देश और जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिले, परंतु इस प्रकार के किसी भी उच्च पद को ग्रहण करने की इच्छा कदापि नहीं थी। रियासत में मुख्य इंजीनियर का पद संभालने के पूर्व भी मैंने यही इच्छा प्रकट की थी कि तकनीकी शिक्षा के प्रसार और उद्योग-वन्धों का विकास करने के अवसर मुझको मिलने चाहिए। इस वार भी महाराज से मैंने यही कहा कि यदि मुझको विकास विभाग की परिषद में सदस्य नियुक्त कर दिया जाय तो मेरे लिए वही काफ़ी होगा। इससे मुझे राज्य के अन्दर शिक्षा प्रसार, उद्योग विकास तथा लोकहित के अन्य कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। पर महाराज इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। उनका आग्रह यही था कि मैं दीवान के पद को स्वीकार कर लूं। खैर, तो उस पद को ग्रहण करने में मुझे बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि इस पर कार्य करते हुए मुझे लोगों की सेवा करने के बहुत से अवसर प्राप्त हुए। मेरे कार्य भार संभालने के तुरन्त बाद, मैसूर इंजीनियर मण्डल ने ३० नवम्बर, १९१२ को, एक सभा बुला कर मुझे मान-पत्र भेंट किया। श्री वी० पी० माधव राव सभा के अध्यक्ष थे। मानपत्र के उत्तर में मैंने जो भाषण दिया, उसका सारांश इस प्रकार है:

“मैंने देखा है कि आपने अपने मानपत्र में मेरे लिए इससे भी अधिक

मान और सम्पत्ति की कामना की है। आप जानते ही होंगे कि मेरी सदा यही इच्छा रही है कि मुझे काम करने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया है वह व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने पद की उन्नति के लिए नहीं किया। महाराज ने कृपापूर्वक जो महत्वपूर्ण काम मुझे सौंपा है उसमें उन कार्य की तमाम गुंजाइश है जिसकी मुझे हमेशा चाह रही है।”

अब तक रियासत के इस पद पर आई० सी० एम० अफसर काम करते रहे थे और अब इस पद पर एक इंजीनियर की नियुक्ति होने के कारण सरकारी क्षेत्रों में बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया। परन्तु मैसूर की जनता ने इस बारे में किसी प्रकार की हैरानी प्रकट नहीं की। जब मैंने इस पद का कार्य संभाला तो राज्य की जिन-जिन कमियों की ओर मेरा ध्यान गया, वह इस प्रकार हैं-

शिक्षा का निम्नस्तर,

कार्य आरम्भ करने की लगन तथा सगठन शक्ति की कमी,

प्रमुख अधिकारियों में योजना बना कर कार्य करने की अक्षमता,

निम्नस्तर की अर्थव्यवस्था जिसे सुधारने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा था।

मेरा सब से मुख्य लक्ष्य यही था कि शिक्षा, उद्योग तथा वाणिज्य और लोक-निर्माण कार्यों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाय, जिसमें लोगों को काम मिले, उनकी कमाई में वृद्धि हो और उनका जीवनस्तर ऊंचा उठे। सीधे ही राज्य के अधिकारियों तथा जनता का ध्यान उनके जीवनस्तर की कमियों की ओर आकृष्ट किया गया और आवश्यक सुधार तथा विकास के लिए वही तरीके अपनाने के सुझाव दिये गये जो जापान, पश्चिम यूरोप तथा अमरीका जैसे देशों में अपनाये जा रहे हैं और जिन का अध्ययन मैंने इन देशों की यात्रा के दौरान में किया। इन सब बातों की चर्चा मैंने अक्तूबर, १९१३ में प्रतिनिधि मन्त्रियों में दिये गये अपने प्रथम भाषण में ही की। भाषण इस प्रकार है-

“आजकल रेलवे ट्रामवे या अन्य लोकोपयोगी कार्यों का निर्माण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह गयी, क्योंकि इन कार्यों के लिए कुशल विदेशी एंजिनियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। यदि हम उचित



प्रतिफल देने का जिम्मा लें तो विदेशी पूंजी प्राप्त हो सकती है। लोक सेवाओं के कार्य को चलाने के लिए योग्य भारतीय या विदेशी व्यक्तियों की सेवाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि विदेशी एजेंसियों की सहायता का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने हित के साथ हमारा हित भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पूर्ण रूप से विदेशी सहायता द्वारा शुरू किये जानेवाले बड़े-बड़े कामों से न हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा और न हमारे देश की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। और जब तक राज्य के लोगों की सूझ-बूझ और राज्य के प्राकृतिक साधनों तथा पूंजी को एक साथ काम में नहीं लाया जाता, तब तक स्थायी रूप से प्रगति नहीं हो सकती।

“हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य में पिछले ३० वर्षों में काफी प्रगति हुई है, परन्तु यह प्रगति हमारे संगठित प्रयत्नों से नहीं हुई बल्कि यह तो व्यापक प्रगति है जिसका रूप सारे भारत में दिखायी दे रहा है।

“राज्य के प्रत्येक सोलह व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ लिख सकता है। जब खेतों में काम के दिन होते हैं, तब भी किसान लोग पूरी तरह से व्यस्त नहीं रहते और जब किसी कारण से फसलें खराब हो जाती हैं तो वे महीनों हाथ पर हाथ रखे बिना काम-धंधे के बैठ रहते हैं। राज्य के तीन चौथाई लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर रहते हैं और उनमें से अधिकांश गांवों में रहते हैं। गांवों के इन लोगों के पास कुछ करने-घरने के लिए नहीं है और इनका जीवन घर की चारदीवारी तक ही सीमित है। हमारे किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं, व्यापार छोटे पैमाने पर किया जाता है। हर कोई अपना अलग धंधा लिये बैठा है। समाज के उच्चवर्ग ने भी संगठन और सहकारिता के पाठ को सीखने का प्रयास नहीं किया।

“शासन प्रबन्ध बदलने के बाद रियासत के प्रथम दीवान श्री रंगाचालु ने भी, जो १८७६-७८ में अपनी आंखों से रियासत को अकाल का ग्रास बनते देख चुके थे, इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया था। सन् १८८१ में उन्होंने इस सभा में भाषण देते हुए उद्योग विकास पर बड़ा बल दिया था और कहा था कि कोई भी देश तब तक समृद्धिवाली नहीं बन सकता

जब तक कि उस देश की कुपि और निर्माण उद्योग साथ-साथ नहीं चलते। उनका यह कहना था कि जब बाढ़ी मारा संभार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरकीब कर रहा है तो इस देश की २० करोड़ जनता अपनी चिरनिद्रा में ज्यादा देर तक नहीं पड़ी रह सकती। जब तक हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तब तक यह फस्ताहाली हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और अकाल जैसे किमी भी संकट की पहली चोट ही हमें कुचल देने के लिए काफी होगी।”

“३० वर्ष पूर्व कहे गए इन शब्दों में आज भी उतनी ही सच्चाई है जितनी कि पहले थी, और यदि हम अपनी हालत को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते तो ३० वर्ष बाद भी इनकी सच्चाई कम नहीं होगी।

“हमें लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनमें सामर्थ्य पैदा करने के लिए उन्हें स्वावलम्बी बनाना है, उन्हें साहस का पाठ पढ़ाना है ताकि वे लकीर के फकीर न बने रह कर नव-निर्माण के लिए उठ खड़े हों और संगठन तथा सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर एक हो जाएं।”

“आर्थिक सम्मेलन नामक संस्था ने राज्य के लोगों में सहकारिता का उचित क्षेत्र तैयार किया है, भले ही संस्था का काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। कोई भी व्यक्ति जिसने पश्चिम के विकसित देशों में शिक्षा और उद्योग संघों की बड़ी संजी से विकास होते देखा है, व्यापार की प्रतियोगिता के साथ चलते देखा है, इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट किये और गत्यांग दिग्ग बिना नहीं रह सकता।”

“यह संस्था सड़ो, बस्तों और फिर धीरे-धीरे गांवों में भी, सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। चूंकि हमारे राज्य में ९० प्रतिशत लोग अब भी गांवों में बसने हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करने पड़ेंगे।”

“आर्थिक विभाग के लिये एक गांव को इकाई मान कर वर्ष भर में दूई करना वांछनीय बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यदि हर एक गांव सरकारी के रास्ते पर कुछ आगे बढ़ता है तो सामूहिक रूप में होने वाली प्रगति काफ़ी सन्तोषजनक होगी। जिस गांव में ५ से १० प्रतिशत तक लोग दूई होते नहीं होते उस गांव की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं रहा ज सकता। गांवों में देशीय उत्पादों के एब-दो अच्छे बनावार-द्वारा

नियमित रूप से मंगा कर पढ़े जाने चाहिए, ताकि लोगों को बाहिरी दुनियां के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। गांव के प्रत्येक कुटुम्ब के पास इतना अनाज या धन जमा रहना चाहिए कि यदि कभी अकाल पड़ जाए तो वह इस अनाज या धन के सहारे कम-से-कम दो वर्ष काट सकें। प्रत्येक किसान कुटुम्ब को कोई-न-कोई सहायक धंधा अपनाना चाहिए, ताकि जब खेतों में काम के दिन न हों या कोई आड़ा वक्त आ पड़े, तो वे अपना निर्वाह भली-भाँति कर सकें। हर एक गांव के वासियों को चाहिए कि प्रगति की किसी न किसी दिशा में क्रदम बढ़ा कर वे हर साल सामूहिक विकास में अपना योग दें।”

“हर एक गांव में साल भर में हुई आर्थिक प्रगति का आवश्यक लेखा-जोखा साल में एक बार प्रकाशित किया जाना चाहिए।”

रियासत के दीवान के रूप में कार्य करते हुए मेरी नौकरी के छः वर्ष के दौरान मेरी हर तरह से यही कोशिश रही कि जो भी विकास कार्य किया जाय, वह योजना के अनुसार हो और उसके लिए एक स्तर निश्चित कर दिया जाए। यद्यपि शिक्षा और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तथापि राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा न कर के राज्य में उपलब्ध साधनों के अनुसार उन के विकास की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया था।

दुर्भाग्यवश मेरे कार्य संभालने के २१ महीने बाद अगस्त, १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और दिसम्बर, १९१८ तक, जब तक कि मैं रियासत का दीवान रहा, युद्ध का अन्त नहीं हुआ।

महाराज ने रियासती सेना देकर तथा समस्त साधनों द्वारा अंग्रेजी सरकार की हर तरह से सहायता की। इसके अतिरिक्त महाराज ने भारतीय सेना के खर्च के लिये ५० लाख रुपये नकद दिये। इस भेंट को पेश करते हुए २० अगस्त, १९१४ के एक पत्र में महाराज ने भारत के वाइसराय को लिखा :

“मैं आप को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि रियासत की राज-भक्त प्रजा अपनी सरकार के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने और साझे हितों की रक्षा के लिए तैयार है।”

महामहिम वाइसराय ने उत्तर में एक बहुत ही प्रशंसा भरा पत्र लिखा, जो इस प्रकार है :

"इस समय तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप जैसे मित्र की राज-भक्ति तथा देशभक्ति से मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है।"

महायुद्ध के परिणामस्वरूप राज्य में होने वाले वृद्धि से महत्वपूर्ण विकास-कार्यों को विशेषकर औद्योगिक विकास को बड़ा भारी धक्का लगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक्त जानकारी अगले कुछ पन्नों में प्रस्तुत की गई है कि युद्ध की स्थिति में क्या कुछ करने का प्रयास किया गया और उस में कहां तक सफलता प्राप्त हुई। यह सब विवरण कुछ लम्बे जरूर हैं, परन्तु इनसे पता चलता है कि उस समय महायुद्ध के कारण सामान्य प्रयत्न चलाने तथा विकास व सुधार कार्य करने के लिये मार्ग में कौन-कौन-सी बाधनाएँ पैदा आईं।

सुप्रसन्नः प्रसीदति

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

इस समय पर विचार करने के लिए जब किया गया तब निम्नलिखित भी निर्दिष्ट माना गया है १९३३ में मीसूर का दौरा किया, जो जान समझ में निश्चय किया गया कि पर्वतों पर भी यह भी हो सकता है। मीसूर का भी यह मीसूर में ही किया गया, जब भारत के वाट्सनस लाई हाउस कागानुर में एलिफेन्टा की मूर्ति का दौरा करने कागानुर में आया हुआ है। इस अवसर पर वाट्सनस में वाट्सनस काल के लिए अंग्रेज रेजीडेंट सर ह्यू डाली, महासचिव तथा मैं उपस्थित थे। तब संधि के मीसूर को स्वीकार किया गया।

“इन्द्रभूषण आंकट शून्गाफर” में उन गव दातों की व्याख्या की गई थी, जिनके आधार पर रियामत का सामन-प्रबंध महाराजा को सीपा गया था। संधि में यह सब दातों दी गई थी, जिन पर महाराज और अंधेजों के बीच समझौता हुआ था।

इससे महाराज के रियासत के भीतर शासन-प्रबन्ध चलाने के पूरे-पूरे अधिकार मिल गए परन्तु प्रमुख सत्ता अंग्रेजी सरकार की ही रही। इस संधि से महाराज के अधिकारों में वृद्धि हो गयी और उनका प्रभुत्व भी बढ़ गया।

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् देशी रियासतों तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधों में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए उस संधि द्वारा रियासत में हुए परिवर्तनों का व्योरा देने की जरूरत नहीं रही। अब देशी

रियासत राजनीतिक दृष्टि से भारत के साथ मिला दी गई हैं और यद्यपि वह भारत के लोकतन्त्र का ही भाग है, फिर भी उनकी जो प्रतिष्ठा अंग्रेजी शासन काल में थी, सो अब नहीं है। आशा है कि नये प्रजातन्त्र के अभिक विकास में यह केवल छोड़े दिनों की ही बात है।

६ नवम्बर, १९१३ के दिन मैसूर में आपण देते हुए लार्ड हार्डिंग ने संधि के बारे में निम्नलिखित विचार प्रकट किये -

“जितनी खुशी मुझे आज इस घोषणा को आप के सामने पेश करने में हो रही है, मेरा ख्याल है कि उसे सुनकर महाराज भी उतने ही खुश होंगे। लगभग चार मास पूर्व महाराज आपने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें आपने सन् १८८१ के “इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ट्रान्सफर” के कुछ अंगों पर आपत्ति की थी जिसके अनुसार मैसूर का शासन-प्रबन्ध महाराज के पिता को सौंपा गया था। आपने इस बात की ताकीद की कि इस दस्तावेज के रूप और सार में इस तरह का परिवर्तन किया जाए, जिससे अंग्रेजी सरकार तथा रियासत के बीच संबंधों का और अधिक स्पष्टीकरण हो जाए। इस प्रश्न पर काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात् मैंने भारत सरकार के सचिव के साथ मिल कर यह निर्णय किया है कि ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ट्रान्सफर’ को रद्द कर के उसके बदले एक नई संधि पर समझौता किया जाय, जिससे अंग्रेजी सरकार के मैसूर राज्य के साथ वैसे ही सम्बन्ध स्थापित हो जाएं, जैसे कि दूसरी रियासतों के साथ हैं। सरकार ने मेरी तजवीज को स्वीकार कर लिया और यह देखा कि इस प्रश्न पर महाराज के विचार बड़े प्रभावशाली ढंग से सरकार के सामने रखे गए थे। महाराज के उच्च चरित्र तथा उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें और भी प्रभावशाली बना दिया। मैं इन बातों से पूर्णतया सहमत हूँ और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि इस शुभ अवसर पर आप को यह बताने के लिए मुझे भेजा गया कि इस विमल साम्राज्य के उच्चाधिकारियों की दृष्टि में आपका कितना मान है।”

अंग्रेजी सरकार के साथ संधि हो जाने के पश्चात् २२ नवम्बर, १९१३ के दिन महाराज ने मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नई संधि तैयार करने के लिए मेरे द्वारा दिये गए सहयोग की चर्चा की। यह पत्र मेरे प्रति महाराज की उदारता की प्रकट करता है। पत्र में लिखा था:

“बाइसराय का दौरा समाप्त होने के पश्चात् मुझे अवसर मिला है कि

## प्रतिनिधि सभा में सुधार

रियासत में प्रतिनिधि सभा की स्थापना १८८१ में हुई थी। उस समय मंसूर की राजगद्दी पर महाराज चामराज वाडियार बहादुर विराजमान थे और श्री सी० रंगाचार्लू जैसे देशभक्त तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ रियासत के दीवान थे। प्रतिनिधि सभा के अधिकार केवल सरकार के पास प्रार्थनाएं लेकर जाने तक ही सीमित थे और मेरे कार्य संभालने तक सभा के अधिकारों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

आधुनिक प्रजातन्त्र की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्चय किया गया कि प्रतिनिधि सभा को कुछ ठोस अधिकार दिए जाएं। इस बारे में महाराज की अनुमति प्राप्त करके ११ अक्टूबर, १९१३ के दिन सभा की पहली ठक में मैंने जो भाषण दिया, वह इस प्रकार है :

“यह उचित होगा कि प्रतिनिधि सभा के निर्माण, इस अधिवेशन में सदस्यों का चुनाव करने के तरीकों तथा उसके अधिकारों व काम करने की विधियों पर विचार किया जाए। यदि सदस्य इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श

करके इस बारे में अपना-अपना मत प्रकट करें, तो उन सबके विचारों को महाराज के सामने रखा जाएगा।”

तब जो निर्णय हुआ उसके अनुसार मभा को रियासत के बजट पर बहम करने की अनुमति दे दी गई। इस उद्देश्य के लिए मैगूर की भाषा कन्नड़ में एक सक्षिप्त बजट प्रकाशित कर उसकी प्रतिया प्रकाशित कर सदस्यों में बांट दी गई।

उन दिनों दशहरा होने के कारण सितम्बर और अक्तूबर में मभा का केवल एक ही अधिवेशन हो सका और बजट की मंजूरी उसके बाद दी गई। बजट स्वीकृत होने से पूर्व सदस्यों को उस पर बहस करने का अवसर देने के लिए मभा का दूसरा अधिवेशन बुलाया गया। इस प्रकार का पहला अधिवेशन २१ अप्रैल, १९१७ को हुआ था। मभा को विधान परिषद् के लिए दो की वजाय चार सदस्यों का चुनाव करके भेजने का अधिकार भी दिया गया। बाद में चुनाव के लिए खड़े होने वाले सदस्यों तथा मतदाताओं की योग्यताओं में भी कमी कर दी गई।

## विधान परिषद् में सुधार

जैसा कि पहले बताया जा चुका है विधान परिषद् का आरम्भ १९०७ में हुआ, जब कि श्री बी० पी० माधवराव रियासत के दीवान थे। परिषद् में १५ से १८ तक सरकारी तथा गैरसरकारी मनोनीत सदस्य हुआ करते थे जिनमें से केवल दो सदस्य प्रतिनिधि मभा द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। परिषद् का मब से महत्वपूर्ण काम रियासत का विधान बना कर, उस पर बहम करके उसे लागू करना था। विधान परिषद् की रचना तथा उसके अधिकारों में भी बहुत कुछ परिवर्तन किए गए। परिषद् के सदस्यों की संख्या १८ से बढ़ा कर २४ कर दी गई। इनमें से चार सदस्य प्रतिनिधि मभा द्वारा चुने जाते थे, चार सदस्य जिलों के चुनाव हलकों के होते थे, दस सदस्य सरकारी होते थे और छ मनीनीत सदस्य होते थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या दो से बढ़ा कर आठ कर दी गई।

परिषद् के अधिकारों को बढ़ा दिया गया और उन्हें बजट पर बहम करने की छूट भी दे दी गई। आरम्भ में यह अधिकार सीमित थे, परन्तु बाद में सदस्यों को पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दे दिया गया।

आजकल की स्थिति को देखते हुए इन सुधारों का कुछ भी महत्व नहीं रह



जाता, परन्तु यह उस समय की स्थिति के अनुसार प्रगति की राह पर काफ़ी महत्त्वपूर्ण कदम कहे जा सकते हैं और इस समय इनका बड़ा महत्त्व था।

### शासन प्रबन्ध में सुधार

सबसे पहले राज्य के शासन प्रबन्ध तथा न्याय प्रबन्ध को अलग-अलग करने का काम हाथ में लिया गया। अंग्रेजी शासन काल में इस विषय पर बहुत समय तक वाद-विवाद चलता रहा, परन्तु लोगों की स्वतन्त्रता के लिए इन दोनों प्रबन्धों का अलग-अलग होना आवश्यक माना जाता था। शुरू-शुरू में केवल दो जिलों में ही इस प्रणाली को अपना कर देखने का निश्चय किया गया और इसकी व्यवस्था मेरे रियासत में होते हुए ही कर ली गई। परन्तु १ जनवरी, १९१९ को लागू किया गया, जब कि मुझे अवकाश प्राप्त किए कुछ सप्ताह हो चुके थे।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रियासत के राजस्व अफ़सरों से न्यायिक अधिकार छीन कर इस काम के लिए अलग न्यायाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। राजस्व अफ़सरों तथा अमिलदारों को फौजदारी मुक़दमों के फ़ैसले नहीं करने दिए जाते थे। परन्तु राज्य में शान्ति की स्थापना के लिए उन्हें न्यायाध्यक्षों के अधिकार प्राप्त थे। ज़िलाधीशों के स्थान पर डिप्टी कमिश्नरों को ही कार्य करने दिया गया। संविधान तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यों पर विचार करने के लिए तथा आय के स्रोतों का सुधार करने के लिए दो समितियों की स्थापना की गई। इस प्रश्न पर विचार किया गया और स्थानीय स्वायत्त शासन को पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक क़ानून बना दिए गए। इस योजना का प्रयोजन नगर पालिकाओं के निर्वाचन तत्व तथा स्थानीय मंडलों को सुचारु ढंग से स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए अधिक अधिकार देना तथा उनकी आय के साधनों में वृद्धि करना था तथा इन संस्थाओं को वास्तव में ऐसा बनाया जाय, जो ज़िम्मेदार हों तथा अपना स्थानीय प्रबन्ध करने की क्षमता हो।

नगर पालिकाओं को उनकी जन संख्या के अनुसार तीन श्रेणियों—नगरों, क़स्बों तथा छोटी जगहों की नगरपालिकाओं में बांट दिया गया और शहरों के लिए निर्वाचित तत्व कम-से-कम दो तिहाई, नगरों के लिए आधा तथा क़स्बों के लिए एक तिहाई निश्चित कर दिया गया। कुछ खास नगरपालिकाओं के अध्यक्षों

तथा बहुत-सी नगरपालिकाओं के उपाध्यक्षों का चुनाव होता था। बंगलोर नगर-पालिका को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया।

ज़िला मंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या से दो तिहाई कर दी गई और तालुक मंडलों में यह संख्या कम-से-कम आधी कर दी गई। इन दोनों मंडलों को स्वतन्त्र रूप से पैसा इकट्ठा करने तथा खर्च चलाने के अधिकार दे दिए गए।

ग्राम मंडलों के स्थापना तथा व्यय संबंधी अधिकारों में घृष्टि कर दी गई तथा अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, औपचारिक तथा पशु चिकित्सालयों का नियन्त्रण भी उन्हीं के हाथ सौंप दिया गया।

डिप्टी कमिश्नरों को जिला मंडलों के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और जहाँ तक हो सका, उनकी जगह पर अन्य गैर सरकारी लोगों को नियुक्त कर दिया गया। सर्वे स्कोप में गांव को मूह्ता दी गई, ताकि ये काछन हटाये जा सकें कि स्थानीय संस्थान ऊपर से बनाए जाते हैं। यह तज़वीज़ भी रखी गई कि धीरे-धीरे जिला मंडलों के अधिकारों को बढ़ा कर उन्हें जिला का सामान्य शासन-प्रबन्ध चलाने योग्य बना दिया जाए, जैसे कि इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों की जिला परिषदों में होता है।

### मैसूर में आर्थिक सम्मेलन

आर्थिक सम्मेलन का काम तभी आरंभ हो गया था, जब मैं मैसूर का चीफ इन्वीनिपर था। इस सम्मेलन की तीन समितियाँ—कृषि, वाणिज्य व उद्योग तथा शिक्षा का और अधिक विस्तार किया गया। इन समितियों तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से एक सचिव नियुक्त कर दिया गया।

रिपोर्ट के आर्थिक साधनों के सर्वेक्षण के लिए एक अफसर नियुक्त किया गया और इस सम्बन्ध में एक बड़ी ही विस्तृत तथा लाभदायक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

जब आर्थिक सम्मेलन का काम बहुत बड़ गया तो प्रत्येक जिले में एक अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। ये अधीक्षक डिप्टी कमिश्नरों तथा जिला समितियों को

सूचना प्रसार के काम में हाथ बटाने तथा अन्य स्थानीय उद्योग धंधों तथा योजना कार्यों में लोगों को व्यावहारिक सहायता देने के लिए नियुक्त किए गए थे। रियासत के आठों जिलों की स्थिति तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में एक आर्थिक रिपोर्ट पुस्तिका रूप में प्रकाशित की गई।

आर्थिक सम्मेलन का अधिवेशन हर साल हुआ करता था और उसकी अध्यक्षता रियासत के दीवान किया करते थे। इन अधिवेशनों में सम्मेलन द्वारा साल भर में किए गए विकास कार्यों पर विचार किया जाता था और आगामी वर्ष के कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती थी।

सम्मेलन समितियां अपने-अपने कार्यक्षेत्र की बहुत-सी समस्याओं पर विचार करती थीं और आर्थिक विकास के लिए नई योजनाएं बनाती थीं। समितियों ने मैसूर बैंक स्थापित करने, मैसूर विश्वविद्यालय कायम करने, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने, अनिवार्य शिक्षा लागू करने तथा अन्य सांस्कृतिक व औद्योगिक योजनाएं लागू करने के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। इसके अतिरिक्त समितियों ने कन्नड़ साहित्य अकादमी की, जो कि कन्नड़ भाषा में वैज्ञानिक साहित्य रचना के लिए बनाई गई थी, स्थापना के प्रश्न पर विचार किया।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ महाराज ने यह निर्णय किया कि आर्थिक सम्मेलन को रियासत में एक स्थायी संस्थान के रूप में काम करने दिया जाए।

### कार्य-कुशलता की जाँच

सरकारी महकमों में कार्य-कुशलता तथा अनुशासन को बनाए रखने के लिए 'कार्य-कुशलता की जाँच' प्रणाली लागू की गई। इस प्रकार की जाँच करने की ज़रूरत क्यों थी? अक्टूबर, सन् १९१३ को प्रतिनिधि सभा में भाषण देते हुए इस जाँच पड़ताल की आवश्यकता को मैंने अपने भाषण में इन शब्दों में बताया :

“हमारे राज्य में जहाँ सरकारी महकमों में यूरोपियन ढंग से काम-काज चलता है और काम करने वाले अभी यूरोपियन ढंग की आदतों को नहीं अपना पाये, वहाँ हिसाब-किताब की जाँच की तरह कार्य-कुशलता की जाँच भी बढ़ी ज़रूरी है।”

“कार्य-कुशलता जाँच” की शाखा ने, जो कि सचिवालय में खोली गई थी,

सरकारी दफ्तरों के काम को व्यवस्थित कर के वहाँ ही प्रशमनीय कार्य किया। इसने कई दफ्तरों के काम-काज के बारे में नियम बनाए और दफ्तरों नियमावलिओं को तैयार कर के विभिन्न दफ्तरों में भेजने और समय-समय पर उनका सरोपन करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। दफ्तरों के निरीक्षणों को प्रामाणिकता दी गई और सरकारी अभिलेखों को ठीक ढंग से रखने के सम्बन्ध में नियम बनाए गए। सरकारी काम में कहीं भी कोई गड़बड़ नजर आने पर इस शाखा के अफसर जाच के लिए मुरतब वहाँ भेज दिये जाते। कार्य-कुशलता जाच शाखा एक प्रमासिक पत्रिका "ब्लू बुक जमरल" भी प्रकाशित करती थी, जिसमें सरकारी सूचनाएं तथा सरकारी कर्मचारियों के काम में आने वाले अन्य तकनीकी बातें भी रहती थी।

राज्य सरकार द्वारा अब कभी भी कोई गराहनीय कार्य किया जाता, महाराज उसकी प्रशंसा किये बिना न रहते। २४ जुलाई, १९१४ को उन्होंने मुझे एक व्यक्तिगत पत्र लिखा जो इस प्रकार है :

“मुझे यह बात आप पर प्रकट करने में खरा भी शिक्षक महसूस नहीं होती कि जितनी खुशी और मानसिक शान्ति का अनुभव मैंने पिछले २१ महीनों में किया है, उतना सन् १९०२ से कभी नहीं किया था। यह सब आपकी योग्यता और कार्य-कुशलता के कारण ही है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी बहुत दिनों तक आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा।”

## शिक्षा प्रसार तथा मैसूर विश्वविद्यालय

प्रतिनिधि सभा में मैंने जो भाषण दिये, उनके अनुसार राज्य में सहकारी दृष्टि-कोण से जिन बातों की सब से अधिक जरूरत थी, उन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

१. उत्पादन बढ़ाना और लोगों की उपार्जन शक्ति को बढ़ा कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।

२. जनता के सब वर्गों में शिक्षा तथा ज्ञान का प्रसार करना।

३. लोगों में स्वावलम्बन, सहयोग तथा उद्यम की भावना उत्पन्न करना।

जैसा कि मैंने प्रतिनिधि सभा में अपने २२ अप्रैल, १९१८ के भाषण में कहा, ऊपर बताये तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किये गए और उनमें सफलता भी प्राप्त हुई।

जिन दो विकास कार्यों—उद्योग तथा शिक्षा पर मैंने सब से अधिक बल दिया उनमें शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता दी गई थी। उद्योग विकास को युद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार तथा मैसूर के व्यापारियों की ओर से पूरा-पूरा सहयोग नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त विदेशी निर्माताओं का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका।

पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा शिक्षा को जो महत्व दिया जा रहा था, अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे तो हम वान का पूर्ण विश्वास हो गया कि मैसूर की आर्थिक हीनता का सब से बड़ा कारण शिक्षा की उपेक्षा ही है। हम दिना में मैं उन्नीसवीं सदी के अन्त में की गई अपनी जापान यात्रा के समय सब से अधिक प्रभावित हुआ था। जापानी नेताओं ने यह स्पष्ट ज्ञान दिया था कि शिक्षा ही सारी प्रगति का आधार है। जापानी शिक्षा विभाग का लक्ष्य यह था कि जापानियों को यूरोपियन स्तर में गौरवने तथा साम्र करने का अन्तर्धान प्राप्त जाए। हम दिना में जापान द्वारा जो सब से पहला कदम उठाया

गया वह यह था कि देश में एक शिक्षा-भरिता जारी की गई, जिगला आशय जापान के मन्त्रालय मित्रादो ने राष्ट्र को इन दलों में समझाया

"सामान्य जीवन के लिए जो समस्त ज्ञान आवश्यक है, और वह उच्च-कोटि का ज्ञान जिसके कारण बड़े-बड़े अफसर, किसान, व्यापारी, कारीगर चित्रितक आदि अपना-अपना धंधा चलाते हैं, शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है। इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि शिक्षा का इस प्रकार प्रसार किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई गाँव न होगा जिसमें कोई भी परिवार अशिक्षित हो ऐसा कोई परिवार न होगा जिसमें कोई व्यक्ति अपढ़ होगा।"

सन् १८७७ में टोकियो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसमें वाणिज्य तथा अन्य व्यावहारिक विषयों की शिक्षा देने के लिए विदेशी भाषाओं में कई स्कूल आरंभ किए गए। शिक्षा कोट का बार-बार पुनरावलोकन कर के सुधार किया गया। एक बार जिन मिडान्तो के आधार पर सुधार किए गए, वे इस प्रकार वर्णित हैं—'नैतिक चरित्र का विकास, देशभक्ति तथा स्वामिभक्ति की भावना का विकास तथा अमली धन्यो के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति।"

अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए कई स्कूलों में कौजी कवायद सिराई जाती थी। बच्चों को सदा प्रेमप्रवृत्ति रखा जाना था और उन्हें नैतिकता, देशभक्ति, राजभक्ति तथा मानव सम्बन्धों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जापान में जिस बात ने मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया वह थी स्त्री-शिक्षा का विकास। मैंने देखा कि जहाँ जापान के स्कूलों में १५,००,००० लड़कियाँ पढ़ रही थी, वहाँ भारत जैसे विमल देश में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या केवल ४,००,०० थी।

सन् १८९८ में जब मैं पहली बार जापान यात्रा पर गया तो मुझे टोकियो और क्योटो के प्रोफेसरों ने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें खरीदनी जरूरी नहीं है। प्रोफेसर विद्यार्थियों को कक्षा में नोट लिखा देते थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी पुस्तकालय की किताबों की सहायता भी लेते थे। मैंने देखा कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी, अमली प्रशिक्षण होता था। इसलिए विश्वविद्यालय से परीक्षा पास करते ही विद्यार्थियों को सरकारी गैर सरकारी नौकरियाँ मिल जाती थी।

जापान में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर कठोर परिश्रम करते थे और उनका जीवन बड़ा सादा होता था। हालांकि वे

अपनी योग्यताओं के बल पर गैर सरकारी जगहों पर काम कर के इससे अच्छा वेतन पा सकते थे, परन्तु वे उच्च भावनाओं से प्रेरित हो कर सादा जीवन व्यतीत करते हुए विश्वविद्यालय के थोड़े वेतन में ही संतोष कर लेते थे। बाहर काम करते समय उनकी वेश-भूषा यूरोपियन होती थी और घर में वे जापानियों की भाँति रहते थे। उनकी बहुत-सी आदतें परम्परागत होती थीं।

११ जुलाई, १९१३ को मैसूर आर्थिक सम्मेलन में मैंने मैसूर राज्य की सामान्य शिक्षा स्थिति पर निम्नलिखित भाषण दिया :

“मैसूर की ५७ लाख की जन संख्या में केवल ३॥ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। यानी केवल ६ प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं, जहाँ कि दूसरे उन्नत देशों में ८५ से ९५ प्रतिशत तक लोग पढ़े-लिखे हैं।”

“अमरीका में शिक्षा पर सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति १४६पए खर्च किये जाते हैं, जहाँ कि मैसूर में यह खर्चा छः आने प्रति व्यक्ति से भी कम है। दूसरे उन्नत देशों में कुल आबादी का १ भाग स्कूलों में जाता है। मैसूर में स्कूल जाने वालों की संख्या पचास में एक है।”

“मैसूर की कुल आबादी ६० लाख के करीब है, फिर भी यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। कनाडा की जन संख्या मैसूर की जन संख्या से केवल २५ प्रतिशत ज्यादा है और वहाँ विश्वविद्यालय हैं। इंग्लैण्ड में साढ़े चार करोड़ की जन संख्या के पीछे २० विश्वविद्यालय हैं और जर्मनी में साढ़े छः करोड़ की जनसंख्या के पीछे २१ विश्वविद्यालय हैं।”

“पहले प्रत्येक देश की कुल आबादी में केवल ५ से १० प्रतिशत लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। कृषि, उद्योग या अन्य शारीरिक मेहनत में लगे लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी, परन्तु अब नम्य देशों ने इस बात को भली-भाँति जान लिया है कि व्यावसायिक शिक्षा कृषि, उद्योग तथा शारीरिक मेहनत के वर्गों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है और यह शिक्षा जिनकी अधिक वैज्ञानिक होगी, उनकी ही धन में वृद्धि होगी।”

## प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य में सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल खोलने का काम बड़े जोर-शोर से शुरू किया गया और स्कूलों की इमारतों के लिए अनुदान दिए जाने लगे। इससे ग्रामीण जनता में कुछ उत्साह दिखाई देने लगा। एक बार मैं बेलदारा नामक गांव के निरुद्ध सड़क पर मैं हो कर जा रहा था तो उस गांव के लोगो ने रुपये की एक पैली मेरी कार में फेंक दी। यह रुपये उन्होंने अपने गांव में बनने वाली स्कूल की इमारत के लिए इकट्ठे किए थे। उन्होंने मुझसे शिकायत की कि इमारत के लिए उन्होंने अपने हिस्से के लिए रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, परन्तु इमारत बनाने के लिए सरकार की ओर में अभी तक मजूरी नहीं आई।

हरिजनों में शिक्षा के प्रसार के लिये विशेष रूप से अनुदान दिये गए। शिक्षा प्रसार का लक्ष्य यह रखा गया कि आगामी पांच वर्षों में स्कूल जाने वालों की संख्या पहले से दुगुनी हो जाए।

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया। शुरू-शुरू में यह कानून कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू किया गया और जैसे-जैसे समय बीतता गया, इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। जून, १९१८ तक इसे ६८ केन्द्रों में लागू कर दिया गया और १७० केन्द्रों में लागू करने की तैयारी की जा चुकी थी।

इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों की संख्या, जो १९१२ में ४५६८ थी, १९१८ में ११,२९४ हो गई। इसी अवधि में स्कूल जाने वाले बच्चों की गिनती १३८,१५३ से ३६६,८५६ हो गई।

लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे कर इसे भी प्रोत्साहित किया गया। स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में लड़कियों की गिनती जो १९१२-१३ में ९.४ प्रतिशत थी; १९१७-१८ में १४.२ प्रतिशत हो गई।

लड़कियों के लिए नये प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल खोले गए। मैसूर के महारानी कालेज को १९१७ में डिग्री कालेज बना दिया गया। मैसूर में लड़कियों के लिए पहला होस्टल १९१४ में आरम्भ किया गया।

## इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा

सन् १९१३ में बगलोर में एक कृषि स्कूल खोला गया। जहां तक संभव हो



सका, स्कूल के पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया और किसानों के लिए कन्नड़ भाषा में लघु पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की गई।

बंगलौर में एक इंजीनियरिंग तथा एक वाणिज्य स्कूल स्थापित किया गया। मैसूर के इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक स्कूल को मिला कर चामराजेन्द्र टेक्निकल इंस्टीच्यूट का नाम दे दिया गया और इसके लिए मैसूर नगर में एक विशाल भवन बनाया गया। इस संस्थान में वाणिज्य शिक्षा भी दी जाती थी।

बंगलौर के वाणिज्य स्कूल में एक वर्ष के लिए वाणिज्य की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी, जो कि अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में होती थी। वाणिज्य की माध्यमिक शिक्षा दो वर्षों के लिए अंग्रेजी में दी जाती थी। छोटे-मोटे दुकानदारों के लिए कन्नड़ में प्रारंभिक लेखे-जोखे तथा बैंकिंग की शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रम रखे गए।

ज़िले के प्रधान स्थलों में औद्योगिक स्कूल खोले गए और कई हाई स्कूलों में वाणिज्य शिक्षा देने का प्रवन्ध किया गया।

तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगलौर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया गया। यह कदम इसलिए उठाना पड़ा, क्योंकि पूना तथा मद्रास के इंजीनियरिंग कालेजों में हर साल मैसूर राज्य के पांच से अधिक छात्र नहीं लिये जाते थे और इससे रियासत की मांग पूरी नहीं होती थी।

विदेश जा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थियों को बहुत-सी छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई थी।

### मैसूर विश्वविद्यालय

मेरे दीवान पद ग्रहण करते ही सरकार ने मैसूर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सोच-विचार करना आरम्भ कर दिया।

रियासत की ओर से दो शिक्षा अधिकारियों को नियुक्त करके उन्हें इंग्लैण्ड, अमरीका, जापान तथा आस्ट्रेलिया के दौरे पर भेजा गया, जहां से लौट कर उन्होंने बड़ी लाभदायक रिपोर्ट पेश की। उन दो अधिकारियों में एक तो डॉ० सी० आर० रैंडी थे और दूसरे श्री थामस डैनहाम थे।

विश्वविद्यालय कायम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जुलाई, १९१४ में सरकारी सदस्यों तथा प्रमुख शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई और

छ महीनों तक इस समिति की बैठकें होती रहीं। इसके बाद जुलाई, १९१५ में इस समिति ने एक योजना बना कर भारत सरकार को पेश की। भारत सरकार के राजनीतिक तथा शिक्षा अधिकारियों ने इस योजना में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और इस सम्बन्ध में उन्होंने रियासत के अग्रेज रेजीडेंट सर ह्यू डाली तथा मेरे साथ विचार विमर्श किया। इससे कुछ दिन बाद भारत सरकार के शिक्षा आयुक्त श्री थार्प ने इस योजना की आलोचना कर के उसमें कई नए सुझाव दिए। तब मैसूर सरकार ने उन सुझावों के अनुसार अपनी योजना में संशोधन कर के, फरवरी १९१६ में यह योजना भारत सरकार को पेश कर दी।

इसके पश्चात् उसी मास में सर ह्यू डाली तथा मैं भारत सरकार के शिक्षा अधिकारियों से मिले और उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत की। शिक्षा अधिकारी हमारे साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आए और उन्होंने इस मामले पर बड़ी सहानुभूति से विचार किया।

शुक्र शैतिक वर्ष, आमतौर पर, एक जुलाई को आरम्भ होता था, इसलिए प्लान की सरकार उमी दिन से विश्वविद्यालय का श्री गणेश करने के लिए उत्सुक थी। ऐसा न कर पाने से एक वर्ष और नष्ट हो जाता। तब हमने मार्च, १९१५ में भारत सरकार से प्रार्थना की कि हमें आगामी एक जुलाई से विश्वविद्यालय आरम्भ करने की अनुमति दी जाय। भारत सरकार ने अनुमति तो दे दी, पर साथ में यह शर्त लगा दी कि अविष्य में मद्रास विश्वविद्यालय के साथ भी कुछ सम्बन्ध कायम रहे जायें। इससे पूर्व मैसूर के कालेजों के छात्र मद्रास विश्वविद्यालय में ही डिग्री प्राप्त किया करते थे।

मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति लार्ड एम्पिल द्वारा इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए, जून, १९१६, में अटकमंड में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मद्रास विश्वविद्यालय सिंडीकेट के सदस्य तथा मैसूर की ओर से मैसूर राज्य के रेजीडेंट तथा मैं शामिल हुए।

मद्रास विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने मैसूर द्वारा अलग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का विरोध किया। हमने कहा कि यदि हम अपने पाव पर सहे हो कर अलग विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो मद्रास विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को इस बात की खुशी होनी चाहिए। खैर, अन्त में सब मतभेद दूर हो गये और नये विश्वविद्यालय ने १ जुलाई, १९१६ से अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

विश्वविद्यालय के लिए मैसूर नगर में उचित स्थान का चुनाव करने का निश्चय किया गया। विश्वविद्यालय बिल विधान परिषद् में पेश करते हुए मैंने जो भाषण दिया, वह इस प्रकार था :

“मुझे इंग्लैण्ड, अमरीका तथा कनाडा में कई विश्वविद्यालय देखने के अवसर प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय आवादी-वाली जगहों में स्थित हैं। मैं विद्यार्थियों को जन जीवन से अलग-थलग रख कर पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा करने से, जब वे वास्तविकता के संसार में पहुँचते हैं तो, उनके लिए जीवन के साथ निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। विश्वविद्यालयों का लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि वह छात्रों का चरित्र निर्माण उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार करें जिन परिस्थितियों के साथ उन्हें जीवन में बाद में जूझना है।”

मैंने कहा कि हर विश्वविद्यालय के देश की सम्यता तथा भौतिक समृद्धि के अनुसार कुछ सामान्य तथा कुछ विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य की मोटी बात तो यह है कि उच्च-शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे देश के कोने-कोने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाय, ज्ञान की लौ जगमगा उठे और राज्य में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित हो जायें। मैसूर में शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोगों की मानसिक शक्ति तथा कार्यक्षमता का विकास हो, उन्हें निर्माण कार्य का प्रशिक्षण मिले; राज्य में व्यापारी, अर्थशास्त्री, वकील, इंजीनियर तथा राजनीतिज्ञ तैयार हों।

जैसा कि बताया जा चुका है, १ जनवरी, १९१६ से विश्वविद्यालय ने कार्य आरम्भ किया और इस का प्रथम उपाधि वितरण समारोह १९ अक्टूबर १९१८ को हुआ। महाराज को, जो कि विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इस अवसर पर सभा का अध्यक्ष बनाया गया और कलकत्ता के विख्यात विद्वान् सर आशुतोष मुखर्जी ने भाषण दिया। अपने भाषण में महाराज ने विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहा :

“मैं चाहता हूँ कि मैं इस सार्वजनिक अवसर पर अपनी ओर से तथा राज्य के लोगों की ओर से रियासत के दीवान सर एम० विश्वेश्वरैया के प्रति आभार प्रकट करूँ।”

उनके देश प्रेम और उनके उत्साह ने रियासत के एक स्वप्न को साकार कर

दिखाया है। उनके अग्रक परिधम से ही इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, बतः उनका नाम इस विश्वविद्यालय के साथ सदा के लिए जुड़ा रहेगा।”

उन दिनों किसी भी देशी रियासत में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इस प्रकार का यह पहला प्रयास था और लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि यह काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन दिनों परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थीं। यह तो सौभाग्य की बात थी कि महाराज ने इस सम्बन्ध में हमारी हर प्रकार की सहायता की और भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड हाउडिंग की नीति भी शिक्षा के पक्ष में थी।

## मैसूर में लोक सुधार के कार्य

जब मैं रियासत का दीवान था तब राज्य में शिक्षा, राजनीति तथा प्रशासन सम्बन्धी जो-जो सुधार किये गये थे उनका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। स्मरण रहे कि नवम्बर १९०९ में, मैसूर में, चीफ़ इंजीनियर का पद ग्रहण करते समय मैंने इस बात का आश्वासन प्राप्त किया था कि लोकनिर्माण कार्यों के अतिरिक्त मुझे रियासत में शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्रों में विकास करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मैंने महाराज से एक बार फिर कहा कि शासन प्रबन्ध के दैनिक कार्य में कोल्हू के बौल की तरह काम करते रहने से मुझे सन्तोष नहीं होता और मेरे मस्तिष्क में तो वह सब बातें घूमती रहती हैं जिनका अध्ययन मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान किया था। जब अन्य देश प्रगति की राह पर बड़ी तेज़ी से दौड़े जा रहे हैं तो क्या हमें यह शोभा देता है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और तुच्छ रूप से जीवन-यापन करते रहें ?

सो, राज्य में जो दूसरे महत्वपूर्ण विकास कार्य किये गये, यहां संक्षेप में उनका उल्लेख करना असंगत न होगा।

राज्य की ८५ प्रतिशत जनता अशिक्षित थी और लोगों के पास जोतने के लिए बड़ी थोड़ी भूमि थी। अतः कृषि उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होने की सम्भावना नहीं थी। फिर भी उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीक़े अपनाये गये।

सरकारी फ़ार्म खोले गये, खेती-बाड़ी के तरीक़ों में सुधार कर के लोगों में उसका प्रदर्शन किया गया और कृषि में काम आनेवाले औज़ारों में भी सुधार किये गये। इसके अतिरिक्त किसानों को खाद तथा अच्छी किस्म के बीज दिये गये और कृषि शिक्षा देने के लिए हवल में एक कृषि स्कूल खोला गया तथा अन्य केन्द्र स्थापित किये गये और अधिक तकावी ऋण वांटने के लिए अनुदान दिये गये। कृषि सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्रित करने का प्रयाग भी किया गया।

रियासत में बहुत से तालाब थे, परन्तु उनमें ने अधिकांश आकार में छोटे थे और उनकी मरम्मत करना ज़रूरी होना था। लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कठिन था कि वे स्वयं ही तालाबों की देखभाल और मरम्मत आदि का काम

मभावें। मैंने मारीकानव जलाशय तथा कावेरी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में सिंचाई की तुरन्त प्रणाली लागू करने का प्रयास किया, परन्तु अनपढ़ किसानों को यह समझाना मुश्किल था कि अधिक पानी देने से फसलों को विशेष लाभ नहीं होता। पानी को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने के नियमों का आज तक पालन नहीं होता। कावेरी की बाढ़ी में भी फसलों को इतना अधिक पानी दिया जाता है कि वह उल्टा फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ग्रामीण किसी प्रकार के प्रतिबन्ध को सहन नहीं करते और जिला अधिकारी भी, उनका पक्ष ले कर, पानी को नष्ट होने से नहीं रोकते। आशा है कि भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी और सिंचाई सम्बन्धी आवश्यक नियम बना कर उन्हें सस्ती से लागू किया जायगा।

## उद्योग

आजकल के समय में किसी राष्ट्र की प्रगति तथा समृद्धि उसके उद्योग-धंधों पर निर्भर है। मेरे समय में मैसूर में जो उद्योग धंधे आरम्भ किये गये थे, वह इस प्रकार हैं -

रेशम के कीड़े पालना,  
सदल का तेल बनाना,  
साबुन बनाना,  
पानु बनाने का कारखाना,  
चमड़ा रंगन का कारखाना,  
केन्द्रीय तथा जिला कारखानों की स्थापना,  
छद्म एवं ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानों की स्वीकृति,  
नये घरेलू धंधों की स्थापना,  
होटलों तथा छापाखानों की स्थापना,  
गैरसरकारी कारखानों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज देना,  
छूतवा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सहायता देना, आदि।

मैसूर का लोहे व लकड़ी का कारखाना, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन बाद में

किया जायगा, का निर्माण १९१८ में आरम्भ हो गया था। इस महत्वपूर्ण काम को शुरू करने में पूर्व तैयारी के लिए इसके बारे में जान लेनी पड़ी थी। इस कारखाने की योजना म्यांमर अगरी की इंजीनियर श्री सी० पी० पैरिन की सहायता से तैयार की गयी थी, जिन्होंने जमशेदपुर में दादा के लोहे व इस्पात कारखाने की योजना तैयार की थी।

सन् १९१४ में लेकर १९१८ तक, जब मैंने अपने पद का त्याग किया, महायुद्ध के कारण भारत सरकार नये इंजीनियरिंग उद्योग तथा कारखाने स्थापित करने के पक्ष में नहीं थी। वह चाहती थी कि देश के गारे कारीगर लॉग लड़ाई का सामान तथा हथियार बनाने में ही लगे रहें। इन परिस्थितियों में हम सिवाय भारी योजनाएं बनाने के और कर ही क्या सकते थे? सो हमने लोहे, कागज, चीनी और सीमेंट जैसे नये उद्योग स्थापित करने की योजनाएं तैयार कर के रख लीं और उन्हें कार्यरूप देने के लिए युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे।

युद्ध के कारण माल बाहर भी नहीं भेजा जा सकता था। फिर भी हमने आयात तथा निर्यात सम्बन्धी नीति की रूपरेखा तैयार कर ली। इसके पश्चात् कामर्स कालेज की स्थापना की गयी। बंगलीर निवासी प्रसिद्ध व्यापारी हाजी सर इस्माइल सैत ने व्यापार मण्डल के भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। सामान्य व्यापारियों को वाणिज्य विषयों की शिक्षा देने के लिए बंगलीर तथा कुछ तालुकों के सदर मुकामों में रात्रि पाठशालाओं का प्रवन्ध किया गया। मेरे अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में बी० काम० की कक्षाएं बन्द कर दी गयीं, परन्तु बाद में उन्हें फिर से आरम्भ कर दिया गया।

सन् १९१७ में व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल जापान में भेजा गया। इस मंडल को एशिया के उस प्रगतिशील देश में भेजने का उद्देश्य यह था कि व्यापारी वहां की व्यापार प्रणालियों का अध्ययन कर के उन्हें मैसूर में लागू करें, ताकि यहां का व्यापार भी जापान की भांति प्रगति करे।

### पानी से बिजली पैदा करने के साधनों का विकास

पहले बताया जा चुका है कि शिवसमुद्रम् में १३,००० हॉर्स पावर बिजली तैयार की जाती थी और कावेरी जलाशय का कुछ भाग बन जाने से यह बिजली

२५,००० हाँस पावर हो गयी थी। इससे कोलार की सोना खानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पहले से अधिक बिजली मिलने लगी थी। यह वृद्धि निश्चित अवस्थाओं में की गयी थी।

इस समय पानी द्वारा कुल ८३,००० हाँस पावर बिजली पैदा की जा रही है। सरकार को बिजली से प्राप्त होनेवाली आय १९११-१२ में १६.६५ लाख रुपए, १९१८-१९ में २४.२ लाख और १९४८-४९ में १.३३ करोड़ रुपए थी।

राज्य की पानी द्वारा बिजली पैदा करने की योजना में जिन दो अमरीकी इंजीनियरों की सहायता से प्रगति हुई थी, वे थे श्री एच० पी० गिंस तथा श्री एम० पी० फोविस। ये दोनों इंजीनियर जिन्होंने मंसूर में दक्षता में कार्य किया, बाद में सर्वश्री टाटा संस्थ, बम्बई की नौकरी में चले गये थे।

सिमोगा जिले में घाटावती नदी के जोग प्रपात पर बिजली पैदा करने की एक योजना तैयार की गयी और इसके लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हुआ। परन्तु यह महत्वपूर्ण व आकर्षक योजना युद्ध काल में आदिमियों तथा घन की कमी के कारण भरे रहने हुए पूरी न हो सकी। यह बड़ी खुशी की बात है कि बाद में इस योजना के कार्य में बड़ी प्रगति हुई और अब इसके द्वारा ४८,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है। अनुमान है कि जब इस योजना का कार्य पूरा हो गया तो १,२०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

## रेलो का विस्तार

जब मैं रियासत का दीवान बना तो रेल के विस्तार का निर्माण कार्य, जो पहले बन्द पड़ा था, पुनः आरम्भ कर दिया गया। रेल निर्माण के लिए श्री ई० ए० एस० रेल की मेजर एं भारत-भरकाद से प्राप्त की गयी और उन्हें रेलवे निर्माण कार्यों के लिए चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय रेल विभाग की स्थापना कर के स्थानीय इंजीनियरों तथा अन्य अधिकारियों को रेल विभाग में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मंसूर तथा दक्षिण मराठा रेलवे से मंसूर-जगलौर तथा अन्य ब्रांच लाइनों का काम सम्भाल लेने की व्यवस्था की गयी। इस सम्बन्ध में महाराज ने १० अप्रैल, १९१८ के दिन मुझे जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है :



गयी थी। ऐसा होते हुए भी १९१९-२० के वजट को, जो कि मेरे पद त्यागने के कुछ मास बाद ही विधान सभा में पेश किया गया, तत्कालीन दीवान ने 'समृद्धि वजट' के नाम से पुकारा।

## शहरों व कस्बों की हालत में सुधार

बंगलौर तथा मैसूर में भी कुछ सुधार किये गये। मैसूर नगर का विकास तो स्वर्गीय महाराज श्री कृष्णराज वाडियार बहादुर की निजी देख-रेख में हुआ था। इन दोनों नगरों की विकास योजना पर सदा दृष्टि रखी जाती थी। मेरे बाद रियासत के दीवान सर मिर्जा इस्माइल के समय में इन दोनों नगरों के विकास की ओर और भी अधिक ध्यान दिया गया। सर मिर्जा इस्माइल काफ़ी असें तक इस पद पर रहे। उन्होंने राज्य के दो मुख्य नगरों तथा अन्य कस्बों को सुधारने में तथा कस्बा आयोजन स्कीमों में विशेष दिलचस्पी ली। मैसूर में आधुनिक जल निकास योजना का काम तभी आरम्भ हो चुका था जब मैं रियासत का मुख्य इंजीनियर था।

मैसूर तथा बंगलौर नगरों का विकास रियासत के कई दीवानों, सर के० शेषाद्रि अय्यर, श्री वी० पी० माधव राव, सर मिर्जा एम० इस्माइल के संयुक्त प्रयत्नों से ही हो सका था। इन दोनों नगरों का निर्माण आधुनिक ढंग से किया गया था। सम्भवतः भारत के अन्य बड़े-बड़े नगरों में से कोई भी नगर इन दोनों नगरों की बराबरी नहीं कर सकता।

## ग्राम विकास

ग्राम विकास के क्षेत्र में सब से बड़ा काम यह किया गया कि ग्राम सुधार योजना बना कर उसे गांवों में लागू कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत गांवों में पंचायतें बना कर गांवों की सफ़ाई का काम उन्हें सौंप दिया गया। ग्रामवासियों को आस-पास के गांवों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सड़कें बनाने तथा गांवों में अन्य सुधार कार्य करने के लिए अनुदान दे कर, तथा प्रचार द्वारा, प्रोत्साहित किया गया। इन सब बातों से गांव के लोगों को बड़ा बढ़ावा मिला और उन्होंने स्वयं

गावों को माफ सुधारा रखने के अतिरिक्त आन पाग के गावों तथा कस्बों के माथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गड़के बनाने भी शुरू कर दी।

आज तक गावों की बांधी में ४६० गावों तथा कस्बों में बिजली दी जा रही है। गावों में उद्योग घरों को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

महानाद क्षेत्र की भूमि को सुधारने के लिए यहाँ भूमिनाट विकास योजना लागू की गयी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र की भूमि को सुधार कर वहाँ उत्पादन तथा लोगों की उत्पन्नता बढ़ाई जाय और मच्छरों का नाश कर के मलेरिया दूर किया जाय। मन् १९१७ में सरकार ने १०० मुठ्ठी में अधिक की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें इस क्षेत्र के भूतलगत विषय में सुधार कार्यों का ध्यान दिया गया था।

### सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न

बहुत से क्षेत्रों में विकास कार्य करने की जरूरत थी, परन्तु एक ही राज्य के मानव सीमा में और दूसरे जनता में, विशेष कर ग्रामीण जनता में, उरसाह की समी थी।

इस दिशा में सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों को माफ सुधारा रखने की व्यवस्था की गयी और उनकी देख रेख के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये गये।

पहाड़ी स्थानों के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। सबसे पहले बंगलौर में ६६ मील दूर नन्दी नामक पहाड़ी स्थल का विकास किया गया और वहाँ अधिक से अधिक पर्यटन सुविधा देने की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त बाल हाट गिरी तथा देवायों दुर्ग जैसे अन्य पहाड़ी स्थानों के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। ये दोनों स्थान अंग्रेजी अफसरों के लिए पहाड़ी स्थलों का काम देने थे। नन्दी को एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल बनाने के लिए वहाँ पर्यटकों के निवास स्थानों का सुधार किया गया तथा अन्य सुविधाएँ दी गयीं।

मंसूर नगर में नये विद्यालय घरों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से अनुदान दे कर बंगलौर में आधुनिक ढंग के हिन्दू-होटल स्थापित करने की व्यवस्था भी की गयी और मंसूर में हिन्दू-होटल के लिए आधुनिक ढंग का

एक नया भवन बनवाया गया। वंगलीर में अंग्रेजी तरीके के दो क्लब 'सेंचुरी क्लब' तथा लेडीज़ क्लब स्थापित किये गये और मैसूर में एक क्लब की स्थापना के लिए सरकार ने अपनी ओर से ज़मीन ले कर दी।

नागरिक तथा सामाजिक सम्मेलन की स्थापना करके एक समिति बनाई गयी, जिसके अध्यक्ष थे सर् के० पी० पुट्टान्ना चेट्टी।

### सामान्य कार्य

अपनी ओर से इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया कि मैसूर में उन सब संस्थाओं तथा सेवाओं को बढ़ावा दिया जाय जो कि दूसरे उन्नत देशों में प्रचलित हैं। परन्तु धन तथा साधनों की कमी के कारण इस दिशा में जो विकास हुआ, वह सीमित ही था।

मेरे समय में जो भी विकास कार्य हुए उसका श्रेय उन सब सरकारी अफसरों तथा प्रमुख समाज सेवकों को प्राप्त है जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया। यह सब विकास इसी ध्येय को ले कर किये गये थे कि राज्य के लोग प्रगति की राह पर आगे बढ़ें और सम्य लोगों का-सा जीवन व्यतीत करें।

यहां महाराजा सर श्रीकृष्णराज वाडियार बहादुर के सम्मान में कुछ कहना असंगत न होगा। वह उच्चकोटि के देशभक्त राजा थे। राज्य की प्रगति और प्रजा के हितों का उन्हें बड़ा ध्यान रहता था। वह सच्चे अर्थों में लोगों के दिलों पर राज्य करते थे। लोग उनके उच्च चरित्र का बड़ा सम्मान करते थे। राज्य की प्रगति के लिए जितने भी विकास कार्य हुए, उन सब के लिए उन्होंने अपनी ओर से पूरा-पूरा समर्थन प्रदान किया।

यद्यपि मेरी नौकरी के अन्तिम दिनों में मेरे और महाराज के बीच सरकारी मामलों में, विशेषकर विकास कार्यों के लिए अपनायी जानेवाली नीति के बारे में, कुछ मतभेद पैदा हो गये थे, फिर भी हमारे सम्बन्ध अन्त तक मैत्रीपूर्ण रहे।

२४ मई, १९१७ को महाराज ने मुझे ऊटकमंड से एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है :

“जिन हाल की घटनाओं की आपने चर्चा की है, उनके बारे में मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिये हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी मामलों

में हमारे जो भी मतभेद हैं, वे दूर हो सवने हैं। मैं आप को इस बात का विद्वान् दिलाता हूँ कि सरकारी मामलों पर मतभेद होने पर भी हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धों में कोई अन्तर नहीं आया और आपके प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, उसमें कमी नहीं होगी। आपने रियासत के लिए जो महान् सेवा कार्य किया है, उसे मैं कभी नहीं भुला सक्ता।"

## बाद की परिस्थितियां और नौकरी से ऐच्छिक अवकाश ग्रहण

### वैधानिक सुधारों पर बहस

सन् १९१७-१८ के आस-पास भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक सुधारों तथा भारत के भावी संविधान के प्रश्न पर बड़े जोर की बहस हो रही थी। इस बहस के साथ भारतीय रियासतों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। भारत के तत्कालीन रियासती सचिव श्री ई० एस० मॉन्टेग्यु १९१७ में भारत के दौरे पर आये। मैसूर में हमने एक समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बनायी कि भविष्य में मैसूर के भारत सरकार के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिए। इस समिति का अध्यक्ष महाराज को बनाया गया और मैसूर के युवराज ने भी जो समिति के सदस्य थे, इस बैठक में भाग लिया।

भारत के वाइसराय लार्ड चैम्सफ़ोर्ड तथा श्री ई० एस० मॉन्टेग्यु कुछ दिन बाद मैसूर में आये और उन्होंने प्रमुख अधिकारियों तथा भारतीय नेताओं के विचारों से वहाँ के लोगों को अवगत कराया। उस अवसर पर मैंने भी एक सभा में भाग लिया और बाद में लार्ड चैम्सफ़ोर्ड तथा श्री मॉन्टेग्यु से बातचीत की। मेरी इस बातचीत की चर्चा श्री मॉन्टेग्यु ने अपनी पुस्तक “भारत की डायरी” में इस प्रकार की है:

“मैसूर के दीवान के साथ कुछ लोग मुझसे कावेरी सम्बन्धी समझौते के बारे में बातचीत करने के लिए आये। मैसूर के दीवान यह भी चाहते थे कि रियासती राजाओं को द्वितीय सदन में सम्मिलित कर लिया जाय। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। चैम्सफ़ोर्ड ने इस बात का विरोध किया, परन्तु मैं समझता हूँ कि चैम्सफ़ोर्ड इस मामले में ग़लती पर हैं।”

यह वता देना उचित होगा कि लार्ड चैम्सफ़ोर्ड तथा श्री मॉन्टेग्यु ने वैधानिक सुधार सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफ़ारिश की कि राजाओं की

परिपद को सलाहकार समिति के रूप में स्थायी रूप से काम करने दिया जाय, जिससे वह राज्य परिपदों के साथ मिलकर अपने हितों की रक्षा कर सके।

मैं यह बना दूँ कि बीकानेर के महाराज मर गंगासिंह बहादुर मैसूर में पधार चुके थे। उन्होंने राज्य के शासन प्रबन्ध का बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। बाद में बीकानेर पहुंच कर उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है -

“आपके सुन्दर राज्य की यात्रा करके मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप का राज्य तथा उसकी सरकार यथार्थ में महान् आदर्श प्रस्तुत करने हैं। आपके महाराज, आप तथा दूसरे महकारी अफसर अपने राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि मारे भारत के लिए सराहनीय सेवा कार्य कर रहे हैं। मैंने आप से बहुत-सी बातें सीखी हैं और मुझे आशा है कि हम आगे चल कर भी आपके शासन प्रबन्ध की बहुत-सी अच्छाइयों को अपनायेंगे।”

महात्मा गांधी कई बार मैसूर की यात्रा पर आये। एक बार वह तब आये, जब मैं रियासत का दीवान था और दूसरी बार, मेरे नौकरी छोड़ कर चले जाने के नौ वर्ष बाद, भद्रावती के स्थान पर लोहे का कारखाना तथा मैसूर नगर के निकट इष्णाराज मागर जलाशय को देखने आये। उन्होंने इन दोनों कामों के बारे में कुछ ऐसी राय देने सुन रखी थी जिन पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। तब मैसूर की एक मार्जनात्मिक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा

“इष्णाराज मागर, जो संसार के बहुत बड़े जलाशयों में से एक है, अकेला ही मर विदेहेश्वरिया की कीर्ति को बढ़ाने के लिए काफी है। इसके अनिश्चित रियासत में जो अन्य उद्योग-धंधे शुरू किये गये हैं, उनमें पक्का यकीन है कि मैसूर भारत के दूसरे राज्यों में कितना आगे निकला जा रहा है और उसमें उद्यम की कितनी भावना है।”

### अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण

महकारी नौकरियों में ब्राह्मण जाति के लोगों को जो प्रभुत्व प्राप्त था, उसके विरुद्ध मद्रास में १९१७-१८ के आम-गाम बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का प्रभाव मैसूर में भी हुआ। मैं जानता था कि इस क्षेत्र में गैर-ब्राह्मण जाति के लोग उच्च शिक्षा भी कभी के कारण ही पिछड़े हुए हैं। रियासत में आने के बाद मैंने शिक्षा

भारतीय रियासतों में विकास कार्यों के रास्ते में आमतौर पर कठिनाइयाँ पेश आती हैं। इन कामों की आलोचना भी होती है। परन्तु इसे मेरा सीमाग्य कहना चाहिए कि नी वर्यों की अवधि में मैंने जो-जो काम हाथ में लिये, वह बड़े सुचारु ढंग से पूरे हो गये और उनसे सरकार को तथा लोगों को जो आशाओं से अधिक लाभ हुआ उसने आलोचना करनेवालों का मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया।

तो, इस प्रकार मेरी रियासती नौकरी के महत्वपूर्ण अध्याय की समाप्ति होती है। ९ दिसम्बर, १९१८ के दिन मैंने परिपक्व के सदस्यों, विभागीय अध्यक्षों, सरकारी सचिवों तथा अन्य अधिकारियों से, जिन्होंने मेरे साथ मिल कर बड़ी लगन से काम किया था, विदा ली। परिपक्व भवन में विदाई के समय मैंने जो भाषण दिया, उसका सारांश इस प्रकार है:

“मुझे आशा है कि यदि मैं इस बात का दावा करूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे कि दीवान का पद ग्रहण करते समय मैंने जिन उद्देश्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो सका, उन्हें कार्यरूप देने की पूरी कोशिश की गयी। गैरसरकारी क्षेत्रों में अक्सर यह कहा जाता है कि मैं फलां जाति का समर्थक हूँ और फलां जाति का विरोधी। आनेवाला समय अपने आप यह बतायेगा कि मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परन्तु मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करता कि रियासत का प्रमुख शासन अधिकारी होने के नाते मेरा सब से बड़ा कर्तव्य-रियासत के महाराज तथा रियासत की जनता के हितों की रक्षा करना था।

“मुझे दुःख है कि मेरे लक्ष्य अधूरे ही रह गये। मेरे लिए सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि बहुत से काम, जो कि पूरे किये जा सकते थे, अधूरे ही रह गये। परन्तु मैं राज्य की जनता का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी ओर से मुझे पूरा-पूरा सहयोग दिया और गत छः वर्षों में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे राज्य के प्रशासन को बट्टा लगता। मैंने देखा कि मैसूर के लोगों का व्यवहार, जिनमें राज्य की ग्रामीण जनता भी शामिल है, बड़ा ही सराहनीय रहा है; इसलिए नहीं कि शासन प्रबन्ध ने कोई विशेष कुशलता दिखायी, बल्कि इसलिए कि लोग जानते थे कि सरकार सच्चे दिल से उनके लिए सेवाकार्य करने की इच्छुक है।

“मैं उन सब देशी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों के प्रति भी आभार प्रकट

करता चाहता हूँ, जो मेरे समय में प्रभामन के प्रति बड़े उदार और निष्पक्ष रहे।”

“अन्त में मैं महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक वय-प्रदर्शक के रूप में मुझे सदा ही रियासत की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है और हर प्रकार की सहायता दी है।”

१० दिसम्बर, १९१८ के दिन मेरे पूर्व अधिकारी दीवान टी० आनन्द राव ने मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र लिखा, जिसे मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ :

“कल के अनाधारण गजट में मैंने आपकी छुट्टी जान के बारे में पढ़ा और कल शाम का ‘हेली पॉस्ट’ भी देखा, जिसमें आपका कल सचिवालय में दिया गया बिदाई भाषण छपा है। मुझे लाई मार्ले द्वारा लिखित ग्लैडस्टोन की जीवनी का एक अंश याद आ रहा है। पुस्तक का वह अंश, जिस में नीचे उद्धृत कर रहा हूँ, आप पर ठीक लागू होता था :

“आप गहरी जानते कि हम में से वे व्यक्ति, जिन्हें सबाई में विश्वास रखने वाले प्रधान मंत्री के साथ कार्य करने में अत्यधिक प्रसन्नता होती है, आपका जितना सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि हर आदमी गलतियों का पुत्र है, परन्तु जब एक आदमी की मत्त-परायणता पर पूर्ण विश्वास हो, तो इस बात में बड़ा सन्तोष होता है।”

अवकाश ग्रहण करने से पूर्व मैं छः महीनों की छुट्टी पर चला गया। छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् मेरे अवकाश प्राप्ति करने की घोषणा सरकारी गजट में इस प्रकार की गई :—

“... इस अवधि में सर एम० बिस्वेस्वरैया ने रियामत के भौतिक माधन्य में वृद्धि करने के लिए बड़ी लगन और परिश्रम से कार्य किया। दीवान के रूप में उनके शासन प्रबन्ध द्वारा शिक्षा, सिंचाई कार्य, रेल-यानागमन तथा उद्योग धर्मों का भारी विकास हुआ है। उन्होंने रियामत को प्रगति व समृद्धि की नींव पर लाकर सड़ा कर दिया। सर बिस्वेस्वरैया जहाँ भी जायेंगे, रियामत के हर जाति के लोगों की तथा रियासत के महाराज की पुनर्जागरण सदा उनके साथ रहेंगी।”

हार्डिंग के अवकाश प्राप्ति ज्ञात स्वर्गीय श्री सैठसर ने १२ फरवरी, १९२६ के ‘हिन्दू’ में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा :



भारतीय रियासतों में विकास कार्यों के रास्ते में आमतौर पर कठिनाइयाँ पेश आती हैं। इन कामों की आलोचना भी होती है। परन्तु इसे मेरा सौभाग्य कहना चाहिए कि नी वर्षों की अवधि में मैंने जो-जो काम हाथ में लिये, वह बड़े सुचारु ढंग से पूरे हो गये और उनसे सरकार को तथा लोगों को जो आशाओं से अधिक लाभ हुआ उसने आलोचना करनेवालों का मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया।

सो, इस प्रकार मेरी रियासती नौकरी के महत्वपूर्ण अध्याय की समाप्ति होती है। ९ दिसम्बर, १९१८ के दिन मैंने परिपद् के सदस्यों, विभागीय अध्यक्षों, सरकारी सचिवों तथा अन्य अधिकारियों से, जिन्होंने मेरे साथ मिल कर बड़ी लगन से काम किया था, विदा ली। परिपद् भवन में विदाई के समय मैंने जो भाषण दिया, उसका सारांश इस प्रकार है:

“मुझे आशा है कि यदि मैं इस बात का दावा करूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे कि दीवान का पद ग्रहण करते समय मैंने जिन उद्देश्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो सका, उन्हें कार्यरूप देने की पूरी कोशिश की गयी। गैरसरकारी क्षेत्रों में अक्सर यह कहा जाता है कि मैं फलां जाति का समर्थक हूँ और फलां जाति का विरोधी। आनेवाला समय अपने आप यह बतायेगा कि मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परन्तु मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करता कि रियासत का प्रमुख शासन अधिकारी होने के नाते मेरा सब से बड़ा कर्तव्य रियासत के महाराज तथा रियासत की जनता के हितों की रक्षा करना था।

“मुझे दुःख है कि मेरे लक्ष्य अधूरे ही रह गये। मेरे लिए सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि बहुत से काम, जो कि पूरे किये जा सकते थे, अधूरे ही रह गये। परन्तु मैं राज्य की जनता का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी ओर से मुझे पूरा-पूरा सहयोग दिया और गत छः वर्षों में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे राज्य के प्रशासन को बट्टा लगता। मैंने देखा कि मैंसूर के लोगों का व्यवहार, जिनमें राज्य की ग्रामीण जनता भी शामिल है, बड़ा ही सराहनीय रहा है; इसलिए नहीं कि शासन प्रबन्ध ने कोई विशेष कुशलता दिखायी, बल्कि इसलिए कि लोग जानते थे कि सरकार सच्चे दिल से उनके लिए सेवाकार्य करने की इच्छुक है।

“मैं उन सब देशी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों के प्रति भी आभार प्रकट

करना चाहता हूँ, जो मेरे समय में प्रज्ञामन के प्रति बड़े उदार और निष्पक्ष रहे।”

“अन्त में मैं महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक पथ-प्रदर्शक के रूप में मुझे सदा ही रियासत की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है और हर प्रकार की सहायता दी है।”

१० दिसम्बर, १९१८ के दिन मेरे पूर्व अधिकारी दीवान टी० आनन्द राव ने मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र लिखा, जिसे मैं महा उद्धृत करता हूँ :

“कल के असाधारण गजट में मैंने आपकी छुट्टी जाने के बारे में पत्रा और कल शाम का ‘डेली पोस्ट’ भी देखा, जिसमें आपका कल सचिवालय में दिया गया विदाई भाषण छपा है। मुझे साइड मालों द्वारा लिखित ग्लैंडस्टोन की जीवनी का एक असा याद आ रहा है। पुस्तक का वह अधः, जिसे मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ, आप पर ठीक लागू होता था :

“आप नहीं जानते कि हम में में वे व्यक्ति, जिन्हें सचार्ड में विद्वान रखने वाले प्रधान मन्त्री के माय कार्य करने में अत्यधिक प्रमत्तता होती है, आपका कितना सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि हर आधुनिक गलतियों का पुतला है, परन्तु जब एक आदमी की मृत्यु-परम्परा पर पूर्ण विश्वास हो, तो इस बात से बड़ा सन्तोष होता है।”

अवकाश ग्रहण करने से पूर्व मैं छः महीनों की छुट्टी पर चला गया। छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् मेरे अवकाश प्राप्त करने की घोषणा सरकारी गजट में इस प्रकार की गई:—

“... इस अवधि में सर एम० विश्वेश्वरैया ने रियासत के भौतिक साधनों में वृद्धि करने के लिए बड़ी लगन और परिश्रम से कार्य किया। दीवान के रूप में उनके शासन प्रबन्ध द्वारा शिक्षा, मिचार्ड कार्यों, रेल-मातायान तथा उद्योग संघों का भारी विकास हुआ है। उन्होंने रियासत को प्रगति व समृद्धि की नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। सर विश्वेश्वरैया जहाँ भी जायेंगे, रियासत के हर जाति के लोगों की तथा रियासत के महाराज की शुभकामनाएँ सदा उनके साथ रहेंगी।”

हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज स्वर्गीय श्री सैटलर ने १२ फरवरी, १९२६ के ‘हिन्दू’ में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा :

क्योंकि लोहे की क्रीमर्तें गिर कर पहले से आधी रह गयी थीं। इस अवस्था में महाराज ने रियासत के तत्कालीन दीवान श्री बनर्जी को मेरे पास बम्बई भेजा। महाराज का कहना था कि मैं आकर इस कारखाने का काम संभालूँ और इसकी व्यवस्था करने में सरकार की सहायता करूँ। सो मुझे इस काम को लेना पड़ा, परन्तु मैंने बताया कि खातों की जांच करने के अतिरिक्त मेरे काम में किसी को अधिक दखल देने का अधिकार नहीं होगा। कारखाने के काम को ठीक रास्ते पर लाने के लिए एक व्यवस्थापक मण्डल बना कर मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार मैं कारखाने को साढ़े छः वर्षों तक चलाता रहा। इस अवधि में कारखाने के बारे में बहुत-सी निराशावादी भविष्यवाणियाँ की गयीं। सर आल्फ्रेड चैटर्टन ने, जो पहले रियासत की नौकरी में रह चुके थे, २२ मई, १९२५ के दिन लंदन में रॉयल सोसायटी ऑफ़ आर्ट्स के सामने भाषण देते हुए कहा कि लोहे के इस कारखाने को बन्द करने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं। इन सब निराशावादी उक्तियों के बावजूद, तथा कच्चे लोहे और विक्री के लिए तैयार किये जानेवाले लोहे के माल के भावों में और अधिक कमी हो जाने पर भी, कारखाने के काम में प्रगति होती रही। कारखाने की कार्यकुशलता भी पहले से बहुत बढ़ गयी।

२४ सितम्बर, १९२९ के दिन कारखाने के अध्यक्ष पद से मुक्त होते समय मैंने कारखाने की स्थिति के बारे में जो भाषण दिया उसका सारांश इस प्रकार है :

“गत छः वर्षों में कारखाने के काम की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कारखाने के लिए कच्चा माल इकट्ठा करने तथा ढोने के खर्च में भारी कमी हुई है और माल तैयार करने के खर्च में भी ५० प्रतिशत की कमी हुई है। स्थानीय लोगों को कारखाने में विभिन्न पदों पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया है तथा शासन प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों को कारखाने में लागू किया गया है। धीरे-धीरे कारखाने को इस अवस्था में पहुँचा दिया गया है कि उनसे अब लाभ की आशा की जा सकती है।”

श्री सी० पी० पैरिन, जिन्होंने इस कारखाने का नक्शा तैयार किया था, जनवरी, १९२७ में इसे देखने आये। वह जमशेदपुर में टाटा इस्पात कारखाने में सम्बन्धित किसी काम से भाग्य आये थे और वहाँ से वह कारखाना देखने मैगूर भी चले आये। मेरी उनसे भेंट नहीं मेली, क्योंकि उन दिनों मैं यूरोप में था। कारखाने

के निरीक्षण करने के पश्चात् उन्होंने १९ जनवरी, १९२७ को तार द्वारा लंदन में मुझे निम्नलिखित सन्देश भेजा :

“जो व्यवस्था आपने भड़ी की है तथा उससे जो फल प्राप्त हो रहा है, उस सब के लिए आपको बधाई है। कारखाने के काम को देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई है और यह बात आज शाम मैं महाराज से भी कहूँगा।

आपका शुभचिन्तक—‘गैरिन’

बाद में १२ फरवरी, १९२७ के दिन महाराज ने मुझे दिल्ली में एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है :

“मैं समझता हूँ कि छोटे के कारखाने का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। थोड़े दिन पहले जब श्री पैरिन मैसूर आये थे तो मेरी उनमें भेंट हुई थी। उन्होंने कारखाने की व्यवस्था देख कर बड़ा मन्तोष प्रकट किया था। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था कि आप मारे अमरीकन कारीगरों को हटा कर उनको जगह पर अपने आदमियों से काम ले रहे हैं। यह एक ऐसी सफलता है जिसके लिए रियामत को गर्व होना चाहिए।”

मैंने सितम्बर, १९२९ में कारखाने के व्यवस्थापक मटल के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के कारणों का सम्बन्ध कारखाने के काम से नहीं था।

मेरे त्यागपत्र देने पर महाराज ने ६ अक्टूबर, १९२९ के दिन मुझे एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है :

“गिछे माझे छ. वर्षों में आपने कारखाने के बिक्राम के लिए जो कार्य किया है, मैं उसकी सराहना बिचे बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आपने जो महान् कार्य किया है, उसकी प्रशंसा मुझसे अधिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता।”

मर मिर्बा इन्माइल ने, जो उस समय रियामत के दीवान थे, मुझे एक पत्र इस प्रकार लिखा :

“यह कहने में बरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि आप जैसे योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति के बिना कारखाने की बड़ी बुरी दशा होगी और मैं समझता हूँ कि यह अब तक बन्द हो गया होगा। आपने कारखाने के अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी में अपना कर्तव्य पालन किया।”

मेरे त्यागपत्र देने की तबत मुनवर अमरीकी मनाहवार इलीनोय थी पैरिन,

ने २५ नवम्बर, १९२९ के दिन न्यूयार्क से एक पत्र लिखा। पत्र इस प्रकार है :

“मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मैसूर राज्य के लोहा कारखाने के व्यवस्थापक मंडल से आपके त्यागपत्र देने की खबर सुन कर मुझे कितना दुःख हुआ है।

“आपने कहा था कि कारखाने के निर्माण में हमने जो दिलचस्पी ली उससे कारखाने को बड़ा लाभ हुआ। परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि आप इस काम को अपने हाथ में न लेते तो कारखाना कब का बन्द हो गया होता। आपके द्वारा भेजे हुए कागजात को हमने बड़ी दिलचस्पी से देखा और मुझे आशा है कि लोहे के भावों में परिवर्तन होने पर कारखाने को बहुत लाभ होगा और कारखाना बनाने की योजना लाभदायक सिद्ध होगी।

“जहां तक आपका सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन के विस्तृत क्षेत्र में आप जैसे लोग बहुत कम देखे हैं। मैं आपके नैतिक चरित्र, देशभक्ति तथा उच्च आदर्शों का ही नहीं, बल्कि आपकी इंजीनियरिंग योग्यता का भी सम्मान करता हूँ।”

जनवरी, १९५० में, यानी कारखाने के काम से अलग होने के २० वर्ष बाद, राज्य के उद्योग मन्त्री के कहने पर, मैं उस कारखाने को देखने के लिए गया। इस अवसर पर मैंने कारखाने की स्थिति के बारे में जो भाषण दिया, वह इस प्रकार है :

“सन् १९४९ तक इस कारखाने में कुल १.६९ करोड़ रुपए का माल तैयार होने लगा था और उससे सरकार को १३.१ लाख रुपए की आमदनी होने लगी थी। सरकार ने कारखाने पर जितनी पूजी लगायी थी, वह उसे मूल्य-हानि निधि के रूप में वापस मिल चुकी है।

“जैसे-जैसे कारखाने का विस्तार तथा विकास होगा, उस पर लगायी गयी पूंजी की रकम ५ करोड़ रुपए तक पहुँच जायेगी। आया है कि कारखाने का नारायण काम पूरा हो जाने के बाद उसने कुल ५ करोड़ रुपए की कीमत का माल बनाना आरम्भ हो जायगा और सरकार को उसने ५० लाख रुपए वार्षिक की आमदनी होने लगेगी।”

## श्री जय चामराजेन्द्र व्यावसायिक संस्थान

जब मैं कारगाने के काम से अलग हुआ तो मुझे साढ़े छ वर्षों के वेतन के रूप में मिलनेवाले राशम अच्छी खासी हो गयी। मैंने यह रकम सरकार को लौटाते हुए यह प्रार्थना की कि उम से बंगलौर में एक व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की जाय। मैंने इस संस्थान की योजना तैयार करके सरकार को भेज दी। सरकार ने, जिसके सीवान श्री एन० माधव राव थे, इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस संस्थान को स्थापित करने के लिए अपनी ओर से भी एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने की तैयारी हो गयी।

मेरे मुताब पर रियामन के तत्कालीन महाराजा ने मेरे इस मुताब को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया कि संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाय। मैं यह संस्थान आज कल श्री जय चामराजेन्द्र व्यावसायिक संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है।

## कावेरी नहर समिति

जहां तक कावेरी जलाशय योजना का सम्बन्ध है, मैंने देखा कि सरकार मेरे द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार ही योजना के काम को आगे बढ़ाना चाहती थी और इस काम की हर अवस्था में मेरी सलाह ली जानी थी। जून, १९२४ में महाराज ने मुझे एक पत्र लिख कर यह आशा प्रकट की कि मैं इस योजना के काम में सिलवप्पी लेता रहूंगा, क्योंकि यह बहुत हद तक मेरी अपनी योजना थी।

सरकार की इच्छानुसार कावेरी घाटी में मिर्चार्ड के बिकास हेतु कावेरी जलाशय तथा नहर व्यवस्था के निर्माण तथा संरक्षण संबंधी सुझाव देने तथा मिर्चार्डों के लिए स्थापित समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया।

समिति द्वारा पेश की गयी योजना सरकार ने मंजूर कर ली और मैं समय-समय पर वहां जा कर नहरों तथा मुंखों के निर्माण कार्य की देख-भाल करना रहा।

बम्बई प्रान्त में नीला नहर पर लागू की गयी मिर्चार्ड की सफ़ा प्रणाली को यहां भी लागू कर दिया गया और उसकी देख-भाल रियामन के थॉम-ट्रेनिजर के० आर० मेसाचार को सौंप दी गयी।

महाराजा सागर योजना मिर्चार्ड तथा बिजली की सम्मिलित योजना थी,

और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इससे सरकार को अब प्रत्यक्ष और परोक्ष आय के रूप में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए वार्षिक की आमदनी हो रही है।

सन् १९४८-४९ में राज्य के भूतपूर्व चीफ-इंजीनियर तथा तत्कालीन विशेष मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार सरकार को इस योजना पर लगायी गयी पूंजी पर, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आय के रूप में, १५ प्रतिशत प्रतिफल की प्राप्ति हो रही थी।

### बंगलौर की नयी जल-वितरण योजना

बंगलौर की पुरानी जल-वितरण योजना से नगर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थीं। मेरे सुझाव पर सरकार ने अधिक जल देने की नयी योजना तैयार करने के लिए एक समिति बनायी और मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति ने ३०,००० लाख घनफुट पानी जमा करने के लिए एक जलाशय बनाने की तजवीज पेश की। इस जलाशय से १ करोड़ गैलन साफ़ किया हुआ पानी प्रतिदिन बंगलौर नगर को दिया जाना था।

### मैसूर में मोटर कारखाना खोलने का प्रयास

सन् १९३५ में मैं अपनी यूरोप तथा अमरीका यात्रा के दौरान एक मोटर कारखाने की परियोजना तैयार करके लाया था। जैसा कि बाद में २६वें अध्याय में बताया जायगा, भारत सरकार ने युद्ध के कारण इस कारखाने को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। इस कारखाने को बंगलौर में खोलने की तजवीज हुई और मैसूर सरकार ने इसके लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया। रियासत के दीवान सर मिर्जा इस्माइल इम उद्योग को शुरू करने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्होंने मेरी रिपोर्ट को दोबारा प्रकाशित किया। अमरीका का किसान कार्पोरेशन कारखाना बनाने के काम में हाथ बटाने तथा सहायता देने के लिए तैयार था। जब यह सब तैयारी हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने मैसूर के रेज़िडेंट से कह कर महाराज को इस तजवीज की मंजूरी देने से रोक दिया। अतः इस काम को वहीं बन्द कर देना पड़ा।

## हिन्दुस्तान हवाई जहाज कारखाना

मैंने अपनी विदेश यात्रा में यूरोप तथा अमरीका के तमाम बड़े-बड़े मोटर कारखानों को देखा और भारत छोड़ कर १९३६ में महा मोटर कारखाना खोलने के लिए एक योजना तैयार कर के उसे प्रकाशित किया। बम्बई के श्री बालचन्द्र हीराचन्द इस उद्योग को शुरू करना चाहते थे। उनके कहने पर बम्बई की कांग्रेस सरकार ने १९३६ में उद्योग विभाग के निदेशक श्री पी० वी० अडवानी को तकनीकी सलाहकार के रूप में श्री बालचन्द्र के साथ अमरीका भेजा।

लौटते समय हवाई जहाज में श्री अडवानी की मुलाकात हवाई जहाजों के जानकार श्री टक्यू० डी० पावले, जो अमरीका के रहनेवाले थे और चीन जा रहे थे, से हो गयी। बातों-बातों में श्री अडवानी ने श्री पावले से भारत के लिए हवाई जहाजों के निर्माण की एक योजना तैयार करके देने को कहा और श्री पावले ने योजना तैयार कर दी। यह योजना श्री बालचन्द्र ने भारत के सेनापति को भेज दी और कहा कि इस उद्योग को आरम्भ करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ दी जायें। छः महीनों तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उनकॉ की दुर्घटना के पश्चात् अंग्रेजी सरकार चैती और उसने भारत में हवाई जहाज बनाने का कारखाना खोलने की 'छरुत समझी। सो बगलौर में, श्री पावले की देख-रेख में, हवाई जहाज बनाने का कारखाना खोलने की व्यवस्था की गयी और सर्वश्री बालचन्द्र हीराचन्द्र एड कंपनी को इसका मैनेजिंग एजेंट नियुक्त कर दिया गया।

कारखाने का निर्माण श्री बालचन्द्र ने बड़ी मफलतापूर्वक किया। बाद में भारत सरकार ने, मैसूर सरकार की हिस्सेदारी में, इस कारखाने की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। कई कारणों से, शायद भारतीय प्रबन्धकार्य में अविश्वास होने के कारण, हवाई जहाज बनाने का काम एक लम्बे अर्से तक धन्द रहा। आशा है कि भविष्य में इस कारखाने से पूरा-पूरा लाभ उठाया जायगा और जनता तथा सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कारखाने में हवाई जहाजों का निर्माण शुरू हो जायगा।

## ग्रामो में उद्योग स्थापित करने की योजना

अखिल भारतीय निर्माता संघटन के अध्यक्ष पद पर काम करने समय मैंने, १९४६ में, ग्रामो के उद्योगीकरण के लिए एक योजना तैयार करके भारत सरकार



को पेश की। भाग्य सरकार ने उस योजना में अपनी ओर से कोई भी सिकारिश किये बिना उसे तमाम राज्य सरकारों के पाग भेज दिया।

मैसूर सरकार ने योजना को तुरन्त स्वीकार करके इसे राज्य के दो जिलों में लागू कर दिया। तजवीज यह थी कि यदि इस से इन जिलों को लाभ हुआ, तो यह राज्य के सारे देहाती इलाकों में लागू कर दी जायगी।

इस नये काम को चालू हुए अभी छः महीने ही हुए हैं। इस कार्य को मेरे परामर्श के अनुसार राज्य के उद्योग विभाग के एक अधिकारी बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इस दिशा में जो प्रगति हुई उसके अन्तर्गत कोई नये उद्योग भी स्थापित किये गये। इन बातों को देखने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं रहा।

## सलाहकार इंजीनियर के रूप में किये गये कार्य

इस अध्याय में उन सब कामों की चर्चा की गयी है जो कि मैंने सरकारी नौकरी में अवकाश प्राप्त करने के बाद एक सलाहकार इंजीनियर के रूप में, किये। इस प्रकार के कामों को चार श्रेणियों में रखा जा सकता है

१. बम्बई तथा कराची के नगर निगमों के शासन प्रबन्ध, धन सवधी कार्यों, नागरिक सुधार तथा अन्य विकासों के लिए सलाहकार के रूप में;
२. बहुत से शहरों तथा कस्बों के लिए जल-वितरण योजनाएं तैयार करना,
३. कुछ नगरों तथा कस्बों के लिए जल-निकास योजनाएं तैयार करना,
४. अन्य विशेष कार्य।

प्रथम महापुरुष के सम्प्राप्त होने ही बम्बई नगर निगम में नगर के विकास तथा विस्तार की बड़ी-बड़ी योजनाएं बना डाली और उन्हें कार्य रूप देने के लिए दिनांक ताल कर लक्ष्य करना शुरू कर दिया। परन्तु १९२२-२३ में, जब स्यापार में मन्दी आरम्भ हुई तो, योजनाओं के लक्ष्यों में भारी कमी बरनी पड़ी और बर्नचारियों की छटनी के लिए एक समिति बनायी गयी। समिति के बहने पर हम काम में सहायता देने के लिए निगम में मुझे बुला भेजा। मुझे कहा गया कि मैं लक्ष्य कम करने तथा निगम के शासन प्रबन्ध में सुधार करने के लिए सुझावों की एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कर के दूं।

मैंने वहीच देड महीना लगा कर हम सम्मग्य में एक रिपोर्ट तैयार कर दी। इस रिपोर्ट में निगम के कुछ विभागों में बर्नचारियों की छटनी कर के १२ में १५ माना गया की बर्नच करने की सिफारिश की गयी थी। निगम ने १७ जुलाई, १९२४ को मेरी समाम सिफारिशों मान कर उन्हें बर्नचन देना शुरू कर दिया।

मैंने अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ जनवरी, १९२५ के दिन वेद की। तब तब मेरी पत्नी। रिपोर्ट को ब्याबन्धित रूप दे कर, ११-२३ मार्च १९२५ को बर्नच की जा चुकी थी। अन्तिम रिपोर्ट दो भागों में थी। पहले भाग में नगर की आर्थिक

आवश्यकताओं तथा जनोपयोगी कार्यों पर प्रकाश डाला गया था और ब्रम्बई नगर के विस्तार के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। रिपोर्ट के दूसरे भाग में कर्मचारियों की छटनी करने तथा इंजीनियरिंग विभाग का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुझाव दिये गये थे।

शासन प्रबन्ध में ये दो महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये. ( १ ) विभागीय अध्यक्षों को शासन प्रबन्ध के स्थानिक अधिकार दे दिये गये, और ( २ ) शासन प्रबन्ध पर नियन्त्रण रखने के लिए अंग्रेजी तरीके की एक कार्यवाहक समिति बना दी गयी।

पश्चिम के बड़े-बड़े नगरों, विशेषकर अमरीका के नगरों की भांति, एक म्यूनिस्पल अनुसंधान कार्यालय स्थापित करने की सिकारिश की गयी। इस कार्यालय का उद्देश्य निगम के काम में कार्य-कुशलता लाना, राजस्व में वृद्धि करना, खर्च को घटाना तथा कर की दर को कम करना था। शहर में नवयुवकों को तकनीकी तथा वाणिज्य शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया गया और नये कारखानों की स्थापना के लिए कर माफ़ी की व्यवस्था की गयी, ताकि धन उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले। कारीगरों के निवास स्थानों की व्यवस्था करने के सुझाव भी दिये गये। यह भी कहा गया कि ब्रम्बई नगर निगम की ओर से ब्रम्बई के उद्योग-धंधों को कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही। और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि ब्रम्बई के पास एक उद्योग क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए।

पानी, गैस तथा बिजली जैसी जनोपयोगी सेवाओं पर, जिनमें पानी को छोड़ कर बाक़ी सेवाओं की व्यवस्था गैर सरकारी कम्पनियों के हाथ में थी, नगर निगम द्वारा सख्ती से नियन्त्रण रखने पर बल दिया गया।

नगर के उत्तम विकास के लिए यह आवश्यक था कि इस दिशा में काम करने वाले तमाम अभिकरण समान उद्देश्यों को ले कर आगे बढ़ें। यदि जनता को नयी योजनाओं के उद्देश्यों तथा उसकी उपयोगिता के बारे में पूरी-पूरी जानकारी देने की व्यवस्था की जाय तो विकास कार्यों को बहुत अधिक बढ़ावा मिल सकता है। इस बारे में यह सुझाव दिया गया कि सरकार से एक केन्द्रीय मण्डल बनाने को कहा जाय, जिसमें अन्य कई प्रतिनिधियों के साथ उपनगरों के स्थानीय अधिकारी भी हों। बताया जाता था कि इंग्लैण्ड में लोग नगरपालिकाओं की योजनाओं में बड़ी रुचि लेते थे। अन्य देशों में भी जनता द्वारा की गयी जांच तथा आलोचना

नगर योजनाओं के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती थी। ख्याल था कि यदि केन्द्रीय मण्डल तीन महीनों में एक बार, सप्ताह भर के लिए, बैठक बुला कर नगर में हो रहे विभिन्न योजना कार्यों के बारे में शहर के प्रमुख व्यक्तियों तथा जानकारों के विचार जानने की व्यवस्था करे, तो यही बहुत होगा।

### कराची नगरपालिका का शासन प्रबन्ध

कराची नगरपालिका के अध्यक्ष ने २६ जुलाई, १९२४ को एक पत्र लिख कर मुम में कहा कि मैं कराची नगरपालिका की आर्थिक व्यवस्था की पूरी जांच करके उसमें सुधार करने तथा छुटनी करने के बारे में सुझाव दूँ। बाद में मुम में नगरपालिका के विभिन्न विभागों का पुनर्गठन करने के बारे में सलाह मांगी गयी। मैंने छ सप्ताह लगा कर नगरपालिका के धाम्न प्रबन्ध में सुधार करने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर के दी, जिसका शीर्षक था 'कराची नगरपालिका की आर्थिक तथा प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण और सुझाव'। रिपोर्ट उस प्रकार के नगर सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी थी, जिस प्रकार का सर्वेक्षण अमरीका तथा कनाडा जैसे देशों में किया जाता है और जिसमें नगर की प्रमुख आवश्यकताओं की मोटी-मोटी बातें तथा उन्हें पूरा करने के बेहतरीन तरीकों के बारे में सुझाव और सिफारिशें थी। रिपोर्ट में नगरपालिका की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया गया था और उसके विभिन्न विभागों के काम की आलोचना की गयी थी। इसके धतिरिक्त भावी योजनाओं के बारे में सुझाव भी दिये गये थे। कर्मचारियों की छुटनी से नगरपालिका को ३.६५ लाख रुपए की बचत होने की सम्भावना थी। नगरपालिका में लोकनिर्माण समिति तथा भण्डार समिति की स्थापना करने की सिफारिश की गयी। यह भी बताया गया कि कराची नगरपालिका की आर्थिक स्थिति भारत के अन्य शहरों की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। जहां तक उनके बारे में की गयी आलोचना का सम्बन्ध है, रिपोर्ट में कहा गया, "लोग कहते हैं कि नगरपालिकाओं का पैसा बर्बादी के गड्ढे में जा रहा है, लेकिन यह काम इतनी भ्रष्ट गति में होता है कि बर्बादी की गोबन ही नहीं आती।" यह शब्द मुझ के पदचान् एक अमरीकी ने अफेन्दी अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में कहे थे।

के पुनर्निर्माण के बारे में परामर्श देने के लिए मुझे दो तीन बार महानगर जाने का अवसर प्राप्त हुआ।

जेदराबाद (मिर्जा) नगरपालिका की प्रार्थना पर मैंने मिर्जा नदी पर जल गाँव बनाने वाले कुओं का नक्शा बना कर दिया।

मुझे दो तीन बार बम्बई नगर की जल-वितरण योजना के बारे में सुझाव देने के लिए बम्बई भी जाना पड़ा। एक बार एक 'म्यूनिस्ट्रियल इंजीनियर' ने मुझे इस काम में सहायता दी।

नागपुर शहर की जल-वितरण योजना के लिए निम्नगामी नदी का जल प्राप्त करने का सुझाव भी मैंने दिया था। इस काम के लिए मैंने तीन सप्ताह नागपुर में रहा। इस योजना को कार्यान्वयन देने के लिए एक समिति बना दी गयी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति मैंने ही की थी।

गोवा सरकार के कहने पर मैंने गोवा जाकर वहाँ के बन्दरगाह के लिए एक जल-वितरण योजना तैयार कर के दी।

राजकोट नगरपालिका की प्रार्थना पर मैंने वहाँ के जलाशय का पुनर्निर्माण करने की तजवीज पेश की। जलाशय के कच्चे बाग में दरारें पड़ गयी थीं।

भावनगर शहर की जिस जलाशय से पानी दिया जाता था, उसका पुनर्निर्माण करके उसे पहले से बड़ा कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त बम्बई सरकार की नौकरी में रहते हुए तथा अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्, मुझे बड़ीदा, सांगला, मोरवी, पंडरपुर तथा अहमदनगर जैसे कई अन्य नगरों की जल-वितरण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सुझाव देने के अवसर प्राप्त हुए। यह पहले बताया जा चुका है कि जिस समिति ने बंगलीर नगर की जल-वितरण योजना तैयार की थी, उसका मैं अध्यक्ष था।

### आधुनिक जल-निकास योजनाएं

सन् १९०८ में मैंने पूना नगर के लिए एक आधुनिक पम्पिंग मलमार्ग योजना तैयार करके दी। मलमार्ग निर्माण करने का काम एक यूरोपियन इंजीनियर को सौंप दिया गया।

हैदराबाद नगर (दक्षिण) की जल-निकास योजना का काम भी मेरी देख रेख में हुआ था।

धुलिया नगर की जल-निकास योजना भी मैंने ही १८९० में तैयार करके दी थी।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गवखर तथा अदन की जल-निकास योजनाएं भी मैंने तैयार करके दी थी।

ईरीर की जल-निकास योजना का कार्य भी कुछ समय तक मेरी देख रेख में चलता रहा था।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मंसूर नगर की जल-निकास योजना उस समय तैयार की गयी थी, जब कि मैं रियासत का चीफ इंजीनियर था।

पाठकों के लिए शायद यह बात रुचिकर हो कि जब मैं १९०८ में यूरोप की यात्रा पर गया, तब मैंने कुछ ऐसे नगर देखे जिनकी जल-निकास व्यवस्था धड़ी ही उन्नत थी। मिलान, पैरिस, ब्रुसेल्स और लंदन में मैंने गहरे जमींदोज मल-मार्गों में जा कर उनकी बनावट का निरीक्षण किया था। उन अवसरों पर मल-मार्गों में प्रकाश तथा वायु का संचालन करने की विधेय व्यवस्था की गयी थी।

### अन्य विशेष कार्य

उड़ीसा में मैंने बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी एक रिपोर्ट तैयार कर के दी। यह रिपोर्ट महात्मा गांधी के कहने पर तैयार की गयी थी। एक कांग्रेसी नेता श्री निरयानन्द कानूनगो उस समय उड़ीसा में लोक-निर्माण कार्यों के मन्त्री थे। पहले मैंने उड़ीसा जाकर, अप्रैल, १९३८ में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और फिर एक रिपोर्ट तैयार कर के दी। मैंने सुझाव दिया कि इस काम के लिए दो इंजीनियरों तथा कुछ स्थानीय अधिकारियों की एक समिति बना दी जाय। परन्तु उड़ीसा राज्य सरकार के पाम पैसे की कमी होने के कारण इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। अब आजकल, केन्द्रीय सरकार की सहायता से, महानदी के ऊपरी भागों में 'हीराकुड' नामक अलासय का निर्माण किया जा रहा है।

सन् १९४७ में, भद्रास तथा हैदराबाद (दक्षिण) सरकार के कहने पर, मैं पुनश्च बांध का निर्माण कार्य देखने के लिए गया। किसी एक इंजीनियरिंग

प्रश्न को ले कर, इन दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियरों के बीच मतभेद हो गया था और मुझे उसके बारे में सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। बातचीत के पश्चात् इस सम्बन्ध में फ़ैसला हो गया जो दोनों दलों को मान्य था। भोपाल के नवाब के कहने पर मैंने, भोपाल नगर में बिजली पानी की सप्लाई के मामले की जांच पड़ताल की तथा उपयुक्त प्रस्ताव पेश किये।

सीराष्ट्र में पानी जमा करने के लिए कई जलाशयों का निर्माण होना था। इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सीराष्ट्र सरकार ने मुझे बुलावा भेजा और १९४९ में मैं वहां गया।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने हैदराबाद (दक्षिण) तथा इंदौर जैसे नगरों के निर्माण कार्य के लिए भी सुझाव दिये थे।

बम्बई नगर के लिए पेश की गयी मेरी एक तजवीज़ की चर्चा करते हुए बम्बई के गवर्नर लार्ड सिडनहाम ने बम्बई में अंधेरी के नये बाजार का उद्घाटन करते समय कहा :

“... और अब मैं साल्सैट के सामान्य विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिसमें मेरी विशेष दिलचस्पी है। इस प्रश्न की ओर सब से पहले मेरा ध्यान श्री विश्वेश्वरैया की एक रिपोर्ट द्वारा आकृष्ट हुआ था और फिर बाद में मैंने इस योग्य इंजीनियर के साथ इस सम्बन्ध में स्वयं बातचीत की।”

## सरकारी तथा सार्वजनिक समितियों में

सरकारी नौकरी के दौरान में मुझे कई समितियों में काम करने का अवसर मिला, परन्तु इस पुस्तक में मैं केवल उन प्रमुख समितियों का ही उल्लेख करूँगा जिनमें मैंने, सरकारी नौकरी से अवकाश लेने के बाद, एक सदस्य या अध्यक्ष के रूप में काम किया।

### बम्बई तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा समिति, १९२१-२२

नौकरी छोड़ने के बाद मुझे सब से पहले जिस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह थी तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा समिति (१९२१-२२)। यह समिति बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त की गयी थी। सन् १९२० में माटफोर्ड सुधारों के लागू किये जाने के तुरन्त बाद एक कांग्रेसी नेता को शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस समिति में १० यूरोपियन और ७ भारतीय सदस्य थे। मुझे समिति का अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया। समिति का उद्देश्य बम्बई प्रेजीडेंसी में, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा के लिए, वर्तमान साधन-सज्जा की जाँच पड़ताल करना तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए व्यापक योजना बनाना था। रिपोर्ट में समिति के कामों के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप में यह कहा गया था कि इसे इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के सुझाव देना है जिससे प्रेजीडेंसी के विभिन्न उद्योगों और धंधों के लिए व्यापारिक संस्थाओं में उच्च पदों को सम्भालने में उनके संगठकों तथा विद्वानों को सहायता मिल सके और प्रोन्नत, अधीक्षक तथा तकनीकी महायुक्तों आदि के अधीन पदों के लिए एक वर्ग तैयार हो सके। इस जाँच पड़ताल के पहले दौर में सब सदस्यों ने बड़े सहयोग से कार्य किया और हमने एक सर्वसम्मति प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर ली।

इस काम में लगभग एक वर्ष लगा, लेकिन, काम के आगे बढ़ने पर, बम्बई के तत्कालीन गवर्नर ने एक भेंट में मुझ से कहा कि मुझे शिक्षाधियों के प्रशिक्षण



के सम्बन्ध में सुझाव दे कर ही सन्तोष कर लेना चाहिए। मुझे यह बात रुचिकर नहीं लगी। मैं और समिति के दूसरे भारतीय सदस्य अल्पसंख्या में थे, फिर भी हमने अपनी बात पूरी कही और यह सिफारिश की कि एक तकनीकी संस्थान स्थापित करने के साथ साथ उन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाय जो तकनीकी शिक्षा के लिए जरूरी हैं। लेकिन अन्त में सभी यूरोपियन सदस्य, एकमत होकर ऐसे सुझावों के विरोधी हो गये, जिनका विस्तार किसी भी रूप में स्थायी दिखाई पड़ता था। यह रिपोर्ट दो भागों में थी। एक भाग यूरोपियन सदस्यों का था और दूसरा भारतीय सदस्यों का। मैंने यह रिपोर्ट अपनी देख-रेख में इसलिए तैयार करायी थी जिससे सभी सदस्य इसे मान लें। लेकिन यूरोपियन सदस्यों ने, एकमत होकर, रिपोर्ट को अपनी इच्छानुसार बदल दिया। भारतीय सदस्यों ने मेरा पूरा मसौदा स्वीकार कर लिया, लेकिन हम लोग अल्पसंख्या में थे।

हालांकि समिति की नियुक्ति प्रान्त की नवसंगठित विधान सभा की इच्छा से हुई थी, परन्तु ल डे लॉयड ने मुझसे जो कुछ कहा था, उससे यह स्पष्ट था कि बम्बई सरकार का उच्चतर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का कोई विचार नहीं है। वाद में मुझे लगा कि मैंने अपना लगभग एक वर्ष योंही नष्ट कर दिया।

## रासायनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय समिति

जनता को इस बात पर बड़ी निराशा हुई कि समिति के बहुत परिश्रम करने के बाद भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। बम्बई विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी इससे बड़ी निराशा हुई, लेकिन वे जानना चाहते थे कि क्या विश्वविद्यालय अपने माधनों द्वारा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कुछ कर सकता है? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा समिति ने यह सिफारिश की थी कि बम्बई विश्वविद्यालय को अपने यहां एक तकनीकी मंत्रालय स्थापित करना चाहिए और बम्बई नगर में एक तकनीकी कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के अधिकारी इस तर्जवीज को कार्य रूप देना चाहते थे, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होने से पूर्व, बम्बई सरकार ने विश्वविद्यालय में सुधारों के

लिए समिति नियुक्त कर दी। इस समिति ने भी तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा समिति की सिफारिशों से अपनी सहमति प्रकट की।

मार्च, १९३० में बम्बई विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार किया और श्री के० एम० मुन्शी के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें मेरी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का मुन्ताव दिया गया था। समिति से यह कहा गया कि वह विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का तकनीकी विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में एक व्यौरेवार योजना तैयार करे।

मार्च, १९३० में विश्वविद्यालय ने रासायनिक उद्योगों के विकास के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसमें ७ भारतीय और ३ यूरोपीयन सदस्य थे। इस बात के लिए बम्बई विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने समिति के लिए रसायनशास्त्र के विशेषज्ञों तथा उद्योगपतियों का चुनाव किया। इस समिति का अध्यक्ष भी मुझे ही बनाया गया था। इस काम में लगभग छ. महीने लगा कर एक सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार की गयी और विश्वविद्यालय ने उसे स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को कार्यरूप देने हुए विश्वविद्यालय ने एक अपना ही रासायनिक तकनीकी संस्थान स्थापित किया और उसे अस्थायी रूप से फोर्ट के इलाके में रखा गया। बाद में इसे बम्बई के माटुंगा क्षेत्र में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया। यह संस्थान विश्वविद्यालय अधिकारियों के देश प्रेम का प्रतीक है। कई लोगों ने निजी रूप से दान देकर भी इस संस्थान की सहायता की और अब यह बहुत अच्छी तरह में चल रहा है।

### सिचाई जांच-पड़ताल समिति, १९३८

इस समिति को बम्बई सरकार ने, दिसम्बर, १९३७ के अन्त में, सिचाई और जगमे सम्बन्धित मामलों की पूरी-पूरी जांच करने के लिए तथा आवश्यक सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। समिति में सरकारी तथा निरसरकारी, कुल मिला कर, १० सदस्य थे। इसमें केन्द्रीय डिवाजन के आयुक्त, वृषि विभाग के निदेशक तथा सिचाई विभाग के सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर जैसे उच्च सरकारी अधिकारी शामिल थे। मुझ से इन समिति का अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया। समिति

## भारतीय अर्थ-व्यवस्था जांच समिति, १९२५

केन्द्रीय विधान सभा जिसका संगठन मांटज़ोर्ड सुधारों के अनुसार किया गया था, यह चाहती थी कि उद्योगों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे कर के जनता के सामने रखे जायें। इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था जांच समिति नियुक्त की। पंडित हरिकिशन कौल, जो बाद में राजा हरिकिशन कौल हो गये, समिति के सदस्य थे और प्रोफेसर वनॉट हर्स्ट इसके सदस्य व सचिव थे। मुझे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

समिति को ये कार्य करने थे,

“जो भी सामग्री वर्तमान काल में उपलब्ध है उसकी जांच करके एक ऐसा विवरण तैयार करना, जिससे भारत के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चल सके; इसके औचित्य पर विचार करना और इस प्रकार के सुझाव देना जिनसे सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण सम्भव हो सके। इसके साथ ही इन सुझावों को कार्य रूप देने के खर्च का अनुमानित विवरण भी देना था।”

इस समिति ने लगभग सात महीनों तक काम किया; देश के विभिन्न भागों का दौरा किया, बर्मा भी गयी क्योंकि तब बर्मा भारत का ही भाग था। और फिर एक रिपोर्ट तैयार की। श्री वनॉट हर्स्ट ने, जो कि समिति के सदस्य और सचिव थे, रिपोर्ट से असहमति प्रकट करते हुए एक अलग नोट लिखा।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण पर बल दिया था, जिसका उद्देश्य ऐसे आंकड़े और जानकारी इकट्ठी करना हो जिनसे वर्तमान अर्थ नीतियां निर्धारित करने तथा अर्थ समस्याएं सुलझाने में सहायता मिल सके और देश के सावनों का विकास करके देश को समृद्धिशाली बनाया जा सके। आंकड़े सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया और तथ्य एकत्रित करने, उत्पादन, आय, धर्म, वेतन, क्रीमतों, निर्वाह-खर्च मूचकांक तथा दूसरे सम्बन्धित मामलों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके उन्हें गही रूप में प्रकाशित करने के सुझाव दिये गये। कुछ विशेष निष्कारियों भी की गयीं जिनमें एक यह भी थी कि कानून बनाकर एक ऐसे सांख्यिकी संगठन की स्थापना की जाय, जिसके केन्द्रीय और प्रांतीय कार्यालय हों और सांख्यिकी संग्रह के काम में तालमेल रखा जाय। भू-पश्चिमी देशों में आंकड़े संग्रह करने की पद्धतियों का अध्ययन किया था जो

उन्हीं के आधार पर, मैंने स्थानीय परिस्थितियों के अनकूल एक प्रणाली की सिफारिश की।

केन्द्रीय एमम्बली की एक बैठक में तत्कालीन वाइसराय लार्ड रीटिंग ने इस रिपोर्ट की चर्चा करते हुए इससे अपनी सहमति प्रकट की, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे कार्यरूप देने के लिये कोई सत्रिय कदम नहीं उठाये गये और आकटे सम्बन्धी स्थिति अभी तक असतोषजनक है।

### बैंक वे जांच समिति, १९२६

यह समिति भारत सरकार ने इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश सर प्रिमबुड मियर्स की अध्यक्षता में नियुक्त की। इसमें तीन और सदस्य थे। दो भारतीय, जिनमें से एक मैं था, और तीसरे एक यूरोपियन गज्जन थे जो मिस में नीबरी कर चुके थे। समिति के सचिव इंडियन सिविल सर्विस के एक यूरोपियन अफसर थे।

समिति के जिम्मे बैंक वे सुधार योजना के कार्य के इतिहास की जांच करने तथा भविष्य में इस काम को चलाने के बारे में सुझाव देने का काम था।

बम्बई में कई गवाहों से पूछ-ताछ की गयी, जिनमें एक यूरोपियन टेकेंडार तथा बम्बई नगर निगम के सदस्य भी थे।

समिति की बैठकें लंदन में भी हुईं। पहले यह बैठकें पार्लमेंट स्ट्रीट में हुईं और बाद में संसद भवन में। महा लॉर्ड लॉयड से भी, जो उस समय मिस में हार्ड कमिशनर थे, पूछ-ताछ की गयी।

समिति ने एक योजना बना कर दी, जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि जिस क्षेत्र की भूमि पहले सुधार ली गयी है, उसका विभाग बंभें बिया जाय और अधिक भूमि को सुधारने का काम रोक दिया जाय तथा योजना के उन कामों में जिन्हें अभी हाथ में नहीं लिया गया था, नमी कर दी जाय।

### बंगलौर राजनैतिक उपद्रव जांच समिति, १९२९

जुलाई, १९२८ में बंगलौर नगर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो गये। इन दंगों के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति बनायी और मुझे उनका अध्यक्ष

बनने को कहा गया। मैं तो इस काम को हाथ में नहीं लेना चाहता था, परन्तु महाराज मैमूर के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा। समिति तीन-चार महीनों तक जांच कार्य करती रही। इस अवधि में समिति ने बहुत-सी साक्षियाँ प्राप्त कीं और फिर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट वैसे तो सर्वगम्मत ही थी, केवल दंगों में भाग लेनेवाले दो गमुदायों में से एक के नेता ने उससे अग्रहमति प्रकट की थी।

### सक्कर बांध निर्माण समिति, १९२९

सिंध नदी पर बननेवाले सक्कर बांध के निर्माण और उसके भावी स्वरूप के बारे में समाचारपत्रों में कई शिकायतें प्रकाशित हुईं। अतः बम्बई सरकार ने यह ज़रूरी समझा कि केवल भारतीय इंजीनियरों की एक समिति बना कर इस सम्बन्ध में जांच करायी जाय। दो सदस्यों की एक समिति, जिसमें मैं और हैदराबाद के चीफ़ इंजीनियर श्री अहमदअली (बाद में नवाब अली नवाज़ जंग) शामिल थे, इस काम के लिए नियुक्त की गयी। हमने, गर्मी के मौसम में, लगभग साढ़े तीन महीने काम किया। इस अवधि में हम बांध तथा उससे निकली नदी नहरों को देखने भी गये और फिर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसे बम्बई सरकार ने स्वीकार कर लिया। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर फ़्रेडरिक साईक्स ने इस रिपोर्ट की प्राप्ति सूचना देते हुए मुझे एक पत्र इस प्रकार लिखा :

“रिपोर्ट बहुत ही सन्तोषजनक है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट परियोजना के काम को आगे बढ़ाने तथा उसे सबके लिए लाभदायक बनाने में सहायता देगी।”

मुझे पता चला कि समिति के सुझावों को कार्यरूप देने का काम दस वर्ष बाद आरम्भ हुआ।

## राजनीतिक तथा अन्य सम्मेलन

भारत सरकार और देशी रियासतों के अधिपति में बंम सम्मेलन हुआ, इस बारे में विचार करने तथा करने गुमाव देने के लिए, १९१७ में, राजाओं तथा रानियों (राजाओं) की एक समिति बनायी गयी। जब मैं मंगूर का बीजान था तो समिति का सदस्य होने के नाते मैंने दो बार इसकी बैठकों में भाग लिया। इसमें मे एक बैठक बीजानेर में और दूसरी पटियाला में हुई थी। बीजानेर के जगन्धर महाराज का संवत्सिक ब्रह्मपुर इसमें भागदा थे और अजमेर के महाराज तथा रायपुर के भी गिरहा इसके सदस्य थे।

देशी रियासतों के बारे में गुजारों के कई गुमाव रंग गये। उन पर बहुत की गयी और प्रस्ताव पास किए गये। चूंकि अब गारी देशी रियासतों में भारत में सम्मिलित हो गयी है, अतः उस समय जो प्रस्ताव पास किए गये थे या गुमाव रंग गये थे, उनका बहुत उपयोग करने में कोई लाभ न होगा।

सन् १९२३ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसका समारोह मुझे बनाया गया। सन् १९२४ में बम्बई में भारतीय अर्थ सम्मेलन हुआ और उसका समारोह भी मुझे ही बनाया गया। बंगलौर के भारतीय विज्ञान सम्मेलन के सदस्य मण्डल में मुझे प्रधान चुना और, १९३८ में, मैं लगातार तीन वर्षों तक इस पद की संभाले रहा। सन् १९४७ में मैंने स्वयम् प्रार्थना की कि मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाय।

मुझे दो राजनीतिक सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर भी प्राप्त हुए, जिसका वर्णन मधोम करेगा।

## बम्बई का संवैधानीय सम्मेलन, १९२२

१. १९२१ को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई में आये, तो उस दिन
२. नगर में विदेशी बगड़े की होली जलाई जा रही थी।
३. मे दंगा और मून खराबा भी हुआ। उसी दिन कलकत्ता में

एक शान्ति पूर्ण हड़ताल हुई, परन्तु बंगाल सरकार ने कांग्रेस स्वयंसेवकों की भर्ती को रोकानूनी घोषित कर दिया और बहुत-से लोग गिरफ्तार कर लिये गये, जिनमें कांग्रेस के प्रधान श्री सी० आर० दास भी थे। कुछ दिन बाद वाइसराय कलकत्ता गये, जहाँ प्रिंस ऑफ़ वेल्ज बड़े दिनों में जाने वाले थे। वाइसराय के इस कलकत्ता प्रवास में कांग्रेसी नेता पंडित मदनमोहन मालवीय ने, कुछ दूसरे नेताओं से सलाह कर, वाइसराय से बातचीत की। बातचीत का उद्देश्य एक गोलमेज सम्मेलन बुला कर उन प्रश्नों पर विचार करना था जो जनता में रोष का कारण बने हुए थे। बातचीत का परिणाम यह हुआ कि पंडित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल २१ दिसम्बर, १९२१ के दिन वाइसराय से मिलने के लिए गया।

पंडित जी के निमन्त्रण पर इस मण्डल में शामिल होने के लिए मैं भी कलकत्ता जा पहुँचा। इस मण्डल ने, जिसमें श्रीमती ऐनी बेसेंट भी शामिल थीं, सरकार के प्रतिनिधियों और देश के सब राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने की तजवीज पर विचार किया। सम्मेलन का उद्देश्य उन राजनीतिक समस्याओं का हल ढूँढ़ना था जो उन दिनों जनता में रोष का कारण बनी हुई थीं। महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन चलाने का निश्चय किया था, परन्तु वह किसी भी ऐसे उचित मार्ग को अपनाने के विरुद्ध नहीं थे जिससे देश की सब से जरूरी मांगें पूरी होती हों।

कलकत्ता में हुई बैठक में वाइसराय ने इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि गोलमेज सम्मेलन बुलाया जायगा या नहीं। फिर भी उन्होंने यह कहा कि उनकी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सम्मेलन बुलाने से सदा के लिए इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा :

“निश्चय ही मैंने किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, जिसका इस प्रकार का अर्थ लगाया जा सके। मैंने जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त किया है और मैं जानता हूँ कि उन लोगों के साथ बातचीत करने का कोई लाभ नहीं हो सकता, जिनके दृष्टिकोण हमारे सोचने के ढंग से बिल्कुल भिन्न हों।”

तब पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की सभा में भाग लेने और महात्मा गांधी, श्री एम० आर० जयकर तथा एम० ए० जिन्ना के साथ स्थिति पर विचार करने के लिए कलकत्ता से अहमदाबाद गये। इस सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस

की सारी गतिविधियाँ स्थगित कर देने के प्रस्ताव पाम किये और लोगों से अपील की कि वे स्वयंसेवकों में भर्ती होकर, बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन किये, अपने आपकी गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें। यह कदम व्यक्तिगत और सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पूर्ण सूचना थी और मनमाने ढंग से चलनेवाली प्रजापंडित सत्ता में निपटने का यही एकमात्र सम्यक् तरीका था जो प्रभावशाली निद हो सकता था। परन्तु महात्मा गांधी उस स्थिति में भी पंडित मदनमोहन मालवीय, श्री एम० आर० जयकर और श्री एम० ए० जिन्ना के प्रयत्नों द्वारा गोलमेठ सम्मेलन के आयोजित होने पर उसमें भाग लेने के लिए तैयार थे।

पंडित मदनमोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह बम्बई में होनेवाले सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लें। देश के सभी राजनीतिक दलों के साठे तीन सौ प्रमुख नागरिकों को बम्बई में होनेवाले इस प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और लगभग दो सौ सज्जन इसमें भाग लेने के लिए पहुँचे। सम्मेलन में भाग लेनेवाले सज्जनों के नामों की सूची और सम्मेलन की कार्यवाही की रिपोर्ट सम्मेलन के सचिवों श्री एम० ए० जिन्ना, श्री एम० आर० जयकर तथा श्री के० नटराजन द्वारा एक पुस्तिका के रूप में १९२२ में प्रकाशित की गयी। इस सर्वदलीय सम्मेलन के बारे में जो भी जानकारी इस परिच्छेद में दी गयी है, वह उसी पुस्तिका से ली गयी है।

जब सम्मेलन आरम्भ हुआ तो सर शंकरन नायर को सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले दिन तो उन्होंने सभा की कार्यवाही को चलाया, परन्तु दूसरे दिन उन्होंने कुछ प्रस्तावों से असहमति प्रकट की और सम्मेलन से हट जाने का निर्णय कर लिया। तब उनके स्थान पर मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

उक्त पुस्तिका में इस अवसर पर पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा दिये गये भाषण का उल्लेख इस प्रकार है :

"मुझे भेद है कि हमारे मान्य मित्र सर शंकरन नायर, जिन्होंने इस सम्मेलन का अध्यक्ष होना स्वीकार किया था, हमारे कुछ प्रस्तावों से सहमत न हो सके और इसलिए सम्मेलन से अलग हो गये। उन्होंने हमें जो महत्तमा प्रदान की हम उसके लिए उनके आभारी हैं। सर शंकरन नायर के अलग हो जाने पर समिति ने सर विश्वेश्वरैया को अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग समिति द्वारा किये गये इस चुनाव का



परिणाम स्वरूप, जसे चौरीचौरा घटना, वारडोली अवज्ञा आन्दोलन, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और जेल, जो अब ऐतिहासिक घटनाएं बन गयी हैं, समिति को लगा कि अब वातावरण दूसरा सम्मेलन बुलाने के उपयुक्त नहीं है। इसके पश्चात् समिति ने काम करना छोड़ दिया और वह समाप्त हो गयी।

### दक्षिण भारत रियासती जनता सम्मेलन, १९२९

एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन, जिसका अध्यक्ष बनने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, १४ और १५ फरवरी, १९२९ को त्रिवेन्द्रम में होने वाला दक्षिण भारत रियासती जनता सम्मेलन था। इसमें मैसूर, हैदराबाद, पुडुकोट्टा, कांचीन और त्रावन्कोर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय वैधानिक सुधार सम्बन्धी प्रश्न अब एक महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच चुके थे और यह सम्मेलन इन प्रश्नों को मुद्दा बनाने तथा रियासती जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन में मैंने जो भाषण दिया, उसमें मैंने भारतीय वैधानिक सुधारों पर विचार प्रकट किये, रियासती जनता की आवश्यकताओं की चर्चा की और भावी भारत में देशी रियासतों तथा राजाओं की क्या स्थिति हो, उन पर अपने विचार रखे।

सम्मेलन ने सामान्य सिद्धान्त और प्रस्ताव स्वीकृत किये, जिन्हें एक स्मृति पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। स्मृति पत्र का शीर्षक था "भारत तथा भारतीय रियासतों का प्रभुत्वता विधान।"

यह स्मृति पत्र नियम समिति ने तैयार किया था और यह १७ मारच की एक स्थायी समिति द्वारा पेश किया गया था। स्थायी समिति द्वारा यह नियम पारित हो तो वह भारत में इसके अनुसार कार्य करेगा।

## विदेश यात्रा—यूरोप और अमेरिका के लिए औद्योगिक शिष्ट मंडल

मैंने दूर दूर तक विदेश यात्राएँ की हैं। यहाँ पर मैं उनका सक्षेप में वर्णन करूँगा और यह भी यह बनाने के लिए कि उन्होंने मेरे विचारों को किस प्रकार प्रभावित किया। इसमें मुझे अपनी सरकारी नौकरी के अन्तिम दौर में, विशेषकर मैसूर राज्य की नौकरी में और अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् कुछ नीतियाँ निर्धारित करने में सहायता मिली।

मैंने छ बार विदेश यात्रा की, जिसमें से पाँच बार मैं अमेरिका गया। मुझे विश्वास है कि यदि मैं प्रत्येक यात्रा का कुछ विस्तारपूर्वक उल्लेख करूँ, तो पाठक गण ऊँचे नहीं।

१. पहली बार भारत से बाहर मैं मई १८९८ में गया। उस समय तक मैं पूना में केन्द्रीय विभाग (मिचाई) के मुख्य इंजीनियर के महामक के पद पर कार्य कर चुका था।

मार्च, १८९८ में मैं जापान गया और लगभग तीन महीनों तक उस देश में भ्रमण करता रहा। वहाँ मुझे जो कुछ भी नोट करने योग्य लगा वह मैंने नोट कर लिया और वापस आ कर अपने अनुभवों के आधार पर एक छोटी सी पुस्तक लिख डाली। परन्तु मैंने सोचा कि पुस्तक प्रकाशित करने का उचित अवसर नहीं है। इसके अनतिरिक्त उस समय मैं बम्बई सरकार का एक जिम्मेदार अधिकारी था। उस समय सरकार की किसी भी नीति या कार्य की आलोचना करना, चाहे वह ठीक ही हो, अनावश्यक बात होती। पूना को उस समय राजनैतिक आन्दोलनों का केन्द्र समझा जाता था। मैं सरकार तथा मार्क्सवादी नेताओं, दोनों से सम्बन्ध बना कर रहना चाहता था। उन दिनों सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करना गन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और इससे एक सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने हुए मेरे नामों में कई रुकावटें आ सकती थीं।

२. दूसरी विदेश यात्रा मैंने १९०८ में, बम्बई सरकार की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद, की। इस यात्रा का उद्देश्य दो-तीन वर्ष यूरोप तथा अमेरिका

में विता कर कुछ लाभदायक अनुभव प्राप्त करना था। परन्तु मुझे यह यात्रा बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैं इटली में भ्रमण कर रहा था तब मुझे एक तार मिला, जिसमें मुझे इंजीनियरिंग की एक बृहत् समस्या का हल करने के लिए बुलाया था, अर्थात् वाढ़ से नष्ट हुए हैदराबाद नगर का पुनर्निर्माण करने तथा भविष्य में वाढ़ से नगर की रक्षा करने की योजना बनाने के लिए बुलाया गया था। खैर, तो निमन्त्रण स्वीकार करने के पश्चात् भी मैं लगभग पांच महीनों तक यूरोप और अमरीका में रहा। इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ समय इटली, यूरोप, अमरीका तथा कनाडा की जल-वितरण योजनाओं और बांध, जल निकास, सिंचाई तथा दूसरे कामों के इंजीनियरिंग विकास का अध्ययन करने में बिताया। परन्तु भारत लौटने पर मैं इस बुरी तरह से काम में फंस गया कि मुझे अपने अनुभवों को लिखने का समय ही नहीं मिला। हालांकि मैंने जो सामग्री इकट्ठी की थी उससे मेरे विचारों की अभिवृद्धि ही हुई, परन्तु मैं उन्हें ब्योरेवार यात्रा विवरण के रूप में नहीं लिख सका। चूंकि कुछ दिन पहले मैं बम्बई प्रेज़ीडेंसी में इंजीनियरिंग के नक्शे तैयार करने का काम कर चुका था, इसलिए मैंने इटली के जल निकास, सिंचाई और मिट्टी के कटाव की समस्याओं का, दो महीनों से अधिक समय तक, अध्ययन किया। मैं मिलान के चीफ़ इंजीनियर के साथ वहां के ज़मीन दोज़ मल-मार्गों का देखने के लिए गया। उस अफसर ने मेरा स्वागत तो किया, लेकिन पूछने लगा कि मैं इन ज़मीन दोज़ मलमार्गों के नक्शों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि भारत में यह सब काम तो अंग्रेज़ी अफसरों ने संभाल रखे हैं। मैंने उसे बताया कि ऐसी बात नहीं है। यदि भारतीय इंजीनियर कड़ी मेहनत करें तो उनके काम की प्रशंसा होती है और उन्हें काम भी दिया जाता है। अपनी इस बात की पुष्टि में मैंने बताया कि १९०६ में मुझे विशेष कार्य के लिए अदन भेजा गया था।

सन् १९०८ और १९०९ में यूरोप के कई भागों में भ्रमण किया जिनमें स्वीडन और रूस भी थे। स्वीडन, डेनमार्क और हालैंड तब तक भी बहुत आगे बढ़े हुए देश थे। मैं बाल्टिक सागर को एक नाव द्वारा पार करके, सेंट पीटर्सबर्ग (अब लेनिन-ग्राद) भी गया। लेनिनग्राद से मैं मास्को गया। वहां पर भी मैंने श्रम्यता का वही स्तर पाया जो यूरोप के अन्य भागों में था। परन्तु यहां जार का शासन था, इसलिए

जनता में अगलोग फैला हुआ था। जिग और भी भे गया, लन्दन मेरी यात्राओं का केन्द्र रहा। लन्दन में मेरे कुछ पुराने सहयोगी और मित्र थे, जिनमें मुझे यात्रा सम्बन्धी हर प्रकार की महामत्ता मिली।

रुमों परवान् मैं न्यूयार्क गया, वहाँ भारतीय व्यापारियों का एक मध्य था। मैं लोग बड़े उत्साही, जीवन और महत्वाकांक्षी थे। उनसे मिलने पर मुझे भारत के मुजावत अमरीका के जायिक विकासों के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं कनाडा में ओटावा और टोंटो भी गया। वहाँ से डेट्रायट जा कर मैंने फोर्ड कारस्थानों का अध्ययन किया। वहाँ परदेन बाथ जैसे विभाग जलामय भी थे जिनमें न्यूयार्क से जोड़ पड़वाया जाता था। परन्तु अमरीका में उस समय गिचार्ड मापनों का अधिक विकास नहीं हुआ था।

कनाडा में मुझे उन सब विभागों के सम्बन्ध में आकड़े दिये गये, जिन्हें विकसित किया जा रहा था। इस काम में सम्बन्धित श्री सी० एम० कोट्रा में मेरे साथ महा अज्ञा व्यवहार किया। कनाडा छोड़ने के कुछ वर्ष बाद तक भी उनका मेरे साथ पत्र व्यवहार चलता रहा। इस यात्रा के अन्त में लौटने समय मैं लन्दन और प्राग भी गया। फिर मार्सेल में सी० एम० के एक जहाज द्वारा बम्बई वापस आ गया।

३. अगली विदेश यात्रा मैंने १९१९ में की। तब मुझे मैंगूर सरकार की नीकरी में जबरान ग्रहण किये लगभग तीन महीने हो चुके थे। बम्बई के कुछ मित्रगण, जिनमें कंगडा उद्योग में सम्बन्धित सर बिट्ठलदास दामोदर ठाकरे और मूलराम खटाऊ प्रमुख थे, विदेश भ्रमण का कार्यक्रम बना रहे थे। इनमें स्त्री पुरष मिला कर कुछ व्यक्ति थे। मैं भी इसी दल में शामिल हो गया और हमने श्रीलंका और सिंगापुर में होने हुए विश्व भ्रमण का निश्चय किया। हम पी०ओ० के जहाज में सवार हो कर बम्बई में कोलम्बो, सिंगापुर, हांगकांग, साचाई होने हुए जापान में नागासाकी नामक स्थान पर उतरे। मैं जापान में लगभग तीन महीने ठहरा। इस देश में मेरी यह दूसरी यात्रा थी और मैं शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य और राजनीति में हुए नये विकासों का अध्ययन करने के लिए गया था। वहाँ से हम अमरीका जाना चाहते थे। हम सब के लिए एक ही जहाज में स्थान पाना कठिन था, अतः मैं थोकोहामा में होता हुआ कनाडा जा पहुँचा। कनाडा में जिग बन्दरगाह पर मैं तब से पहले पहुँचा, उसका नाम विक्टोरिया था। यह बन्दरगाह लक्की के

व्यापार के लिए प्रगिद्ध था। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे नदी में बहा दिये जाते थे और उन्हें, बिगटोरिया के निकट, नदी से निकाल कर चिराई के लिए दोनों ओर जमा कर दिया जाता था। लकड़ी की चिराई के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लगायी गयी थीं। चिराई का सारा काम मशीनों द्वारा अपनेआप होता रहता था और कारखाने में केवल दो या तीन आदमी ही काम करते थे। तब रेल द्वारा यह लकड़ी ३००० मील दूर, न्यूयार्क जैसी देश के भीतरी भागों की अन्य मंडियों तक, पहुंचा दी जाती।

अमरीका में हमने सीमेन्ट और कागज जैसे कुछ उद्योगों का अध्ययन किया। मोटर उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम डेट्रायट गये। चूंकि मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिये गये कुछ देशों के लिए परिचय पत्र थे, इसलिए अमरीका और कनाडा के निर्माताओं तथा सरकारी अधिकारियों ने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। मैं पहले कई वर्षों तक 'शिकागो कामर्स' नामक एक पत्रिका का ग्राहक रह चुका था। शिकागो के कुछ व्यापारी, जो इस पत्रिका की बड़ी कद्र करते थे, मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आये।

यह १९१९ के अन्त की बात है। इससे पूर्व १९०८ में जब मैं पहली बार ओटावा गया था, तो मैंने वहां कुछ मित्र बना लिये थे जिन्होंने मेरी बड़ी सहायता की।

एक छोटी सी घटना से इन व्यावसायी व्यक्तियों की निष्ठा का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। शिकागो में मैंने एक व्यापारी से एक चीज मंगायी। उसने मुझसे कहा कि वह उसे तैयार करवा कर एक, खास तारीख की शाम तक, अपनी महिला सचिव के पास छोड़ देगा। तब यह हुआ कि मैं उस चीज के लिए ८ डालर दूंगा। लेकिन मैं चाहता था कि वह चीज मुझे एक खास समय तक मिल जाय, इसलिए मैंने यह वायदा किया कि मुझे निश्चित समय तक मिल गया तो मैं १ डालर ज्यादा दूंगा। जहां तक मुझे याद है, मैं लगभग ५ बजे शाम को उसकी दूकान पर पहुंचा था। उस समय वह अपने दफ्तर में नहीं था, लेकिन मेरी चीज उसके सचिव के पास तैयार पड़ी थी। मैंने माल की क्रीमत के साथ एक डालर ज्यादा दे दिया, ताकि वह यह न समझे कि मैंने जो अतिरिक्त डालर देने का वायदा किया था उसे भूल गया हूँ। उस व्यापारी को मेरे ठिकाने का पता नहीं था, परन्तु वह इतना अवश्य जानता था कि मैं अगले दिन सुबह शिकागो से जाने वाला हूँ। मैं यह देख कर बड़ा हैरान

हुआ कि अगले दिन सुबह वह मुझे दूढ़ता हुआ एक डालर लीटाने के लिए मेरे होटल में आ पहुँचा। वह बोला कि मेरा पना उसके पास नहीं था और मुझे दूढ़ने के लिए उसे दो तीन होटलों में पूछ ताछ करनी पड़ी। मैंने उससे पूछा कि उसने यह एटालर चुपचाप जेब में क्यों नहीं रख लिया, क्योंकि बहुत से व्यापारी लोग ऐसा करते हैं। उसने उत्तर दिया कि यह अतिरिक्त डालर उसकी हक की कमाई नहीं है।

“ऐसा कर के मैं अपनी मानसिक शान्ति खो बैठता”, वह अपना भाषा छूटवा डाला। इसके अनिरीकत अमरीका के इस भ्रमण में कुछ और रोचक घटना भी हुई।

मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से मिलने गया और पूछा कि क्या कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन्हें उनका सुप्रसिद्ध विद्यालय विशेष महत्त्व देता है? अध्यक्ष का उत्तर था “हम सभी विषयों का महत्त्व देते हैं।”

मैं अमरीका के मध्यवर्ती एक अन्य विश्वविद्यालय में गया हुआ था। वहाँ के दौरान मैंने वहाँ के अध्यक्ष से पूछा कि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पर साल कितना खर्च करना पड़ता है। उन्होंने उत्तर दिया “जिन विद्यार्थियों के माता-पिता काम करते हैं, हम उन्हें भी काम कर के कमाने और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।” उन्होंने मुझे बताया कि अपने विद्यार्थी जीवन वह स्वयं इसी प्रकार काम कर पड़े थे। परन्तु उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस बात को किसी और पर प्रकट न करूँ।

मई १९२० में मैंने अमरीका की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया और इस सम्बन्ध में वाशिंगटन में फेडरल रिज़र्व बोर्ड के अध्यक्ष से मिल गया। बातों बातों में मैंने उनसे कुछ प्रश्न भारत की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछे। मैंने यह भी कहा कि क्या वह कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे इस स्थिति कुछ सुधारा हो सके। वह हँसा-हवाला करने लगे और बोले कि सुदूर भारत परिस्थितियों को वह वहाँ बैठे कैसे परख सकते हैं। इस पर मैंने कहा : “मैं आपका पास इसलिए आया हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया था, आप इस देश के शासक से योग्य वित्त विशेषज्ञ हैं। आप यह कैसे दलील देते हैं कि आप भारत की विभाजित देश की वित्तीय स्थिति को नहीं जानते हैं?” मेरे साथ एक योग्य पत्रकार भी था। उने बह एक ओर से गये और बोले : “दूर गज्जत में जा कर ब

कि अपने देश लौट जायें और वहां के विधान को एक राष्ट्रीय सरकार के विधान में बदल दें। तब वह मेरे पास आयें और मैं इन्हें उचित सलाह दूंगा।”

वाशिंगटन में मैंने यह सोचा कि श्री हरवर्ट-हूवर, जो उस समय वाणिज्य सचिव थे, से मिल कर विश्व के मामलों पर, विशेषकर उद्योग के सम्बन्ध में, बातचीत कर के कुछ लाभ उठाऊं। अपनी पहली यात्रा में मैंने वाशिंगटन में कुछ मित्र बनाये थे। इनमें से दो सज्जन जो श्री हूवर को जानते थे, यह चाहते थे कि मैं उनके साथ श्री हूवर से मिलूं और उनसे विचार-विमर्श करूं। मैंने श्री हूवर से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी देर तक बातचीत की। मैं उन दिनों 'भारत का पुनर्निर्माण' नामक पुस्तक लिखने की सोच रहा था, जो बाद में लन्दन में प्रकाशित हुई। मुझे पता लग चुका था कि श्री हूवर अमरीकन उद्योगों के विकास में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके देश में उद्योगों का कितनी तेज़ी से विकास हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार में ऐसी कौन सी बातें हैं, जिसके कारण भारत इतना पिछड़ा हुआ है। वह वाले : 'आप लोगों में कुछ चैतन्यता नहीं है।' कहने का मतलब यही था कि भारतवासी सुस्त और आरामतलब हैं।

तब मैं वहां से लन्दन वापस आ गया और वहां अपनी पुस्तक 'भारत का पुनर्निर्माण' लिखने के लिए लगभग दस महीनों तक रुका रहा। यह पुस्तक लन्दन के सर्वश्री पी० एस० किंग एण्ड संस लि० द्वारा, १९२० में, प्रकाशित की गयी। लन्दन में रह कर इस पुस्तक को पूरा करने में बड़ी आसानी रही, क्योंकि 'इंडिया आफ़िस लायब्रेरी' से मुझे इस पुस्तक से सम्बन्धित हर प्रकार की जानकारी मिल गयी।

लन्दन की 'रायल सोसायटी ऑफ़ आर्ट्स' के भारतीय प्रभाग में एक बार भारतीय समस्याओं पर वाद-विवाद हुआ और मुझे भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बैठक का सभापतित्व श्री एडविन मोन्टेग्यु न किया, जो उन दिनों भारत के सचिव थे।

वाद में जब मैं श्री मोन्टेग्यु से मिला, तो उन्होंने मुझे राज्य सचिवों की परिपक्व का एक पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। यह स्थान भावनगर के सर प्रभाशंकर डी० पट्टणी चले के जाने से खाली हुआ था। सर प्रभाशंकर ने भी इस बात पर जोर दिया कि मैं उनकी जगह संभाल लूं। परन्तु वहां मेरी योजनाओं के लिए

कोई स्थान न था और वहाँ रह कर किसी भारतीय के लिए अपने देश के लिए कोई उपयोगी काम कर पाना कठिन था।

‘भारत का पुनर्निर्माण’ नामक पुस्तक प्रकाशित होने के बाद मैं बम्बई वापस आ गया।

४. चौथी विदेश यात्रा मैंने १९२६ में की, जब भारत सरकार ने मुझे बैंक के पुनर्निर्माण जांच समिति का इंजीनियर सदस्य नियुक्त किया। इस समिति की स्थापना कैसे हुई और इसने क्या काम किया, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

जब लन्दन में इस समिति का कार्य समाप्त हो गया तो मैं इस्पात बनाने और लकड़ी के पकाव से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यूरोप और अमरीका में भ्रमण करने चला गया। यह कार्य मैसूर के लोहा बनाने के कारखाने से सम्बन्धित था, जिसके व्यवस्थापक मण्डल का मैं अध्यक्ष था। इस भ्रमण के दौरान मैंने अमरीका में भद्रावती (मैसूर) का कच्चा लोहा घेचने का पता भी किया। पहले भी मैं दो-एक बार सार्वजनिक रूप से बना चुका हूँ कि अमरीका में निमाताओं को जिस भाव पर कच्चा लोहा मिल रहा था, हम उससे सस्ते दामों पर उन्हें लोहा दे रहे थे। मैंने अमरीका और स्वीडन में, जहाँ लोहे व इस्पात का उद्योग लकड़ी के कोयले से चलता था, इस उद्योग से सम्बन्धित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की।

इस भ्रमण में मैंने देखा कि मलाट्टकार इंजीनियरों की एक गम्भीर बर्लिन और उसके आसपास स्थापित लकड़ी पकाने के लगभग ८० कारखानों की देख-भाल करती थी।

५. पाचवी बार मैं १९३५ में भारत में बाहर गया। इस बार मैं मोटर उद्योग आरम्भ करने और उसके नक्शे तैयार करने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए निकला था। मैंने लगभग छ महीने यूरोप तथा अमरीका में विताये और इस अवधि में मोटर उद्योग का अध्ययन किया।

मैंने पहले में इगर्टण्ड में क्वेंट्री, जॉन्सहोर्ड, बर्मिंघम और डर्बी के कारखाने देखने गया।

बर्मिंघम में मैं लॉर्ड ऑस्टिन में मिला, जिन्होंने बम्बई में एक मोटर कारखाना स्थापित करने के बारे में मुझे अनुमानित व्यय विवरण तैयार कर के दिये। जन्म में उन्होंने मुझे गन्नाही दी कि भारत के लिए विचित्रे आकार की अमरीकी बार टीन



रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि हम छोटी कार चाहते हैं तो इसके लिए उनकी अपनी ओस्टिन कार बहुत अच्छी रहेगी।

फिर मैं वहां से इटली, जर्मनी तथा फ्रांस चला गया और ट्यूरिन के समीप एवस ला वेन्स के स्थान पर एक महीना रहा।

मैंने ट्यूरिन में वह कारखाना भी देखा जहां फिएट कार बनती थी। फिएट कारखाने की एक विशेषता यह थी कि वह कई मंजिल ऊंची इमारत में बना हुआ था और नीचे से सारा सामान ट्रकों द्वारा ऊंचे उठते घुमावदार रास्ते से ऊपर पहुंचाया जाता था। रास्ते के दोनों ओर कारखाने का काम होता रहता था।

तब मैं वहां से अमरीका चला गया और न्यूयार्क में मेरी भेंट एक रूसी इंजीनियर से हो गयी, जो रूस में मोटर उद्योग स्थापित करने के विचार से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए अमरीका आया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि इस काम में सहायता देने के लिए उनके साथ ४० रूसी इंजीनियर आये हुए हैं। उन लोगों को रूस में, अमरीकी मॉडल की एक पूरी गाड़ी का उत्पादन करने का विचार कर के, उससे सम्बन्धित तकनीकी तथा दूसरी जानकारी हासिल करनी थी।

इसके पश्चात् मैं फोर्ड कारखाने के सुविख्यात जनरल मैनेजर श्री चार्ल्स ई० सोरेन्सेन से और डेट्रायट में जनरल मोटर्स कारपोरेशन के दो जानकारों, श्री डब्ल्यू० एस० नडसन तथा श्री किटरिज, से मिला। मैंने लगभग एक महीना डेट्रायट में बिताया। इस अवधि में मैं इस बात की जांच करता रहा कि भारत में किस प्रकार एक अच्छे ढंग का कारखाना स्थापित किया जा सकता है। अनुमानित व्यय विवरण तैयार किये गये और अमरीका में कई मोटर कारखानों के अध्यक्षां ने उनकी जांच भी की। मैं पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार भारत में इस सारे किये कराये पर पानी फेर दिया गया। बहुत समय तक तो भारत सरकार ने इस उद्योग को आरम्भ करने की अनुमति ही नहीं दी और जब अनुमति मिली, तो वम्बई के व्यवसायियों में कोई एकता नहीं हो सकी, हालांकि १९३४-३५ में वे लोग पूर्णरूप से इस उद्योग के पक्ष में थे और उन्होंने मुझे हर प्रकार की सहायता देने का विश्वास दिलाया था।

अमरीका से मैं जो रिपोर्ट और परियोजना तैयार कर के लाया था, वह भारत में दो बार छपी गयी। इस रिपोर्ट और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना के परिणामस्वरूप वम्बई सरकार ने श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र और उनके सहयोगियों को वम्बई प्रान्त

म मोटर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए कुछ सुविधाएँ दीं। सरकार ने तकनीकी जांच-पड़ताल तथा अंग्रेजी या अमरीकी मोटर बनाने वाले कारखाने-दारों के साथ बातचीत करने के काम में, श्री बालचन्द्र की सहायता के लिए, तत्कालीन उद्योग निदेशक श्री पी० वी० अडवानी को नियुक्त कर दिया। ये दोनों सज्जन अमरीका के लिए रवाना हो गए और डेट्रायट पहुँच कर श्री हेंनरी फोर्ड और उनके जनरल मैनेजर श्री मोरेन्सन से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। वे फोर्ड कारखाने के इंजीनियरों के साथ कुछ सप्ताह रहे और भारत में मोटर कारखाना स्थापित करने के बारे में तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की जांच-पड़ताल की। इस जांच-पड़ताल के बाद जब फोर्ड कम्पनी के व्यवस्थापक इस बात से मन्तुष्ट हो गये कि मूल योजना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण है, तब इन दोनों सज्जनों, श्री बालचन्द्र तथा श्री अडवानी ने, बम्बई सरकार और मुझे तार द्वारा सूचित कर दिया कि योजना पर अमल करना सम्भव है। श्री अडवानी ने फोर्ड कम्पनी के साथ एक समझौते के लिए बातचीत की, जिससे भारतीय संगठन को तकनीकी सहायता प्राप्त हो सके। बाद में श्री हेंनरी फोर्ड को यह पता चला कि एक समझौते के अनुसार राष्ट्रमण्डलीय देशों में फोर्ड मोटर बेचने तथा बनाने के सब अधिकार कनाडा की फोर्ड मोटर कम्पनी को प्राप्त है। तब कनाडा फोर्ड कम्पनी से इस सम्बन्ध में बातचीत की गयी। कम्पनी ने बताया कि जब तक कारखाने में उनके ५१ प्रतिशत हिस्से न रहे जायें, वह कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। परन्तु कम्पनी की यह शर्त नहीं मानी गयी और श्री अडवानी ने डेट्रायट के विस्लर कारपोरेशन से बातचीत शुरू की। जब विस्लर कारपोरेशन को इस बात की तसल्ली हो गयी कि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बम्बई में मोटर बनाने का कारखाना स्थापित करना एक व्यावहारिक तजवीज है तो कारपोरेशन ने एक समझौता कर लिया गया। तब, इस समझौते के परिणाम स्वरूप, बम्बई में प्रीमियर आटोमोबाइल की स्थापना की गयी।

हमारे सब प्रयत्नों के बावजूद भारत सरकार ने दूसरे महायुद्ध के दौरान इस उद्योग को विकसित होने का अवसर नहीं दिया। यह बात दो तीन बार दुहरायी जा चुकी है कि किस प्रकार बम्बई के व्यवसायी, मुख्यतः सरकारी महायन्त्रों के जमाब में, यह उद्योग चालू नहीं कर पाये। इस प्रकार की किसी भी लाभदायक योजना के लिए लोगों को समझित करना तब तक बहुत मुश्किल है, जब तक सरकार

औद्योगिक संस्थानों को चलाने तथा विदेशी माल देने के सारे अधिकार अपने हाथ में रते रहती है।

६. अगली वार, १९४६, में मैं अखिल भारतीय निर्माता संगठन, वम्बई के नी सदस्यों के एक शिष्ट मण्डल के साथ भारत से गया। सब से पहले इस दल के सभी लोग लन्दन पहुंचे। हम वहां कई उद्योग धंधों को देखने के लिए गये, जिनमें कपड़ा, इंजीनियरिंग, रासायनिक उद्योग और ब्रिस्टल तथा डर्वी के हवाई जहाज बनाने के कारखाने शामिल थे। जिन सब फैक्ट्रियों में हम गये, वहां के व्यवस्थापकों ने बड़ा ही शिष्ट व्यवहार किया। कुछ ने तो अतिथि सत्कार भी किया और जो जानकारी हम चाहते थे, वह सब तो हमें कई व्यवस्थापकों ने दी।

इंग्लैण्ड से हम अमरीका और कनाडा के लिए रवाना हो गये। वहां भी हमने कई बड़े बड़े उद्योगों को देखा जिनमें नियागरा जल प्रपात पर बना विजली घर और शिकागो के बहुत से इंजीनियरिंग कारखाने भी शामिल थे। कुछ दिन हमने नहर पार के डेट्रायट और विंडसर के कारखाने देखने में लगाये। न्यूयार्क के निकट हमने एक हवाई जहाजों का कारखाना भी देखा। चूंकि मुझे टी०वी०ए० (टेनीसी घाटी योजना) में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी थी, इसलिए मैं अकेला ही न्यूयार्क से नाक्सबील गया और वहां से हवाई जहाज द्वारा लौट आया।

अमरीका और कनाडा का भ्रमण समाप्त करने के पश्चात् हममें से कुछ लोग, अलग अलग दल बना कर, फ्रांस और यूरोप के दूसरे हिस्सों में बड़े बड़े उद्योगों को देखने के लिए चले गये।

अपनी वापसी यात्रा पर, इंग्लैण्ड से रवाना होने से पूर्व, मण्डल के सभी सदस्य दिसम्बर १९४६ में लन्दन में होने वाले उद्योग मेले को देखने गये। भारत लौट कर मण्डल के सभी सदस्यों ने २९८ पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रकाशित करने में सहयोग दिया। इस रिपोर्ट में सदस्यों के अपने अनुभवों के साथ साथ भारत में उद्योग धंधों को तेजी से विकसित करने के बहुमूल्य और व्यावहारिक सुझाव भी दिये गये थे।

## भावी भारत के लिए कुछ उपयोगी बातें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अब तक इस पुस्तक में मैंने व्यक्तिगत कार्य और अनुभवों का ही महिम्न विवरण दिया है। मैं यह पढ़ते बना चुका हूँ कि किस प्रकार, ६६ वर्ष पूर्व, बम्बई में मरकरी नौकरी पाकर मैंने अपनी जीवन-वृत्ति आरम्भ की थी। इस काफी लम्बे अर्थ में मुझे कई बार राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के अनन्तर मिले और देनी तथा विदेशी राजनीतिज्ञों, विचारकों और लेखकों के साथ भारत की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने का मौका भी मिला।

इस अवधि में ग्रामीण जनता के हितों की ओर ध्यान देने के भी पर्याप्त अवसर मिले बिनापूर उन दिनों। जब कि बम्बई प्रेजीडेंसी में मैं गिचाई सम्बन्धी कामों पर लगा हुआ था और मसूर में प्रशासन सम्बन्धी कार्य को सम्भालते हुए था। इसके अतिरिक्त बहुत भी देशी रियासतों तथा भारत के अन्य भागों में मुझे गिचाई, जल-वितरण, जल-निकास, प्रशासन तथा अन्य राष्ट्रीय व प्रादेशिक समस्याओं के बारे में सुझाव देने के लिए जाना पड़ा।

आर्थिक प्रश्नों की ओर मैंने विशेषरूप से ध्यान दिया। मेरे द्वारा प्रकाशित की गयी दो अलग-अलग पुस्तकों में इनकी चर्चा की गयी है। मैं चाहता हूँ कि पुस्तक के इस अध्याय और अगले दो अध्यायों में मैं उन 'व्यावहारिक समस्याओं' पर कुछ विचार प्रकट करूँ जिनका सामना भविष्य में हमारे देश को करना पड़ेगा।

अब भारत पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ कर स्वतन्त्र हो चुका है। इसकी, वर्तमान स्वतन्त्र स्थिति में जहाँ विकास और प्रगति के कई रास्ते खुल गये हैं, वहाँ इसके लिए कुछ नये माहौल भी पैदा हो गये हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ गयी हैं।

यदि गावधानी बरती जाय तो संकट कम हो सकते हैं और जिम्मेदारियों को भी निभाया जा सकता है। परन्तु परमाणु वम और हाईड्रोजन वम जैसे कुछ संकट ऐसे हैं जो अभी-अभी पैदा हुए हैं और जिनसे सारे विश्व को खतरा है। यह संकट तो ऐसे हैं कि जिनसे पूरी तरह से बचाव भी नहीं किया जा सकता।

### जन संख्या का तेजी से बढ़ना

भारत की जन-संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जबकि उस अनुपात से न तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है और न सन्तोषजनक ढंग से रहन-सहन के लिए आय में बढ़ोतरी हो रही है। न्यूयार्क से प्राप्त हाल ही के एक संवाद से पता चला है कि १९४३ में संसार की जन-संख्या २३,१६० लाख के करीब थी। इससे यह पता चलता है कि यह संख्या सन् १९०० की जनसंख्या से ७,००० लाख अधिक है। चीन और जापान की तरह भारत में भी जन्म तथा मृत्यु दर बहुत बड़े-बड़े हैं। विभाजन से पूर्व भारत की जनसंख्या जो १९३१ में ३५३० लाख थी, १९४५ में ४०३० लाख हो गई। विभाजन के बाद भारत की जनसंख्या ३३७० लाख थी और हाल के अनुमानों से पता चला है कि यह ३२.५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ती जा रही है।

सन् १९४३, में जब कलकत्ता की सड़कों पर भुखमरी से मरने वालों के चित्र अखबारों में प्रकाशित हुए, तो उन्हें देख-देख कर भारत की जनता को बड़ा भारी धक्का लगा। इससे पता चलता है कि देश की जनसंख्या देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री से अधिक हो गयी है। अतः इस महासंकट से बचने के तीन-चार उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर इस संकट को ५०-७५ वर्ष तक टाला जा सकता है।

यह उपाय या तो अधिक अन्न उपजाने के रूप में हो सकते हैं या परिवार नियोजन के रूप में, जैसा कि आवादी रोकने के लिए बहुत-से सभ्य देशों में होता है। अन्यथा यह देश अकाल के भय से मुक्त नहीं हो सकता।

“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन—अब सरकार अधिक अन्न

उपग्रहों आन्दोलन चला रही है और लोगों से यह कह रही है कि देश में अन्न की अधिक से अधिक फ़र्मों उगाये जाएँ।

पिछले पांच वर्षों में सरकार ने २०९० लाख टन अन्न प्रतिवर्ष के हिमाव से विदेशों से मगाया है। सबसे अधिक अन्न, अर्थात् ४० लाख टन, १९४८-४९ में आया था। अभी हाल ही में सरकार ने यह निर्णय किया है कि अन्न का आयात धीरे-धीरे कम करके, १९५२ के बाद, वित्कुल बन्द कर दिया जायगा। सरकार को इन बातों का विश्वास है कि यदि कोई अनहोनी घटना न हो गयी तो, उनकी योजनाओं के अनुसार देश, उस समय तक अन्न में स्वावलम्बी हो जायगा।

अधिक अन्न उपग्रहों आन्दोलन का ठीक ढंग से लायू करने के लिए प्रत्येक गाँव में निम्नलिखित आंकड़े रखने जरूरी है

(क) अन्न की बेती वाली भूमि का क्षेत्र।

(ग) उत्पादन का अनुमान और पिछली फ़सल की कीमत।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में जमा अनाज का अनुमान।

अगर यह आंकड़े इकट्ठे कर लिये जायें और उनके अभिलेखों को ठीक ढंग में रखा जाय तो ग्रामीण जनता के लिए आंकड़ों को ध्यान में रख कर बहुत कुछ समस्याएँ सरल हो जायगा।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्षा के बारे में कुछ भी निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। यहाँ प्रायः हर साल ही ऐसा होता है कि देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ जाता है और किसी-किसी साल तो इसकी लपेट में आया इलाक़ा विलुप्त हो सकता है और दूर-दूर तक बिनाम फल सबता है, जैसा कि सन् १९४३ में बंगाल में हुआ। अतः यह जरूरी है कि देश में अधिक से अधिक जलाशय बना कर उनमें सिंचाई के लिए पानी जमा करके रखा जाय। भारत सरकार ने पहले दंग दिशा में कुछ बंदम उठाया भी है।

ग्राम औद्योगिकरण योजना को अपनाने के लिए यह जरूरी है कि या तो ग्राम मरिचिया बनाकर उनके दलालों के अधिन अन्न उपग्रहों का काम उन्हें सीप दिया जाय, या औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनों को इस ढंग से नियंत्रित किया जाय कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए अनिश्चित अन्न दूधरी जगहों में गरीब

## दो वर्षों के लिए खाद्य सामग्री

औद्योगीकरण योजना में यह तजवीज भी है कि प्रत्येक ग्राम समिति को अपने क्षेत्र में दो वर्षों के लिए अन्न का भण्डार जमा रखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाय। इसका यह मतलब नहीं कि हर एक परिवार अलग अलग रूप से दो वर्षों के लिए खाद्य सामग्री जमा करे, बल्कि यह कि उस ग्राम क्षेत्र में एकत्रित अन्न वहां की सारी आबादी के लिए दो वर्षों तक काफ़ी हो।

लगभग पचास वर्ष पूर्व हमारे देश में गावों के समृद्ध लोग इस बात की सावधानी वरतते थे और आमतौर पर साधारण अकाल के दिनों में दूसरे लोगों का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी ले लेते थे।

जनसंख्या पर रोक—जनसंख्या इस तेज़ी से बढ़ रही है कि यदि इसे रोकने के उपाय न किये गये तो संभव है कि भविष्य में अकालों की गिनती भी बढ़ जाये। अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि अधिक बच्चे होने से लोगों के पास स्वस्थ परिवार पालने का मौक़ा नहीं रहता तथा आराम देह और स्थिर जीवन नहीं बिता सकते।

प्रगति के इस युग में छोटे परिवार वाले व्यक्ति अधिक सुख-सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवनस्तर ऊंचा उठा सकते हैं। जिन देशों के लोग अपने परिवारों का ठीक ढंग से नियोजन करते हैं, वे भूख और ग़रीबी से बचे रहते हैं।

परिवार नियोजन मण्डल—यह मण्डल अमरीका में पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है। इसका काम जन्म निरोध द्वारा आबादी को सीमित रखने के बारे में प्रचार करना है। इस देश में भी पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े-बड़े महिला सम्मेलन हुए, जिनमें जन्म निरोध पर बल दिया गया। यदि भारत में जन्म निरोध को न अपनाया गया तो हो सकता है कि भविष्य में लोगों को अन्न के अभाव का सामना करना पड़े।

नरकार परिवार नियोजन के मिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वह जन्म-निरोध की समस्याओं को मुद्दामाने और उनके प्रचार के लिए निकलना विभाग की एक जाना गोल मक्नी है।

## देश की सुरक्षा

यदि देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, तो दूसरे देशों द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ा बना रहेगा। अतः इस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। सुरक्षा के तीनों अंगों—बलसेना, जलसेना और वायुसेना को हर प्रकार के आधुनिक साज-सामान में लैस रखना चाहिए। सेना के प्रशिक्षण की सारी सुविधाएँ अपने ही देश के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों और सब प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है। आजकल देश की सुरक्षा में मशीनों का बड़ा भारी महत्व है। भारत को डट कर मुकाबला करना चाहिए ताकि स्पष्ट हो जाय कि कोई भी देश हमारी स्वतंत्रता पर हाथ बढ़ायेगा, उससे हम लड़ने को तैयार हैं। देश की जनता आपस में भले ही अहिंसात्मक ढंग से रहे, परन्तु बाहर के किसी भी हमले का सामना करने के लिए उसे सदा तैयार रहना चाहिए। संसार की इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ के सामने निहुरे होना, उन्हें आक्रमण के लिए बुलावा देना है।

**सैनिक प्रशिक्षण**—किसी भी आकस्मिक विपत्ति का सामना एक देश जिस प्रकार कर सकता है, इसका उदाहरण दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व जापान द्वारा अपनायी गयी नीति से मिलता है। प्रत्येक गाँव की आबादी में से कुछ लोग (दो से पाँच प्रतिशत तक) ऐसे होते थे, जिन्हें युद्ध में लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और कभी लड़ाई छिड़ जाने पर ये लोग मोर्चों पर जाने के लिए सदा तैयार रहते थे।

आज के इस मशीनी युग में सेना की शक्ति उसके अफसरों के दिमाग में रहती है। शिक्षित वर्ग में से अधिक-से-अधिक अफसर भर्ती किये जाने चाहिए। सेना के तीनों अंगों के लिए देश के हर हिस्से और हर समुदाय में से नौजवानों का चुनाव होना चाहिए। जल, बल और वायुसेना के अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए अभी दो-तीन कालेज और स्कूल चाहिए। विश्वविद्यालयों में सैन्य विज्ञान को उचित प्रमुखता दी जानी चाहिए।

**अस्त्र और अस्त्र निर्माण** की मशीनों का उत्पादन—सैनिक प्रशिक्षण के बाद यदि किसी बात का महत्व है, तो वह है अस्त्र-सम्पन्न बनानेवाली मशीनों का निर्माण। परन्तु यह तब तक नहीं सम्भव नहीं, जब



तक आवश्यक उद्योग और अनुसंधान कार्य को साथ-साथ नहीं चलाया जाता।

सैन्य शक्ति का मुख्य स्रोत संगठित और विकसित उद्योग है, जिसके साथ-साथ कच्चे माल के साधनों की उचित जानकारी का होना भी जरूरी है। सेना के पास आधुनिक किस्म के युद्धपोत, यूबोट, ट्रक, हवाई जहाज और दूसरे हथियार होने चाहिए, जिससे कि वह अपने देश की भलीभांति रक्षा कर सके। देश की सुरक्षा स्थिति, सुरक्षा समस्याओं तथा अस्त्र निर्माण की मशीनों की ओर ध्यान देने की बड़ी भारी जरूरत है।

जनता में जो लोग सुरक्षा सम्बन्धों, बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। आशा है कि भविष्य में लोगों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कराने की व्यवस्था की जायगी, ताकि वे इन मामलों में रुचि ले कर आपत्काल में सेना को सहयोग प्रदान कर सके। देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है। आशा की जाती है कि यह जिम्मेदारी केवल उच्चकोटि के देशभक्त और निष्ठावान् व्यक्तियों को ही सौंपी जायगी।

अमरीका ने पिछली लड़ाई में जो हथियार इस्तेमाल किये थे, उन्हें काफी समय तक वाशिंगटन में प्रदर्शित किया गया था, ताकि लोग उनसे परिचित हो जायें। लेखक ने इस प्रकार प्रदर्शित किये गये बहुत से हथियार वहां १९४६ में देखे थे। इसके अतिरिक्त जनता को जलसेना, थलसेना तथा वायुसेना की शक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करायी जाती थी।

### अणुबम और हाईड्रोजन बम

अणुबम लोगों के लिए एक और खतरे का कारण बन गया है। अमरीका और हम दोनों देश इन बमों बनाने में सफल हो गये हैं। विश्व के कई दूसरे मध्य देश भी गुप्त रूप में इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे विश्वयुद्ध में अमरीका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहरों पर इस बम का प्रयोग किये जाने का जो घातक परिणाम हुआ, उससे पता चलता है कि यह बम मानवता के लिए कितना विनाशकारी है। जब तक अमरीका और

दोनों मित्र-रश्मि वन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी नहीं हो जाते, तब तर, इन बारे में निम्नलिखित रूप में कुछ कहना कठिन होगा। यदि यह दोनों देश ऐसा करने के लिए तैयार हो जाय, तो छोटे-छोटे राष्ट्र भी इनका अनुकरण करेंगे। यदि इस प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा तो यह अल्प हमें के लिए सम्पत्ति और मानवता के लिए एक महान् मन्दिर बन रहेगा।

### नए आर्थिक जीवन दर्शन द्वारा ग्रही की गयी कठिनाइयाँ

समाजवाद : चिन्ता का एक और कारण है, समाज में कुछ वर्गों के बीच विचारों का परस्पर विरोध। यह बात आर्थिक जीवनदर्शन की एक नयी धारा के उत्पन्न होने के कारण पैदा हो गयी है। इस दर्शन के प्रचारक इस बात पर जोर देते हैं कि आय की सममानता—जिन के कारण कई लोगों को तो संगार भर के ऐश्वर्य प्राप्त हैं और कई जीवन की आवश्यकताओं से भी वंचित हैं—समाप्त हो जानी चाहिए। कुछ लोगों के पास सम्पत्ति है और दूसरे लोग अपने निर्वाह के लिए उन पर निर्भर हैं। इससे समाज में असन्तोष की भावना पैदा होगी है।

वर्तमान समय के उत्पादन के मूल साधनों को सम्पत्तिवानों ने अपने हाथ में ले रखा है। यह कहा जाता है कि श्रम का शोषण किया जाता है और उस धन के उत्पादन में हाथ बँटाने के बदले में जो पुरस्कार मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता।

जिनके पास सम्पत्ति है, वे श्रमिकों को रोजगार देने में ममर्त हैं और वे किसी भी उद्यम में लाभ में अपने लिए अनुपात से अधिक हिस्सा रक लेते हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बहुत-सी असमानताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। पूँजीमूलक उत्पादन के प्रति एक शिकायत यह भी की जाती है कि बहुत से उद्योगों में प्रतियोगिता के स्थान पर पूँजीपतियों का एकाधिकार छा जाता है।

समाजवाद यह चाहता है कि वेतन के अतिरिक्त और सब प्रकार की व्यक्तिगत आय को धर्म्य कर दिया जाय। यह इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का अधिकार केवल उस आमदनी पर ही होना चाहिए, जिसका वह स्वयं उपार्जन करे। सम्पत्ति, विरासत में मिली जमीन, व्याज और मुनाफा जैसे अन्य साधनों से आय स्वतन्त्र हो जानी चाहिए।

समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए और उन्हें सहकारी ढंग से चलाना चाहिए। एक और बात जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि समाजवाद निजी लाभ को उपभोगिता माल तक ही सीमित कर देगा।

समाजवाद कई प्रकार का है और विभिन्न स्वरूपों में पाया जाता है। ऐसी किसी एक विचारधारा को आजकल समाजवादी संगार के कई भागों में, उद्योग धन्वों, व्यापार अथवा प्रशासन का नियन्त्रण कर रहे हैं।

**साम्यवाद :** कुछ लोगों के लिए ऐश्वर्य और बहुतां के लिए गरीबी जीवन की एक वास्तविकता है। इससे 'जिनके पास है' और 'जिनके पास नहीं है' के दो भिन्न-भिन्न वर्गों की भावना उत्पन्न हो जाती है और समाजवाद साम्यवाद के नाना रूपों में दिखलायी पड़ने लगता है। पूँजीपति या सम्पत्तिवान वर्ग सीमित है और श्रमिक वर्ग बहुसंख्यक। श्रमिक वर्ग ने एक जुट होना सीख लिया है और अपने मालिकों की परवाह न करके उन्हें सुविधा देने पर मजबूर करता है।

चूँकि प्रत्येक प्रजातन्त्र में वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, इसलिए यह कहा जाता है कि अमरीका जैसे देश में भी श्रमिक वर्ग के मत प्राप्त करने के लिए उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं।

पूँजीवाद से साम्यवाद की दिशा में संतरण की चार अवस्थाएं बतायी जाती हैं—पूँजीवाद, श्रमिक वर्ग की तानाशाही, समाजवाद और साम्यवाद।

सोवियत रूस में सार्वलौकिक जनवादी इस विचारधारा की अत्यन्त वाम-पन्थी नीतियों को दृढ़तापूर्वक अपना रहे हैं और मास्को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का केन्द्र बन गया है। ऐसा लगता है कि रूस संसार के कई भागों में लोगों को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक रूप से प्रेरणा दे रहा है।

१९३६ के सोवियत विधान ने उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था की।

कहा जाता है कि रूस के आर्थिक प्रजातन्त्र का आदर्श यह है कि व्यक्ति को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुपात से पुरस्कार दिया जाय। लेकिन इस प्रकार की कोई जानकारी जनता को उपलब्ध नहीं, जिससे यह विश्वास हो कि इस बात में ईमानदारी बरती जाती है।

और समाजवाद और साम्यवाद का जो वर्णन दिया गया है, वह उन विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर है, जो हमें उपलब्ध है। इसमें से कोई भी नीति किसी स्थायी स्वरूप में बहुत समय तक व्यवहार में नहीं आयी है। परन्तु रूस में जो साम्यवाद है वह तो है ही।

यूरोप और अमरीका में लोग बहुत बड़ी संख्या में साम्यवाद का विरोध करते हैं। आज संसार इन दो परस्पर विरोधी आर्थिक और राजनीतिक जीवन दर्शनों के बीच भटक-मा रहा है।

कुछ लोग साम्यवाद को भुक्ति का साधन मानते हैं, दूसरे इसे महानाश समझते हैं।

बहुत से लोग आधुनिक जीवन की बुराइयों को दूर कर पाने में अग्रगण्य हैं। लोगों की चिन्ता ही साम्यवाद को जन्म देती है।

इस अध्याय में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे पता चलेगा कि केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि सारी मानव जाति ही पिछले ५० वर्षों में ऐसे नये खतरों और आपदाओं में आ फपी है जिनके लिए वह तैयार नहीं थी। विज्ञान की पूर्वाधार प्रगति और आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन दर्शनों के परिवर्तनों के बीच उन कठिनाइयों के लिए जो आज उठ खड़ी हुई हैं किसी स्थायी हल की भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है।

आज केवल एक ही क्रियात्मक पग उठाया जा सकता है और वह यह कि अनुसंधान जारी रखा जाय और गतिविधियाँ पर नज़र रखी जाय। इस प्रकार की सावधानी बरतने के लिए दो जानकार समितियाँ होनी चाहिए—एक वैज्ञानिक पक्षियों के लिए और दूसरी आर्थिक व अन्य धाराओं के लिए। इनका काम यह होगा कि ये उन खतरों से बचने के लिए, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, क्या संभव कुछ उपाय खोजने में लगी रहे।

## राष्ट्रीय चरित्र

यदि आप एक अच्छे राष्ट्र की नींव रखना चाहते हैं तो उसके नागरिकों को बनाइए। एक सफल राष्ट्र वह होता है जिसके नागरिकों की बहुसंख्या कुशल, चरित्रवान् और अपने कर्तव्य को समझने वाली हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापार की नींव साख होती है। यह साख विश्वास पर निर्भर है और विश्वास चरित्र के सहारे खड़ा होता है।

एक कुशल राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, देश के योग्य सलाहकारों के सुझावों के अनुसार, आधारभूत राष्ट्रीय आदर्शों, ज़िम्मेदारियों और विशिष्ट नीतियों की एक योजना और कार्यक्रम बनाया जाय।

इस समय हमारे देश के अधिकांश लोग न तो प्रशिक्षित हैं और न उन्हें अनुशासन की कुछ परवाह है। केवल बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो वांछित स्तर पर पूरे उतरते हैं। लोगों की बहुसंख्या तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती और-रूढ़ियों का शिकार बनी हुई हैं।

विदेशी राष्ट्रों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे भारतीयों को परामर्श दें कि वह अपना विकास एक कुशल राष्ट्र के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं। यह उत्तरदायित्व सरकार तथा देश के नेताओं का है कि वे लोगों का चरित्र निर्माण करें और उन्हें अच्छी आदतें डालें।

राष्ट्रीय चरित्र के विकास की नीति सरकार की दीर्घकालीन नीतियों में होनी चाहिए। जो भारतीय यह समझते हैं कि भारत का संसार के अन्य राष्ट्रों में अपनी कुशलता और उच्च राष्ट्रीय चरित्र के लिए नाम हो, उन्हें चाहिए कि वे इस नीति को पूरा प्रोत्साहन दें।

अन्ततः चरित्र और कुशलता से उच्च कार्यक्षमता, सुखमय जीवन और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दृष्टि से पश्चिम के विकसित देशों की, जैसे अमरीका की, जनता ने जो प्रतिमान हासिल किए हैं, उनमें और वर्तमान भारतीय प्रतिमानों में बहुत अन्तर है।

## शिक्षा और नियोजित जीवन

यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि औसत हिन्दुस्तानी को उपाजन क्षमता कम होने का कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता अनपढ़ है। निम्नशिक्षा के अलावा, लोगों की गरीबी और फुटड्रपन का जो एक और कारण है वह कि लोग एक ही घंटे पर टिक कर काम नहीं करते।

औसत भारतीय मुख्यतः इन्हीं कमियों के कारण परम्पराओं पर आधारित अनियमित जीवन बिताता है। प्रगतिशील जीवन ध्येयित करने के लिए उसे किसी का मार्ग दर्शन नहीं मिलता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अनिश्चित होते हुए भी अपने सीमित क्षेत्र में बड़ी समझदारी का मकूल देते हैं। लेकिन आम तौर पर शिक्षा की कमी के कारण वे ऊँचे जीवन स्तर से वंचित रह जाते हैं।

कुछ लोग अनिश्चित होते हुए भी अपनी प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के कारण अपना प्रभाव जमा लेते हैं और समृद्ध बन जाते हैं। परन्तु उच्च शिक्षा, अनुशासन में बड़ी आदतें और योजनाबद्ध जीवन—ये सब ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति के चरित्र और रहन-सहन के स्तर को काफी ऊँचा उठाते हैं।

अमरीका जैसे देश के लोग क्यों अधिक समृद्धिवाली, प्रगतिशील और धीरार्थी हैं—इनका कारण यही है कि उन्हें समार में सर्वांशम प्रकार की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हैं और वे समार की सभी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं। उनका जीवन योजनाबद्ध और अनुशासित होता है।

औसत अमरीकी शिक्षा, व्यावहारिक कुशलता, भाविक उपकरणों और विश्वज्ञान की दृष्टि से कहीं अधिक सम्पन्न है। अमरीका के लोग अधिक कुशल संगठनकर्ता और उद्यमकर्ता होते हैं और भारत के लोगों से अधिक परिश्रमी हैं। उनके नेता योग्य तथा क्षमता सम्पन्न होते हैं। उन्होंने अपने घंघोरे कई पीढ़ियों के अनुभवों का निचोड़ इकट्ठा किया होता है, जो उनका मार्ग दर्शन करता है।

दूसरी ओर भारत की अधिकांश जनता अनिश्चित है और बहुत से लोग, जो अब तक पुराने ढर्रे का जीवन बिता कर ही मनुष्य के, जिनमें आकांक्षाएँ और आगे बढ़ने की इच्छा न थी, अब आवादी बट जाने के कारण, अपना निर्वाह भी नहीं कर पा रहे।

शिक्षा के अभाव ने लोगों को आलसी बना दिया है और उनकी आकांक्षाएं मर गयी हैं। संगठन क्षमता और सृजनात्मक शक्ति या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। मुख्यतः शिक्षा की कमी के कारण औसत भारतीय की उपार्जन शक्ति एक अमरीकी की उपार्जन शक्ति के दसवें भाग से भी कम है।

अतः भारत में प्रगति के लिए जिस एक बात की बहुत अधिक जरूरत है वह है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अपने देश में सुधार करने के लिए रूस ने सबसे पहले इसे ही लागू किया था। आशा है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बहुत बड़ी कमी की ओर अधिक समय तक लापरवाही नहीं दिखायेगी।

सन् १९४६ में शिक्षा विभाग, न्यूयार्क के अधिकारियों ने लेखक को बताया था कि यदि स्कूल जानेवाली आयु का कोई बच्चा किसी स्कूल में नहीं जाता तो उसके माता-पिता को गिरफ्तार किया जा सकता है। परन्तु भारत में नियम और आदेश मनवाने के लिए इस प्रकार की सक्ती नहीं बरती जाती।

### जीवन के कुछ बुनियादी विचार और विश्व-घटनाओं का ज्ञान

इस सम्बन्ध में कुछ बुनियादी विचार निर्धारित किये जा सकते हैं, जो सुधारों की पृष्ठभूमि का काम करेंगे। जैसा कि उपलब्ध परिणामों से पता चलता है, औसत भारतवासी की कार्य शक्ति बहुत कम है, क्योंकि जन संख्या गुजारे के साधनों की अपेक्षा अधिक तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हालांकि भारत एक कृषिप्रधान देश है, फिर भी यहां इतना अन्न पैदा नहीं होता जो देश की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यहां के लोग अभी दूसरे काम-धंधों से भी इतना उपार्जन नहीं कर रहे जिससे कि बाहर से मंगवाये अन्न की कीमत चुका सकें।

पश्चिमी देशों का आम नारा है जिसकी महत्ता भारतीय नागरिक कुछ कम ही समझ पाये हैं; वह नारा है :—यदि काम नहीं करोगे

तो खाओगे भी नहीं।”

अपने काम से ही तो व्यक्ति अपने निर्वाह के लिए कमा पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम करना चाहिए जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का भलीभांति निर्वाह कर सके और दूसरों के ऊपर बोझ न बने। उसे इसके अलावा

के काम आना चाहिए। अधिक कुशलता या आक्रोश में किये गये कार्य में साधारणतः अधिक फल की प्राप्ति है।

कार्य कुशल बनने के लिए अंगन भारतीयों के लिए यह जरूरी है कि वह पहले में अधिक परिश्रम करे और अपनी आदतों को अनुशासन के माचे में ढाले तथा जहां तक सम्भव हो, सभार की सामान्य घटनाओं की जानकारी प्राप्त करे। प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अधिक योग्य तथा क्षमतावान् व्यक्तियों को अपने काम में अधिक कार्यकुशलता लानी चाहिए। जितने भी महान् व्यक्ति अब तक सभार में हुए हैं, वे सब निरन्तर परिश्रम के कारण ही महान् बन सके।

भारत में हम लोगों को इस स्तर तक पहुँचने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। हम लोग घुघले आदतों की छाया में पलते हैं और हमें जॉस्तिम खेलने की शिक्षा भी नहीं दी जाती। पश्चिम के उद्योगपतियों को इन बातों की सीख मिली होती है। उनका जन्म ही उच्च जाति में होता है जो संघर्ष और उद्यम की आदी है।

अमरीका आज सबसे घनायुष्य राष्ट्र है और अमरीकावासियों का जीवन-स्तर संसार में सबसे ऊँचा है। लेकिन फिर भी जब कभी उद्यम का अवसर आता है, वे हर एक बात के लिए तैयार रहते हैं और अपना जीवन तक धलिदान करने से पीछे नहीं हटते।

यह भारत में हमारा जीवन दर्शन ही कुछ और है। इसमें न गति है और न महत्वाकांक्षा।

अमरीकी केवल व्यापारी जीवन की सुरक्षा से ही सन्तुष्ट नहीं होते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बोस्टन के एक प्रोफेसर श्री गम्बर स्लिघर ने कुछ वर्ष पूर्व एक सार्वजनिक सभा में अपने विचार प्रकट करने हुए कहा था:

“मनुष्य के आदतों में सुरक्षा का स्थान निस्तब्ध रहने के बराबर है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र केवल सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहने पर ही महान् नहीं बन सकता। मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट है, उसे उभारने के लिए रोस और मजिनीन आदतों की आवश्यकता है। जो भी राष्ट्र महान् बनने के इच्छुक है, उन्हें सुरक्षा में अधिक महत्व उद्यम को देना होगा। कुछ लोगों के पलायन हुए उद्यम अनिश्चित लोगों को रोझार देने है। इसलिए देश के अधिकारों, प्रयोगकर्ताओं और उद्यमकर्ताओं को



विशिष्ट स्थान प्राप्त होना चाहिए, और उनके लिए हर तरह से अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।”

“देश को इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि उसमें ऐसे उद्यमकर्ताओं की गिनती बढ़े, जो दूसरों के पास नौकरी न करके अपने यहां दूसरों को नौकरी देते हैं।”

आधुनिक राष्ट्रों ने बहुत-सी अच्छी बातों को ग्रहण किया है : जैसे—परिश्रम, एकता, दूरदर्शिता, महत्वाकांक्षा। इसके अतिरिक्त उन्होंने काम को सुचारु रूप से करना भी सीख लिया है।

काम को सव-गपूर्ण ढंग से करने के प्रयत्न का एक उदाहरण ‘न्यूयार्क वर्ल्ड’ के विख्यात पत्रकार श्री जोसेफ पुलिट्जर के जीवन से मिलता है। इस सम्बन्ध में पियर्सन्स पत्रिका के मार्च, १९०९ के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है :

“समाचार पत्रों में काम करते समय श्री पुलिट्जर अपनी मानसिक तथा नैतिक शक्तियों को तुरन्त काम में जुटा देते थे और किसी तथ्य को विचार को पूर्णरूप से प्रभावशाली बनाने के लिए घंटों प्रयत्न करते थे। अनुशासन का परिणाम ऐसा ही होता है।”

आज के इस कोलाहलपूर्ण जीवन में यदि कोई समुदाय सफल व्यवसायी बनना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी आदतें और अच्छा बर्तन बहुत जरूरी है। एक औसत नागरिक अनुभव द्वारा यह देखगा कि योजनाबद्ध कार्य तथा अनुशासन बद्ध आदतों से मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा दीर्घायु बनता है।

काम के नियमित घंटे, काम करने के लिए ठीक समय पर पहुंचना, अच्छी व्यावसायिक आदतें और समय की कद्र ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, जो व्यक्ति को समृद्ध, चिन्तारहित और स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता देती हैं।

लोगों की प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और क्षमता में अन्तर हो सकता है, परन्तु उन्हें दूरदर्शिता, परिश्रम और संकल्प शक्ति द्वारा विकसित किया जा सकता है।

किसी भी व्यापार या व्यवसाय में व्यक्ति विशेष की सफलता बहुत हद तक उसकी क्षमता, व्यक्तित्व, निष्ठा और दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। जीवन में मनुष्य की सफलता उनकी अपनी भाग दोड़ पर ही निर्भर है। जीवन में जो विधनियां आती हैं उनमें से शायद नये संयोग मात्र नहीं होती, (मॉनिस्ट नामक पत्रिका

के एक पुराने अंक से उद्धृत) बल्कि उनका कारण यह होता है कि लोग आराम का जीवन बिताना चाहते हैं और कठिनाइयों से दूर भागते हैं। जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों से कतराने और आराम को पाने का मिश्रान्त बना रखा है, वह एक न एक दिन ज़रूर मुगीबन में फरेगा। सुख-दुःख के साथ समान रूप से निवाह करना ही जीवन में स्थायी सफलता का आधार है। नैतिक कार्यों पर निष्ठा को छाप होती है और यही किसी महान् व्यक्ति की महानता की सबसे बड़ी द्योतक है।

## आचार नियम

आचार नियमन करने के लिए जो भी नियम बनाये जायें, इन्हें गतिमान रूप में होने चाहिए कि भारतीय नागरिक उन्हें आगामी में याद रख सकें। इन नियमों की स्मरणता को मैंने चार भागों में बांटने का प्रयत्न किया है।

१. कठोर काम : औसत भारतीय हर एक काम को संकीर्ण रूप में नहीं करता। साधारणतः वह बहुत थोड़ा काम करता है। इसका मतलब यह है कि देश में कार्य-कुशलता का स्तर तथा आर्थिक स्थिति बहुत हीन है।

पश्चिमी देशों में लोग कड़ी मेहनत करते हैं, काम ठीक-ठग में होता है और इसलिए उनकी उत्पादन शक्ति अच्छी है और जीवन-स्तर भी ऊँचा है।

२. नियोजित तथा अनुशासित कार्य : यदि काम को अनुशासित ढंग में लिया जाए और दिन में काम के घंटे निर्दिष्ट कर दिए जाएं तो हमारे काम के मूल्य में बड़ी वृद्धि होगी।

अनुशासित ढंग से किये जाने वाले कठोर काम के फलस्वरूप कामगार स्वस्थ रहता है और दीर्घायु होता है।

आराम करने में हर परिस्थिति में स्वास्थ को प्राथमिकता देना है, इस आम धारणा को अलग दायित्व देना चाहिए। बहुत से लोग आराम के लिए अपने काम में परिश्रान्त बंधे होते हैं, उनके लिए आराम इलाज नहीं, बल्कि काम इलाज है।

३. कार्यकुशलता : कार्यकुशलता का अर्थ है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, मनुष्य अपने काम को परिधम, सहृदयता, अनुशासन तथा निष्ठा के साथ करे। साधारणतः काम करने का स्तर जितना ऊँचा होगा, उतना ही अधिक उम्र का पुनर्वास भी मिलेगा।

४. विनय और सेवा : पश्चिमी देशों में दूसरों के साथ मिल कर काम करने की भावना को बहुत सराहा जाता है। भारत में इस मित्रतापूर्ण भावना का अभी तक अभाव है।

साथ में काम करनेवालों या पड़ोसियों के प्रति प्रत्येक नागरिक का वर्तनि सद्भावना और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।

जो भी नागरिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है और समाज का एक योग्य सदस्य बनना चाहता है, उसे चारों सूत्र सदा ध्यान में रखने चाहिए।

ये सब लाभदायक गुण बिना प्रशिक्षण के प्राप्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार का प्रशिक्षण शिक्षा संस्थानों में दिया जाना चाहिए और वयस्क लोगों को, सरकार के निदेशन, में प्रचार द्वारा यह सब कुछ सिखाया जाना चाहिए। जापान में ऐसा ही होता था।

चूँकि अब हमारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार है, इसलिए हमारे मन में नयी इच्छाएं और नई आकाक्षाएं जागृत हो उठी हैं।

ऊपर जिन चार नियमों का उल्लेख किया गया है, उनका लय जनता में मेल-जोल और एकता स्थापित करना तथा उनमें कर्तव्य और दायित्व की भावना को बढ़ाना है।

## राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय कार्यकुशलता

पश्चिम के राष्ट्र हम बात को मानते हैं कि देश की उत्पादन शक्ति, उपभोक्ताओं की मांग, प्रशासनिक कार्यकुशलता, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ, राजनैतिक शक्ति, काम-धंधों तथा सांस्कृतिक योग्यता में मनुज बनाये रखना चाहिए। इसलिए हमें अपने देश में भी इस दिशा में कुछ काम आरम्भ करना चाहिए। पहले हमें काम-धंधों के बारे में मूल सोच-विचार कर एक भावी योजना बनानी चाहिए। यह काम-धंधे जनता के हित के लिए हों और जनता द्वारा ही चलाये जाय। इसके लिये सरकार में भी सहयोग लेना चाहिए। जिससे भावी कार्यवाहियों को सफलता के पथ पर चलाया जा सके।

### राष्ट्रनिर्माण और उसके उद्देश्य

आयोजना का अर्थ है काम करने का वह तरीका जो विशेष प्रकार के विकास, उद्देश्य या प्रयोजन को पाने के लिए आवश्यक समझा जाय। जन प्रशासन में जनता की भलाई के लिए योजना बनाने का विचार अन्तर्निहित है।

किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए आर्थिक आयोजना एक ऐसे योजनायुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, जो अपने साधनों और मनुष्य शक्ति को सर्वोत्तम ढंग से काम में ला कर, जनता की आय, जीवन-स्तर और भौतिक समृद्धि को बढ़ा कर देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमल में लायी जायगी।

कभी न कभी, आर्थिक आयोजना के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के दूसरे क्षेत्रों में सुधार और पुनर्निर्माण के प्रश्न अपने आप आगे आएंगे। ये प्रश्न प्रशासनिक, सुरक्षा, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होंगे। ये एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और इनमें परिवर्तन करना जरूरी होगा। इन सब क्षेत्रों में आयोजना का जो व्यापक रूप होगा, उसे हम राष्ट्रीय योजना या राष्ट्रनिर्माण के नाम से पुकारेंगे। यदि इन सब क्षेत्रों में आर्थिक योजना को सफलता मिलती

ने तो हमारे राष्ट्रनिर्माण के तथा राष्ट्रीय कार्यकुशलता के अन्य प्रयोजन भी सिद्ध हो पायेंगे ।

प्रारम्भ में निम्नलिखित कार्यों के सामान्य उद्देश्य निम्न होने चाहिए:—

१. जनता के लिए उद्योगिक काम और अन्न उकट्टा करना ।
२. गुण और मात्रा की दृष्टि से काम बढ़ाना, उत्पादन में उन्नति करना, गैरमार्ग बढ़ाना तथा आय में वृद्धि कर के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना ।
३. मात्र ही धीरे-धीरे अन्य राष्ट्रनिर्माण के कामों को आगे बढ़ाना और उनके द्वारा ऐसा स्वास्थ्य, सुदृढ़ तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने की कोशिश करना, जो कई दृष्टियों से आत्मनिर्भर तथा आत्मतुष्ट हो ।

किसी राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए नियोजित जीवन सबसे जरूरी चीज है । आर्थिक सुदृढ़ता आ जाने पर इनकी सहायता से राष्ट्रनिर्माण के बहुत से दूसरे काम किये जा सकते हैं ।

भारत में लोगों का व्यक्तिगत या राष्ट्रीय जीवन आयोजित नहीं है । ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इस देश में सरकारी संगठन ने आर्थिक समस्या का कभी सम्पूर्ण रूप से सामना किया हो । यहां राष्ट्रीय प्रगति के प्रति सचेत रहने या उसे बढ़ावा देने की प्रथा ही नहीं रही ।

जनसंख्या में वृद्धि, अन्न प्राप्ति, निरक्षरता निवारण, पूरी मोटर तैयार करना, हवाई जहाज बनाना या ऊँची श्रेणी की मशीनें निर्माण करने जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की ओर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया गया । इस दिशा में जो भी कदम उठाये गये, उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया । इन सब कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त योजनाओं या उपायों को लागू करने में अब देर नहीं की जानी चाहिए ।

## राष्ट्रीय योजना आयोग

सरकार ने अब विकास कार्यों का बढ़ाने और सुधारों तथा पुनर्निर्माण के कार्यों की ओर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग स्थापित कर दिया है ।

आयोग को जो काम तुरन्त अपने हाथ में लेना चाहिए वह है—देश के साधनों की दक्षता से पूरा लाभ उठा कर लोगों को अधिक सोचने और अधिक काम करने

के योग्य बनाना, अन्न की उपज बढ़ाना, देश के माधनों को काम में लाकर आर्थिक शक्ति बढ़ाना तथा लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना।

भविष्य में पुनर्निर्माण की जो भी नई योजना बने, उसके बारे में यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि उसमें कितने परिणाम की आशा है और वह कितने समय के अन्दर पूरी हो जायगी।

## राष्ट्र निर्माण से सम्बन्धित विषयों की गणना

यह वाछनीय है कि योजना आयोग को उन सव कमियाँ और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी हो। जिन्हें राष्ट्रीय योजना या कार्यक्रम में स्थान मिलना जरूरी है। इस प्रकार के कुछ विषयों का मक्षिप्त रूप में नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

१. ऐसे सुधार या विकास कार्य जो अत्यंत जरूरी हैं।

धन की कमी के कारण गुरु-गुरु में केवल उन सुधारों या विकास शायों को ही लागू किया जा सकता है जो बहुत जरूरी हैं।

इस देश के औसत नागरिक को यह बात याद दिलाई जानी चाहिए कि उनकी उपार्जन शक्ति कम और जीवन स्तर नीचा होने का कारण यह है कि वह अपनी हालत में सन्तुष्ट है और अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करता। उसे यह सीख नहीं दी गई कि काम हर प्रकार की समृद्धि का स्रोत है।

देश की यह नीति होनी चाहिए कि वह प्रत्येक नागरिक को अपने समय का सदुपयोग करने और कठोर परिश्रम करने के लिए उभाड़े, ताकि वह अपने तथा अपने परिवार का निर्वाह कर सके। जब भी सम्भव हो और जितना बने पड़े, हर नागरिक को आय का कुछ अंश राष्ट्रीय सम्पत्ति और सुरक्षा के निर्माण के लिए देना चाहिए।

छोटे किमानों, कारीगरों तथा दुकानदारों को लासों की मर्या में प्रारम्भिक उद्योग धर्मों में लगाना मिलजुलकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

रस्ते, मशीनी औजार और मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज और पानी के जहाज बनाने जैसे कुछ उद्योगों को जो ऐसे कारणों से रिहटे हैं जिन्हें जना नहीं जानती, उनका विकास करना चाहिए और उन्हें मनोव-

**बड़े पैमाने पर शिक्षा :** बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रसार का काम, जिसकी ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया, तेजी से आरम्भ होना चाहिए।

जैसा कि सोवियत रूस में किया गया था, देश में अनिवार्य शिक्षा को दृढ़तापूर्वक लागू कर देना चाहिए। हमारे देश में यह काम बड़े वेमन से किया जाता है। इस काम में आर्थिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, परन्तु स्थानीय प्रयत्नों द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। हर क्षेत्र में प्रगति के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रसार परम आवश्यक है। इसके बिना देश उन्नति की चरमसीमा को प्राप्त नहीं हो सकता।

**व्यावसायिक शिक्षा :** लाखों की गिनती में लोगों को काश्तकारी, दस्तकारी और छोटे पैमाने पर दूकानदारी का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रबन्ध करने की ज़रूरत की ओर पहले ही ध्यान दिलाया जा चुका है।

उच्च क्षमता वाले लोगों को प्रशिक्षण के अनुकूल अवसर मिलने चाहिए, जिससे देश में पर्याप्त संख्या में उच्चकोटि के संगठक, तकनीकी विशेषज्ञ और वित्त व्यवस्थापक तैयार हो सकें।

**सांख्यिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण :** भूतकालीन स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना करने के लिए आंकड़े बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और इस से यह भी पता चल सकता है कि भारत की तुलना में अन्य प्रगतिशील देश किस रफ़्तार से और किन साधनों द्वारा उन्नति कर रहे हैं।

**उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का माध्यम :** जापान ने शुरू से ही अपने विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को बनाये रखकर बहुत लाभ उठाया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही जापान को संसार के दो अग्रगामी देशों, अमरीका और इंग्लैण्ड में होनेवाली सभी प्रकार की उन्नति से निकट सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिली।

अंग्रेजी भाषा को अपने यहां चालू रखने में भारत को इस समय जो लाभ है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि विश्व की परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जाय जिससे अंग्रेजी को त्यागना ज़रूरी हो जाय।

उन्नति में बाधक कुछ पारस्परिक असंगतियों और कमियों को दूर करना

जो लोग व्यावसायिक और तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त हैं, उन्हें देश के प्रत्येक क्षेत्र में सेवा कार्य करने के अवसर मिलने चाहिए। ऐसा करते समय दलगत भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

यह सरकार का एक मूल कर्तव्य है कि वह उन लोगों के लिए काम की व्यवस्था करे, जो काम करने के लिए तो तैयार हैं पर उनके पास काम नहीं है। चाहे वो किसी भी दल या जाति के हों।

असम होता यह है कि नौकरियों के मामले में अपने सगे-गम्वन्धियों, अपनी जाति या क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और योग्यता धरी की धरी रह जाती है। यदि वह बातें शीघ्र ही सत्तम न की गयीं तो भारत कभी भी प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता।

यहां पर मैं राष्ट्रीय जीवन और चरित्र (नेशनल लाइफ एण्ड कैरेक्टर) के लेखक चार्ल्स एस० पियर्सन ने इन सामान्य किन्तु अत्यन्त हानिकारक बातों के बारे में जो कुछ लिखा है, उसे उद्धृत करता हूँ।

"उन देशों में जहां योग्यता के आधार पर तरक्की देना प्रायः कोई भी नहीं जानता, वहाँ अतैत्तिक सेवा में नियुक्त छोटे अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना नाममात्र होती है और कर्तव्यपालन में भी उन्हें विशेष बप्ट उठाने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए, जैसा कि सम्भव ही है, यदि सरकार उद्योग पर निरन्तर अपना नियन्त्रण बढ़ा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे रही है तो फिर सेवाओं में होड़ की भावना विलुप्त लुप्त हो जायेगी और हर विभाग में काम का स्तर इतना नीचा हो जायेगा कि चरित्र विकास की शिक्षा ही सत्तम हो जायेगी।"

इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसे देशभक्त नेताओं की एक समिति बनानी चाहिए, जो महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए योग्य और क्षमतावान् व्यक्तियों का चुनाव कर सके।

जो लोग खुद जायें वे सरकार का काम-काज चलायें में उत्तमतर की कार्य-कुशलता नैतिकता, और उत्तरदायित्व का मगुन हैं।

कुछ व्यावसायिक पद्धतियां आज भी भारत में अचूरी हैं और उनमें सुधार



करने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले सर्वोत्तम कालेज और स्कूल अमरीका के बोस्टन नगर में हैं।

सरकारी कर्मचारियों की व्यवहार संहिता में न कोई नियम है, न कोई प्रणाली। इसमें उचित सुधार होना चाहिए। कार्याधिकारियों के लिए सही कार्य व्यवहार के नियम बनाने चाहिए और एक उपयुक्त व्यापार व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। एक भारतीय रियासत के शासन प्रबन्ध में लेखक ने अधिकारियों में अनुशासन कायम रखने के लिए एक नियमावली लागू की थी। लोक सेवा कार्य के कुछ विभागों में इस प्रकार के नियमों का होना बड़ा जरूरी है। राष्ट्रीय चरित्र शीर्षक के १८वें परिच्छेद में औसत नागरिक के कार्य व्यवहार में कुछ नियमित आदतों तथा अनुशासन की ओर ध्यान दिलाया गया है।

प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन का खर्चा घटाने के लिए अधिक मशीनों तथा मशीनी औजारों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना चाहिए।

## ५. धंधे आदि

धंधे : कहा जाता है कि ५५० लाख से भी अधिक अमरीकी प्रतिदिन, प्रतिवर्ष अपना दिमाग हज़ारों तरह के व्यापार, दस्तकारियों, धंधों और व्यवसायों के लिए खपाते हैं। वे अपने समय और अपनी योग्यता को सदा अमरीका को समृद्ध बनाये रखने और अपना पुरस्कार प्राप्त करने में लगाते हैं।

अमरीका और कनाडा, दोनों देशों में लोगों के धंधों को दस वर्गों में बांटा गया है। भारत में भी लगभग यही वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अमरीका में इन दस मुख्य वर्गों को कई अन्य धंधों में बांटा गया है और एक तालिका बना कर यह बताया जाता है कि एक धंधे में कितनी स्त्रियाँ और कितने पुरुष काम करते हैं। इससे रोज़गार ढूँढ़ने वालों को यह पता चल जाता है कि किसी एक इलाक़े में किस प्रकार का काम किया जाता है।

रोज़गार की स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त कराने के लिए आसपास के नगरों में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे काम खोजने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए संतोषजनक धंधा चुन सके।

भारत में भी इसी ढंग से धंधों की ठीक ठीक व्याख्या सूची तैयार की जानी

जहरी है। आशा है कि आगामी जनगणना में यह ज़रूरत पूरी हो जायगी।

**राष्ट्रीय चरित्र :** राष्ट्रीय योजना आयोग को चाहिए कि वह राष्ट्रीय चरित्र पर नज़र रमे और उसे उन्नत करने के लिए कदम उठाये। राष्ट्रीय चरित्र अपने आप ऊँचा नहीं होगा। इसका निर्माण तो अनुशासन और चरित्र सम्बन्धी अन्य गुणों द्वारा ही होगा।

**राष्ट्रीय सुरक्षा :** सत्रहवें अध्याय में हम राष्ट्रीय खतरों के बारे में अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। यह खतरे केवल भारत के सामने ही नहीं, बल्कि समार के दूसरे देशों के सामने भी विद्यमान है। इस दिशा में जो कदम उठाये जा सकते हैं, वह यही हैं कि भारत को भी अनुसंधान कार्य में लगे रहना चाहिए और इन खतरों के स्वरूप में जो परिवर्तन हों, उन पर दृष्टि रखनी चाहिए।

कुछ दूरे छोटे-मोटे खतरे भी हैं, जिनके प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आजकल मोटर मातायात और हवाई जहाज चलाने के लिए पेट्रोल आदि काम में लाया जाता है, जो निरन्तर प्राप्त होता रहना चाहिए। यदि किसी कारण से लड़ाई छिड़ जाये और पेट्रोल आदि मिलना बन्द हो जाये तो मातायात में बाधा पड़ सकती है। इन खतरों के प्रति भी सरकार को सचेत रहना चाहिए।

## पंचवर्षीय योजना

पाँच वर्षों के अन्तर्गत ऊपर दी गयी राष्ट्रीय ममस्याओं को राष्ट्रीय योजना आयोग ठीक ढंग में निपटाने सक्ता है। ऐसा माना जाता है कि इस बिम्बेदारी के काम को पूरा करने के लिए आयोग अपनी महा तार्थ अपने नियन्त्रण में तीन मंडल नियुक्त करेगा। ये मंडल आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवश्यक तथ्य और सामग्री प्राप्त कराने के हेतु छानबीन और अनुसंधान का काम अपने हाथ में लेंगे।

**मंडल १ :** सामान प्रबन्ध जिसमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ममस्याएँ और सुरक्षा शामिल है।

**मंडल २ :** आर्थिक महत्त्व की ममस्याएँ और सज्जोख जिनमें आयोग, इति, व्यापार, परिवहन, शिक्षा आदि शामिल है।

मण्डल ३ : अन्य सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार और विकास।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे राज्य के वित्त और दूसरे साधनों में उन्नति हो।

प्रत्येक मंडल को अपने काम पर नज़र रखनी चाहिए और सभी वांछित सूचना और तथ्य इकट्ठे करके आवश्यकतानुसार योजनाएं या तजवीज़ें तैयार करने के लिए उन्हें, समय समय पर, आयोग के सामने रखना चाहिए। इनमें राष्ट्र की वह तमाम कमियां और आवश्यकताएं भी शामिल होंगी, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

राष्ट्रीय योजना आयोग को पहले एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में आगामी वर्ष के कार्यक्रम की तजवीज़ तैयार की जानी चाहिए।

रूस में इस प्रकार की योजनाओं से क्रान्तिकारी विकास हुए, इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं बहुत लोकप्रिय हो गयी हैं। परन्तु इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं कि योजना किसी और अवधि के लिए, जैसे छः वर्ष के लिए, नहीं बनाई जा सकती। बात सिर्फ़ यह है कि पंचवर्षीय योजना एक परिचित नाम है।

हर साल होनेवाले परिवर्तनों के अनुसार पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन भी किये जा सकते हैं।

यदि योजना आयोग उचित समझे तो एक दस वर्षीय योजना बनायी जा सकती है और उसे लक्ष्य के रूप में सामने रखा जा सकता है।

नयी योजनाओं का चुनाव करते समय योजना आयोग इन बातों का ध्यान रखेगा कि देश के व्यावसायिक कितना व्यय कर सकते हैं या सरकार के पास इस प्रकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए कितने साधन हैं। तीनों मण्डलों की सहायता से योजना आयोग अधिक महत्वपूर्ण सुधारों और विकास कार्यों को वार्षिक तजवीज़ और पंचवर्षीय योजना में शामिल कर सकता है।

इस प्रकार आयोग समयानुकूल महत्वपूर्ण योजनाओं का चुनाव कर के राष्ट्र निर्माण के काम में निरन्तर सहायता करता रहेगा।

योजना आयोग अपनी पूरी शक्ति लगा कर उत्तरोत्तर देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न करेगा। ज्यों ही किसी योजना की मंजूरी दी जाय, त्यों ही उसके काम को उचित गति

से चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उसकी प्रगति में कोई बाधा न उठ सके।

यदि किसी योजना की प्रगति में धन की कमी के कारण बाधा पड़ जाय तो उसे स्थगित नहीं कर देना चाहिए। जनता को प्रचार द्वारा उस योजना का महत्व समझाना चाहिए और धन इकट्ठा होने पर योजना के काम को पुनः चालू कर देना चाहिए।

जिन तीन मण्डलों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, वे अनुसूचित कार्य करने के साथ-साथ योजनाओं की प्रगति पर भी नजर रखेंगे और उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों के बारे में योजना आयोग को सूचित करेंगे।

इस दौरान में देश के साधनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए और वार्षिक तजवीजें बनाते समय हर दिशा में होनेवाले विकास का ध्यान में रखा जाय।

भारत को अमरीका और जापान जैसे देशों के उन अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें से होकर उन देशों को सब मुश्किलें पड़ा था, जब कि समार के आर्थिक मामलों में अभी उनका प्रभाव नहीं जमा था।

भारत सरकार, योजना आयोग तथा तीनों मण्डलों को चाहिए कि वे भारत की सारी कमियाँ और आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

अन्त में मैं इस बात को और विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जनता में अनुशासन और सामान्य कार्यकुशलता सम्बन्धी जो दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए, ताकि देश व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि में उन्नति करके शीघ्र ही गतार के दूसरे उन्नत देशों के स्तर तक पहुँच जाय।

भविष्य में एक महत्वपूर्ण विकास यह करना होगा कि कमियों को दूर करने और राष्ट्रव्यापी सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी का स्थानीयकरण कर दिया जाय, अर्थात् जहाँ तक संभव हो सके, जनसंख्या और साधनों के अनुपात से हर छोटे-छोटे इलाके को भी इस जिम्मेदारी का भागीदार बना दिया जाय। यदि भारते रखने की उचित व्यवस्था की जाय, तो हर विभाग में जहाँ-जहाँ विकास की आवश्यकता है, उसकी मही तस्वीर सामने आ जायगी चाहे किसी प्रांत में, राज्य में अथवा गारे भारत में, तो हमें पथप्रदर्शन किया जा सकता है। पूरे देश की प्रगति की मही तस्वीर मदा हमारे सामने रह सकती है।

इसलिए निश्चित भविष्य में जो नीतियाँ बनें, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए



